HVS/Lib/10 15-11-99

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 जनवरी, 1999

खण्ड - 1, अंक - 2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * LIBRARY * Chandigarh

विषय सूची

शुक्रवार, 29 जनवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	2)19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)38
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(2)52
केन्द्र सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित मामला।	(2)53
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)55
वाक-आउट	(2)83
बैठक का समय बढ़ाना	(2)84
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)84
बैठक का समय बढ़ाना	(2)91
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)91

मूल्य :

113

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 29 जनवरी, 1999

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो0 छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Sadana Minor

***794. Shri Devraj Diwan :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the canal water supplied to Mahara & Bhatana villages through Sonipat distributory Sadana Minor by Dehar Wali Mori No. 3600 and 3661 does not reach upto its tail; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to supply the water upto the tails of Mori No. 3600 and 3661.

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) श्रीमान जी, नहीं बल्कि गांव माहरा तथा भटाना की भूमि को सोनीपत वितरिका की मोरी नं० 3600-एल तथा 3661-एल द्वारा पानी की स्वीकृत क्षमता वितरित की जा रही है।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार और कोई कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, उस रजवाहे में पिछले ढाई साल से पानी की एक भी बूंद नहीं गयी है। मैं कल तक के बारे में भी बता सकता हूं कि वहां पानी की एक भी बूंद नहीं पहुंची है फिर मंत्री जी पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि उस रजवाहें में पानी है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जिस रजवाहे की बात कर रहे हैं पहली बात तो यह है कि सिंचाई विभाग में इस नाम का कोई रजवाहा ही नहीं है। मोरी नं० 3600 तथा 3661 दोनों मोरियाँ सोनीपत डिस्ट्रीब्यूटरी की हैं। इनमें से मोरी नं० 3600 की क्षमता 35.57 क्यूसिक है। स्पीकर सर, दोनों मोरियों की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी वहां हैड पर मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, क्या आपने वहां पर जाकर देखा है कि इस नाम का वहां कोई माईनर है या नहीं ?

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, वहां पर माईनर है मैंने स्वयं वहां पर जाकर देखा है। मुझे माहरा गांव के लोग वहां लेकर गए थे। पता नहीं मंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि वहां पर पानी चल रहा है क्योंकि उस मोरी में पानी जाने से पहले ही खत्म हो जाता है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सडाना माईनर की बात कही है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सडाना माईनर नहीं है बल्कि एक ड्रेन है जो माहरा गांव और सोनीपत डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच से गुजरती है। अध्यक्ष महोदय, ये जिन मोरियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक मोरी की क्षमता 1.75 क्यूसिक और दूसरी मोरी की क्षमता 0.75 क्यूसिक की है। इन दोनों मोरियों में शुरू से लेकर टेल एंड तक पूरा पानी चल रहा है। पिछले तीन साल के रिकार्ड के अनुसार एक मोरी की इरीगेशन 110 परसैंट और दूसरी मोरी की इरीगेशन 51 परसैंट रही है। यह जरूर है कि ये मोरियाँ टूटी पड़ी हैं लेकिन उनकी सफाई और मुरम्मत का काम वहां के उन किसानों का है जो इनके पानी से अपनी जमीन की सिंचाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे महकमे का काम सिर्फ इतना ही है कि हम हैड से लेकर टेल एंड तक पूरा पानी दें और वहां पर हैड से लेकर टेल एंड तक पूरा पानी चल रहा है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं स्पेशली दो महीने पहले इनको देखकर आया हूं लेकिन वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको दोबारा से चैक करवा लें।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इन दोनों मोरियों में टेल तक पानी न पहुंचने की बात कही है इसका मतलब नहर में तो पानी आया है। यह बात तो ये मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक किसान हूं इसलिए मैं और देवराज जी दोनों मिलकर वहां पर चले जाएंगे और दोनों एक साथ उन मोरियों को चैक कर लेंगे और टेल तक पानी पहुंचा देंगे।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मुझे इनकी बात मंजूर है।

Survey conducted for providing of Drinking Water

***798. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether the Bio-science department of Maharshi Dayanand University, Rohtak has conducted any survey for providing Potable water in Chhara, Bhaproda and Assamuda villages of district Jhajjar, if so, the details thereof, togetherwith the action taken thereon ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन नाथ) : जन स्वास्थ्य विभाग के पास महर्षि दयानन्द विश्व विद्यालय, रोहतक के जीव-विज्ञान विभाग से ऐसी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है इससे जुड़ा अत्यंत विचारणीय व गंभीर मामला है और लायक मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में यह कहकर टालने की कोशिश की है कि महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय से रिपोर्ट विभाग के पास नहीं आई। जबकि विश्वविद्यालय ने अपने लेवल पर जांच कराई है और उसमें यह दर्शाया गया है कि जिला झज्जर के ज्यादातर गांवों में कुओं और हैण्ड पम्पों का पानी

पीने लायक नहीं है। आज हमारे इलाके की हालत यह है कि वहां कई अलग किस्म की बीमारियां पानी का स्तर गिरने से पैदा हो गई हैं। मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में केवल इतना कहा है कि विभाग को रिपोर्ट नहीं मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग का दायित्व नहीं बनता था कि विश्वविद्यालय से उस रिपोर्ट के बारे में कोई सलाह-मशविरा करते। यदि इस बारे में विभाग द्वारा कोई कोताही हुई है तो भी बताएं ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे पास न तो कोई सूचना आई, न कोई रिपोर्ट आई और न ही छारा, भापड़ौदा तथा आसंडा गांवों के बारे में किसी ने लिखकर भेजा, न ही गांव वालों ने ही कुछ लिखा। वैसे सारे गांवों का हमारे पास सर्वेक्षण है कि कहां पर खारा पानी है, कहां पर नमकीन है। जहां तक खारे पानी का संबंध है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़ व रिवाड़ी इन आठ जिलों में जमीन के नीचे खारा पानी है उनके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि कैनाल बेसड वाटर सप्लाई स्कीम से इन जिलों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी दें। जहां तक छारा गांव का सवाल है वहां 30-40 लीटर पानी की व्यवस्था है इस समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1985 में काम शुरु हुआ था टैंक बना लेकिन वह छोटा पड़ता था उसकी बढ़ौत्तरी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपके एरिया के लोग इनलैट चैनल्ज को तोड़ देते हैं और पानी अपने खेतों में लगा लेते हैं और आप जो वहां के नेता लोग हैं वहां के लोगों को समझाते नहीं हैं। हमें वहां की समस्याओं का पूरा-पूरा ध्यान है कि किस गांव में कितना पानी दें।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पोलिटिकल स्टेटमैंट देने की कोशिश की है। ये इस बात से अवगत नहीं हैं कि चोरी तो तब होगी जब टेल पर पानी जाएगा। बादली हल्के में किसी भी नहर की टेल एंड पर पानी नहीं जाता है जब पानी जाएगा ही नहीं तो चोरी कहां से होगी ? मैं आपके द्वारा हाउस से गुजारिश करता हूं कि आप एक कमेटी बना दें जो कि बादली हल्के में जाकर देखे कि वहां कितनी टेल हैं और वर्तमान सरकार के बनने के बाद से कितनी टेलों में पानी मुहैया कराया है। पानी खारा तो है ही, उसकी कोई बात नहीं लेकिन उसके अलावा पानी में कई ऐसे गंभीर तत्व आ गए हैं जिससे चर्मरोग व दूसरी बीमारियां फैल रही हैं। बदानी गांव का जिक्र मैं करना चाहूंगा वहां जगन नाथ जी का राज आने के बाद कभी भी टेल पर पानी नहीं गया। ट्यूबवैल्ज का पानी उस गांव की वाटर वर्क्स में डाला जाता है इस बात की आप इंक्वायरी करवा सकते हैं। उस पानी को पीने से इस गांव में चर्म के रोगी बढ़ते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिये।

श्री धीर पाल सिंह : मंत्री जी पोलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं भी यही कहता हूं कि ये केवल अखबारों में ही खबर देते हैं। अध्यक्ष जी आप इस बात को गम्भीरता से लें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम एग्जामिन करवायेंगे।

श्री धीर पाल सिंह : ठीक है, सर।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन के दौरान भी यह बात कही थी कि मेरे हल्के में दो गांव खेड़ी और दिपालपुर हैं इन गांवों में ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन वे चालू नहीं किए गये हैं। इन गांवों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है उसके बारे में मंत्री जी ने क्या कदम उठाये हैं क्योंकि मेरे हल्के में पानी की सतह काफी नीचे है। मेरे हल्के के 5-6 गांव जैसे छतेरा, नाहरी, माजरा इन गांवों के लोगों ने पीने के पानी का बंदोबस्त अपने आप किया है जबकि इन को पानी नहीं मिल पा रहा है।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहब मुझे लिखकर दे दें उसके हिसाब से हम पता करवा लेंगे कि कहां पर गड़बड़ है।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उन गांवों के ट्यूबवैल्ज़ को चालू करवायेंगे। मैं इनको लिखकर भी दे दूंगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इन गांवों में पानी की व्यवस्था करें।

श्री जगन नाथ : आप लिखकर दे दें हम पानी की व्यवस्था करवा देंगे।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी धीरपाल सिंह जी का मेन क्वैश्चन यह था कि विश्वविद्यालय से कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट विभाग को मिली है या नहीं, मंत्री जी ने बगैर विभाग से पता लगाये कह दिया कि रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : इनके पास रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री बलवन्त सिंह : विभाग से इनके पास यह इन्फर्मेशन तो आई होगी कि रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। यह बात तो मंत्री जी कह सकते हैं। उनका यह फर्ज बनता था कि वे विभाग से इस बारे में जानकारी प्राप्त करते और वहां से रिपोर्ट मंगवाते। यह तो उनका कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं है क्योंकि पुराने पाईप लगे हुये हैं जो जगह-जगह से टूटे हुये हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में रिपोर्ट समय-समय पर सारे राज्य से मंगाते रहते हैं। जहां पर पोटेबल वाटर की कमी है और जहां पर पानी में कोई गड़बड़ है वहां पर स्वास्थ्य विभाग और जन-स्वास्थ्य विभाग को भी उसको ठीक करने के लिए कहते रहते हैं। यह हम मानते हैं कि जहां पर कैनाल बेसड वाटर सप्लाई नहीं होती है, वहां पर पानी की कमी है। कई बार नहरों में बाढ़ का पानी भी डाला जाता है, उसमें गारा भी होता है और कैमिकल्स, फर्टीलाइज़र की मिट्टी भी होती है, जहां-जहां पर इस तरह की गड़बड़ है उसको हम फेज़ड मैनर में ठीक करवायेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि बाढ़ का पानी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई वाली नहर में न डाला जाये।

श्री बलवन्त सिंह : जो पाईप टूटे हुये हैं उनमें बाहर का गंदा पानी चला जाता है।

श्री बंसी लाल : उनको भी ठीक करवायेंगे।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, जो लोहे के पाईप टूट गये हैं उनको बदलवा देंगे।

श्री जसविन्द्र सिंह सिन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के के दो गांव गुमथला गढ़ू जिसमें तीन पंचायतें हैं और डेराफतेहपुर जिसमें दो पंचायतें हैं और एक गांव मदनपुर डेरा है इन तीनों गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले सैशन में भी मैंने इस बारे सवाल किया था और मंत्री जी ने कहा था कि लिख कर दो। जो बात पिछले सैशन में हुई हो उसके बारे में तो लिखकर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को एक साथ जवाब कैसे दे सकता हूं ये मुझे लिखकर दे दें तभी मैं कोई कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री जसविन्द्र सिंह सिन्धू : अध्यक्ष महोदय, जो बात पिछले सैशन में आई हो उसके बारे में लिखकर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे बरौदा हल्के में बरौदा गांव है जिसकी दो पंचायतें हैं और वह 17-18 हजार की आबादी का गांव है उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है और बरौदा गांव की पंचायत मंत्री जी के पास आकर भी मिली थी, मंत्री जी ने एक्सीयन साहब को फोन भी किया था लेकिन अब तक उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। पंचायत ने वहां पर पांच-छः लाख रुपए लगाकर ट्यूबवैल लगाया हुआ है तो क्या मंत्री जी वहां पानी की व्यवस्था के लिए कुछ विचार करेंगे ?

श्री जगन नाथ : मान्यवर, हम तो पहले से ही कर रहे हैं, मैंने एक्सीयन और एस०ई० को टैलीफोन कर दिया था और इस बात को छः महीने हो गए हैं, उसके बाद तो कोई मेरे पास आया ही नहीं इसलिए मुझे क्या पता कि वहां पर पानी की दिक्कत है। जो प्रश्न था वह तो छारा, भापड़ौदा और आसन्डा में पेयजल की व्यवस्था के सर्वेक्षण का था कि सर्वेक्षण हुआ या नहीं लेकिन माननीय सदस्यगण तो सारी स्टेट के बारे में सूचना मांगने लग गए कोई स्पेसिफिक क्वैश्चन होना चाहिए।

Cases of Rapes/Murders/Dacoity etc. registered in the State

@*800. Shri Sampat Singh
Capt. Ajay Singh Yadav } : Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the number of absconders in the State as on May 1, 1996 and at present;

(b) the number of cases of murders, rapes, kidnapping/abduction, dacoity, theft in general and of vehicles in particular, snatching of ornaments and vehicles registered in the State from April 1, 1998 todate; and

(c) the number of cases out of those as referred to in part (b) above in which the accused have been arrested/convicted and acquitted during the said period ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

		As on 1-5-96	**As on 31-12-98**
(a)	Total number of absconders	6783	7371
(b)	Head of crime	Cases registered from 1-4-98 to 31-12-98	
	Murder	657	
	Rape	265	
	Kidnapping/abduction	409	
	Dacoity	66	

@ Put by Shri Sampat Singh.

[Shri Mani Ram Godara]

Total theft	4604
Vehicle theft	1991
Snatching of ornaments	204
Snatching of vehicles	132

(c) Head of Crime — The number of cases out of which those as referred to in part (b) above in which the accused have been arrested, convicted and acquitted.

	Cases in which accused arrested	Cases in which accused convicted	Cases in which accused acquitted
Murder	467	1	12
Rape	240	—	10
Kidnapping/abduction	292	—	5
Dacoity	44	—	—
Total theft	1783	22	8
Vehicle theft	744	1	—
Snatching of ornaments	81	—	—
Snatching of vehicles	78	—	1

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, वैसे तो इन आंकड़ों से सारी स्थिति का पता लग जाता है लेकिन भगौड़ों की संख्या जो है वह 7371 हो चुकी है और ये लोग रोज क्राइम कर रहे हैं जिसकी वजह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जेल और पुलिस की हिरासत से भागे हुए लोगों की कितनी संख्या है ? जो वाहनों की चोरी व वाहन छीनने की घटनाएं हैं वे बहुत चौकाने वाली हैं ? जिनकी नौ महीने में संख्या 2123 हो गई है। महीने की औसत निकालें तो 236 केस पर-मन्थ हैं यानी 8 प्रतिदिन हैं, और इन केसिज में गिरफ्तारियां केवल 812 दिखाई गई हैं। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि चोरी की गई वाहनों में से कितने वाहनों की रिकवरी हुई है क्योंकि ये तो गिरफ्तारियां हैं जो एक तिहाई हुई हैं। इसी प्रकार स्पीकर सर, अपहरण, बलात्कार, हत्याएं और दूसरी डकैतियां ये सारे इतने केसिज हैं जिनमें रोज की दो, तीन और एक की औसत आ रही है। क्या इसके लिये कोई प्रबन्ध किया है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने सनेचिंग ऑफ व्हीकल्ज के बारे में पूछा है कि उनकी क्या स्थिति है, उस मामले के अन्दर टोटल प्रोपर्टी के हिसाब से हम उसकी कीमत लगा रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : किस चीज की कीमत लगा रहे हैं ?

श्री मनी राम गोदारा : व्हीकल्ज जितनी छीनी गई, उसकी कीमत लगा रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने दुकान या मकान का जिक्र नहीं किया है। मैंने प्रोपर्टी के बारे में सवाल नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ यह प्रश्न किया है कि जेल या पुलिस हिरासत से कितने व्यक्ति भागे हुए हैं तथा जो वाहन चोरी हुए हैं उन केसिज़ में से केवल एक तिहाई केसिज़ में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कुल कितने वाहनों की रिकवरी हुई है। इसी तरह से मैंने यह पूछा था कि इन की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, जो अपराधी पुलिस कस्टडी से भागे हैं, इस साल की उनकी संख्या 65 है।

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल के जवाब में जो फिगर दर्शाई गई है उनमें से पूछ रहा हूं इस वर्ष की नहीं पूछ रहा हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम ने जो डकैती की प्रोपर्टी रिकवर की है, उस की कीमत आंकी गई है—एक करोड़ 59 लाख रुपए।

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कीमत नहीं पूछी है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो वाहन चोरी हुए हैं या जो वाहन छीने गए हैं, उनकी रिकवरी की कुल संख्या कितनी है ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, 85.21 प्रतिशत की रिकवरी हुई है।

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने वाहनों की रिकवरी के बारे में पूछा है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, 1557 चोरी हुए वाहनों में से 645 वाहनों की रिकवरी हुई है।

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेन सवाल की रिप्लाई में 1991 वाहन चोरी हुए बताए गए हैं और 132 वाहन छीने गए हैं, ये कुल 2123 की संख्या बनती है, इन में से कितने वाहनों की रिकवरी हुई है ? इन केसिज़ में गिरफ्तारियों के बारे में बता ही रखा है। मैं तो सिर्फ वाहनों की रिकवरी के बारे में पूछ रहा हूं। अगर इस समय तथ्य इनके पास नहीं हैं तो ये समय ले सकते हैं। (विघ्न) This is the position of the Government. This is the preparation of the Minister.

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, कुल 1991 वाहन चोरी हुए हैं। इन में 744 केसिज़ वर्क आउट हुए हैं। 859 केसिज़ अंडर इंवेस्टीगेशन हैं। 659 वाहन अंट्रेस्ड पाए गए हैं तथा 12 मामले रद्द कर दिए गए हैं। एक मामले में कंविक्शन हुई है। 460 मामले अंडर ट्रायल हैं।

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितने केसिज़ सौल्व हुए हैं। मैं तो केवल चोरी हुए वाहनों की रिकवरी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, रिकवरी के बगैर कोई अरैस्ट नहीं होता है। (शोर)

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। This is the most unfortunate situation if such type of answer is given by the senior Minister. (Interruptions)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि चोरी हुए वाहनों की रिकवरी की संख्या 645 है और छीने हुए वाहनों की संख्या 56 है लेकिन यह सूचना नोट फार दि पैड पर पूरी तरह से तैयार नहीं की गई है। इसके लिए मैं महकमे को जिम्मेवार मानता हूं। (Interruption) It should not be repeated. They have taken it in a casual way.

श्री बंसी लाल : कोर्ट से परमिशन ले कर तो लगा सकते हैं लेकिन वह कोर्ट तक जाने से पहले भाग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो जेल जम्पर्ज हैं उनके बारे में हमने देखा है कि कितना ही सीरियस क्राइम् किया हो उसकी अदालत में जाते ही जमानत हो जाती है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम उनके खिलाफ अपील भी करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कतें हैं। रही बात यह कि सरकार ने बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए हैं जहां तक सरकार का सवाल है हमने पूरे प्रबन्ध किए हैं। फलाइंग स्कवैड भी बनाई गई हैं। डी०जी० पुलिस डी०आई०जी० और एस०पी० की इस संबंध में 2-3 बार मीटिंग करके उनको हिदायतें दी हैं। डी०जी० पुलिस खुद भी स्टेट का दौरा समय समय पर करते हैं और पुलिस को ताकीद करके आते हैं। इससे पुलिस के काम में मुस्तैदी भी आई है। पहले की अपेक्षा ला एण्ड आर्डर काफी सुधरा है। क्राईम अकेले हरियाणा में नहीं बढ़े। यह समस्या हरियाणा के लिए ही नहीं सारे देश के लिए बनी हुई है।

Setting up of River Authority

***805. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state whether the State Govt. has approached the Central Govt. to set up an authority to sort out the water dispute amongst the States of Punjab, Haryana, Himachal, Rajasthan, U.P. & Delhi on the pattern of Cavery River Authority during the year 1998; if so, the details thereof ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन कावेरी जल बिवाद ट्रिब्यूनल के अन्तरिम आदेश को लागू करवाने के लिए किया गया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार के विचाराधीन ऐसे किसी भी प्राधिकरण के गठन का सुझाव देने की योजना निम्नलिखित के कारण नहीं है :— यमुना जल के बटवारे हेतु तथा यमुना नदी के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के मध्य जल विवादों को सुलझाने के लिए पहले से ही एक ऊपरी यमुना नदी बोर्ड काम कर रहा है। इस बोर्ड के ऊपर सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक ऊपरी यमुना नदी समीक्षा समिति भी है।

रावी व्यास के जल विवाद को सुलझाने के लिए सन् 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जिसने जनवरी 1987 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण एवं मार्ग निर्देश देने की प्रक्रिया जारी है ताकि इस रिपोर्ट की अधिसूचना जारी की जा सके। वर्तमान सरकार की लगातार कोशिशों के बाद लगभग 8 सालों के बाद इस ट्रिब्यूनल की कार्यवाही जुलाई 1997 में दुबारा शुरू हुई है। वर्तमान स्थिति में जब तक कि इस ट्रिब्यूनल के निर्णय की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, ऐसे नदी प्राधिकरण के गठन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० और यमुना नदी के पानी का बंटवारा पांच स्टेटों के बीच में है जिनमें दिल्ली, यू०पी०, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा प्रदेश राज्य शामिल हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब कावेरी नदी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट इम्पलीमैंट हो सकती है तो उसी तर्ज पर यहां पर कोई रीवर अथोरिटी बना कर उसका फैसला इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया जाता ? मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में अब तक सरकार ने क्या काम उठाये ताकि दक्षिण हरियाणा को पानी मिल सके। एस०वाई०एल० का पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए लाईफ लाईन है। इस डिस्प्यूट को चलते हुए कई वर्ष हो चुके हैं। सरकार ने इस मामले में अब तक कितनी मीटिंगें की हैं। कितनी बार आप प्रधान मंत्री से मिले हैं। पीछे राजस्थान में भी भाई रामबिलास शर्मा जी की पार्टी की

सरकार थी यू०पी० में भी इनकी सरकार थी। जिस प्रकार से तामिलनाडू में जयललिता ने एक रीवर अथोरिटी बनवाकर उसको इम्पलीमेंट करवाया है क्या उसी प्रकार की रीवर अथोरिटी यहां पर सरकार बनाने की सोच रही है ? सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं, उनके बारे में सदन को डिटेल में बतायें ?

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाई अजय सिंह के सवाल की बात है; हमारी सरकार इस मामले में बहुत चिन्तित है। कावेरी नदी जल ट्रिब्यूनल वाली बात है, उसकी जरूरत जब पड़ी तो यह मामला सुलझ गया। जिस प्रकार इराडी ट्रिब्यूनल बना था उसी प्रकार का ट्रिब्यूनल वहां बना। जब उसके फैसले की नोटिफिकेशन हो चुकी थी और उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी तब वहां पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कावेरी नदी प्राधिकरण की जरूरत पड़ी। जहां तक हमारे रावी-व्यास और एस०वाई०एल० की बात है, इस बारे में इराडी ट्रिब्यूनल 1986 में बैठा था और उस समय हरियाणा के मुख्य मन्त्री आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी ही थे, उनके मुख्य मन्त्रित्वकाल में ही यह ट्रिब्यूनल नियुक्त हुआ था। उस ट्रिब्यनल ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कुछ और जरूरी कार्यवाही भी करनी पड़ती है। 1987 से ले कर 1996 तक के समय के दौरान में मेरे साथी कैप्टन अजय सिंह जी की सरकार भी यहां पर रही और सैंटर में भी इनकी सरकार रही। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार भी रही और उस दौरान इनके पिता श्री सैंटर की सरकार में उप-प्रधान मन्त्री रहे लेकिन तब भी इनकी तरफ से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। इराडी ट्रिब्यूनल के बारे में 1996 में हमारी सरकार ने आते ही, 8 साल से इस ट्रिब्यूनल के साथ जो एक भी सुनवाई नहीं हुई थी और एक भी तारीख नहीं लगी थी, जुलाई, 1997 में इसकी सुनवाई शुरू हुई। उसके बाद दिसम्बर, 1997 में उसकी तारीख लगी, अप्रैल, 1998, जुलाई, 1998, 16 अक्तूबर, 1998 को इसकी तारीख लगी। अध्यक्ष महोदय, जस्टिस श्री यू०सी० बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो गए और उसके बाद 9 फरवरी 1999 की तारीख लगनी थी। इस बारे में आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की है, वह भी मैं बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 9 जनवरी, 1999 की तारीख इस कारण नहीं लगी कि जस्टिस श्री बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हो गये। केवल 11 दिन बाद यानि कि 20 जनवरी, 1999 को आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने एक चिट्ठी आदरणीय प्रधान मन्त्री जी को लिखी है कि हमारा केस डिले न हो इसलिए जस्टिस श्री बैनर्जी की जगह जल्दी से जल्दी किसी अन्य मैम्बर को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरे ख्याल से इससे जल्दी और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। इससे यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी चिन्तित है। अध्यक्ष महोदय, जिस मामले में 8 साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हमारी सरकार ने सिर्फ दो साल के अर्से में इतना काम किया है। हमारी सरकार को एस०वाई०एल० के मामले पर 9 सितम्बर, 1996 से किसी प्रकार का सहयोग मिलने की उम्मीद नहीं हुई तो सितम्बर, 1996 में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस मामले में 27 तारीख को इसकी पहली पेशी लगी। अगली पेशी में पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा। जिस दिन उनका जवाब आ जाएगा हम पूरी तरह से इस मामले को परस्यू करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री जय सिंह राणा, अगला सवाल पूछें।

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बोलने के लिए खड़े हो गए) (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। मैंने पहले ही जय सिंह राणा का नाम अगले सवाल के लिए बोल दिया है, इसलिए आप सभी अपने स्थान पर बैठें।

Mid Day Meal

***842. Shri Jai Singh Rana** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of schools in which facility of Mid-Day meal is being provided in the State; and

(b) whether the financial assistance is being provided by the Central Govt. to the schools as referred to in part (a) above; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) मध्याह्न पोषाहार की सुविधा सभी 8701 राजकीय प्राथमिक स्कूलों तथा 147 राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में दी जा रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है, लेकिन सूखा खाद्यान (गेहूं/चावल) जो बच्चों में बांटा जाता है, के साथ परिवहन प्रभार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत प्रति विद्यार्थी कितना खर्च होता है और हरियाणा सरकार इसमें कुल कितना खर्च कर रही है। इसके साथ ही मंत्री जी यह भी बताएं कि इस योजना से कितने विद्यार्थियों को लाभ हुआ है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह योजना अगस्त 1995 में बहादुरगढ़ के बालौर गांव में प्रारम्भ की गई थी। उस समय श्रीमान नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में जो पोषाहार दिया जाता था उसकी बड़ी भारी आलोचना की गई। अध्यक्ष महोदय, आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम उस वक्त अपोजिशन में बैठते थे। हमने उस वक्त इस योजना के बारे में टिप्पणी की थी कि "बहन जी बनावे स्वाटर, मास्टर रांधे दलिया। थाली बजावैं राम्भा, धापा और गुलिया।" यह टिप्पणी उस वक्त इस योजना के बारे में की थी। (विघ्न) स्पीकर साहब, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार आई तो चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में हमने इस योजना को दोबारा से शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त सात सौ रुपए में एक महिला को दलिया रांधने के लिए रखना था और इसके ऊपर सरपंच और पंच लड़ पड़े। प्राथमिक विद्यालय में कुल मिलाकर पांच घंटे पढ़ाई होती थी और उसमें से तीन घंटे बच्चों का लिंगा दलिया रांधने की प्रक्रिया को देखने में, कढ़ाई की तरफ और थाली तथा कचोला बजाने वालों की तरफ रहता था। वहां पर कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। इसलिए उस समय हमने इस योजना पर टिप्पणी की थी। हमने 1996 में आते ही जुलाई में इस पर पुनः विचार किया। हमने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अपने यहां के विभाग के साथ बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बारे में विचार विमर्श किया क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। इस बारे में हमने बच्चों के अभिभावकों से भी विचार विमर्श किया और इसका प्रावधान किया है। (विघ्न) स्पीकर साहब संक्षिप्त में जब हम जवाब देते

हैं तो इनका पेट नहीं भरता है और जब हम विस्तृत में दबाव दे रहे हैं तो उसको ये सुनने को तैयार नहीं हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, यह मामला बच्चों को संस्कारिक करने का है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप थोड़ा संक्षेप में बता दें।

श्री राम बिलास शर्मा : ठीक है सर, राणा साहब ने पूछा है कि इसमें प्रति बच्चा हरियाणा सरकार कितना पैसा खर्च करती है तथा केन्द्र सरकार कितना पैसा खर्च करती है। हम इस स्कीम के तहत 100 ग्राम सूखा अन्न चाहे वह चावल के रूप में हो या गेहूं के रूप में प्रति बच्चा देते हैं। स्पीकर सर, हर महीने तीन किलो अन्न यानी डेढ़ किलो गेहूं और डेढ़ किलो चावल प्रति बच्चा दिया जाता है। स्पीकर सर, इसमें 80 और 20 का अनुपात है 80 प्रतिशत अनाज केन्द्र सरकार देती है और 20 प्रतिशत इसमें हरियाणा सरकार का योगदान है। राणा साहब ने यह भी जानना चाहा है कि इस स्कीम से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि 17 लाख 25 हजार बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले इससे लाभान्वित हुए हैं और 147 विद्यालय ऐसे हैं जिनको सरकार 95 प्रतिशत सहायता देती है यानी हम इनको एडिड कैटेगरी के विद्यालय मानते हैं। इन 147 विद्यालयों के 42 हजार बच्चे भी इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं यानी टोटल 17 लाख 67 हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इनको कुछ स्कूलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वहां पर राशन का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं किया जाता ? अगर ऐसी शिकायतें इनको मिली हैं तो क्या इन्होंने उन अध्यापकों या अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय विधायक ने ठीक कहा है। हमें कुछ जिलों में कुछ स्कूलों से इस तरह की शिकायतें मिली हैं। सर, यह राशन भारत सरकार से आता है इसलिए कई बार वहां से यह दो या तीन महीने लेट आता था तो इस तरह की शिकायतें मिली हैं लेकिन हमने इसके लिए भी भारत सरकार के कंसर्ड आदमी से बात करके हर महीने उसको टाईम पर रिलीज करने को कहा है। इसके अलावा कुछ विद्यालयों में यह राशन रखने के कारण कहीं कहीं पर भीग गया था इसलिए यह शिकायत भी हमारे पास आयी थी लेकिन हमने इस को भी दुरूस्त किया है।

Shivalik Board

***837. Shri Ramji Lal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total amount provided for Shivalik Board in the Budget for the year 1998-99;

(b) the names of the places and the schemes on which the amount out of the amount as referred to in part (a) above was spent; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide canal water or tubewells for irrigation purposes in the Shivalik areas; if so, the details thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज पाल सिंह) :

(क) वार्षिक बजट 1998-99 में शिवालिक विकास बोर्ड के लिए 5.69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) वर्ष 1998-99 में विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण संलग्न है।

(ग) शिवालिक क्षेत्र पर्वतीय/अर्धपर्वतीय होने के कारण यहां सिंचाई नहर का निर्माण उपयुक्त नहीं समझा गया। फिर भी पंचकूला जिले के पिंजौर खण्ड में 12 गहरे सिंचाई नलकूप लगाए गए हैं।

विवरण

Sr. No.	Name of the Department	Name of the scheme	Amount (Rs. in lacs)
1	2	3	4
1. COMMUNICATION			
	XEN, PWD, B&R Division No. 1, Ambala	(i) Const. of link road from village Panjokhra to Khatauli	8.00
		(ii) Const. of roads from Rajokheri to Diya Majra	3.00
		(iii) Special repair of roads in Ambala Block Naggal area	5.00
		(iv) Const. of six roads in Naggal area (Distt. Ambala)	5.00
		(v) Const. of link road Haryana Roadways Workshop	1.25
	XEN, Panchayati Raj, Ambala	(i) Internal roads in Ambala City	14.00
		(ii) Drain from Apna Hospital to Session Court	3.00
	XEN, PWD Division No. II, Ambala	Const. of Cement Concrete approach road in Govt. College Ambala Cantt.	1.20
	XEN, PWD B&R Naraingarh	(i) Const. of Link road from Thaska to Sudha Sahib Mandir	9.90
		(ii) Link road from Uttamwala to Panniwala	2.00
		(iii) Link road from Shahbad, Barara, Kala Amb road to village Laharpur	5.00

1	2	3	4
		(iv) Link road from Bilaspur Dhanaura road to Panjoli near Pipliwala	1.63
		(v) Const. of Solid Causeway from Samanwa village in Panchkula district	9.70
		(vi) Link road from Bassi Barwala to village Hangola in Panchkula District	8.50
		Total :	**77.18**
2. PUBLIC HEALTH			
	XEN, PH, Naraingarh	(i) Providing additional pipeline and 11 No. of Public Standposts at Kapal Mochan (Yamuna Nagar district)	2.71
		(ii) Augmentation of water supply scheme in Jagdoli group of 4 No. villages Block Bilaspur, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar	5.00
	XEN, PH, Panchkula	(i) W/S Scheme in village Prempura Block Pinjore	5.00
		Total :	**12.71**
3. HEALTH			
	XEN, PWD, B&R, Naraingarh	Const. of PHC at Pathreri (Ambala district)	4.00
	XEN, PWD, B&R, Division No. II, Ambala	Const. of Mortuary in Civil Hospital, Ambala City	8.00
		Total :	12.00
4. ENVIRONMENT IMPROVEMENT			
	XEN, PWD, Division No. II Ambala	(i) Providing shed on sitting steps in War Hero's Memorial Stadium at Ambala Cantt.	3.41
	XEN, Panchayati Raj, Yamuna Nagar	(i) Community Centre at Bilaspur	7.00
		(ii) Completion of Community Centre at Chhachhrauli	2.18
	XEN, Panchayati Raj, Panchkula	Const. of drain, Nallah and brick pavement and earth filling of phirni at village Mauli, Distt. Panchkula	9.16
		Total :	**21.75**

[श्री सूरज पाल सिंह]

1	2		3	4
5.	**EDUCATION/VOCATIONAL EDUCATION**			
	XEN, PWD, B&R No. II, Ambala	(i)	Boundary wall in Govt. College, Ambala Cantt.	3.00
		(ii)	Const. of two rooms with verandah in Govt. Primary School at chain ki Mandi and Bajigar Colony in Ambala Cantt.	4.80
	XEN, Panchayati Raj Panchkula	(i)	Extension of Deaf and Dumb Centre Building (Ist floor) at Raipur Rani, Distt. Panchkula	5.00
	XEN, PWD, B&R, Panchkula	(i)	JBT Girls' Hostel at Teachers' Training Institute at Morni	10.00
		(ii)	Const. of additional rooms in Govt. Sr. Sec. School, Morni	5.00
	A.D.C., Ambala		Completion of DRDA Training Centre, Ambala	0.50
6.	**WATERSHED MANAGEMENT**			
	D.F.O., Ambala	(i)	Planatation and tree guards in Ambala City & Cantt.	2.50
	D.F.O. (T), Yamuna Nagar	(i)	Pipeline for Thaska Dam	3.00
	D.F.O. Morni at Pinjore	(i)	Afforestation & maintenance of plants planted during the previous years	16.34
	A.S.C.O., Sadhaura	(i)	Soil Conservation works in Manglaur Chanda & Rampur Haria in Sadhaura Block	5.00
	Soil Survey Engineer, Agriculture Deptt., Panchkula	(i)	Soil Conservation works in Morni area	9.55
	D.F.O., Kandi Yamuna Nagar	(ii)	Const. of Pammuwala Dam in Yamuna Nagar Distt.	10.00
			Total :	**46.39**
7.	**Horticulture Development**			
	D.H.O., Yamuna Nagar	(i)	Distribution of fruit plants Strawberry, Supply of Vegetable seeds and Mushroom cultivation on 50% subsidy basis in Yamuna Nagar district	3.00

1	2	3	4
	D.F.O. (Kandi) Y. Nagar	(ii) For setting up a Herbal garden in Bilaspur Block	3.00
		Total :	**6.00**
8.	**FISHERIES DEVELOPMENT**		
	F.D.O., Ambala	(i) Renovation of village fish ponds in Sainmajra, Bhanokheri and Dhurala in Ambala Distt.	6.20
	F.D.O, Yamuna Nagar	(i) Renovation of village fish ponds in Kishanpura, Pipliwala, Malikpur Khadar and Rajpura in Yamuna Nagar	5.00
		Total :	11.20
9.	**SCIENCE & TECHNOLOGY**		
	A.D.C., Panchkula	(i) Provision of Domestic SPV Lighting System and distribution of Solar Lanterens in Morni and Pinjore Blocks in Panchkula Distt.	3.75
10.	**XEN ELECTRICITY**		
	XEN, HVPN, Naraingarh	(i) Electrification of unelectrified Dhanis in Bhoj Kundana and Naggal of Morni Block (Panchkula district)	24.00
11.	**ANIMAL HUSBANDRY**		
	XEN, Panchayati Raj, Panchkula	Const. of Vety. Hospital at Morni	3.97
		Grand Total :	**247.25**

(Funds released to Shivalik Development Agency upto 15-1-1999 - Rs. 275.00 lacs)

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि शिवालिक क्षेत्र के लिए कितनी कितनी राशि किन-किन जगहों पर और किन-किन स्कीम्ज पर खर्च की गयी है ? शिवालिक क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकार ने कुछ ट्यूबवैल्ज लगवाये थे लेकिन जबाव में कहा गया है कि 12 ट्यूबवैल्ज पिंजौर खण्ड में लगाए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये ट्यूबवैल्ज पूरे शिवालिक एरिये में जो कालका से लेकर ताजेवाला तक लगता है, लगवाए गए हैं या नहीं ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिंजौर खण्ड में 12 नलकूप लगाए गए हैं क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए नहर वगैरा वहां पर संभव भी नहीं है। जिन-जिन स्कीम्ज पर आज तक राशि खर्च की गयी है उनके नाम इस प्रकार है, कम्युनिकेशन के लिए 77.18 लाख रुपए, पब्लिक हैल्थ के लिए 12.71 लाख रुपए, हैल्थ के लिए 12 लाख रुपए, इंबायरमैन्ट इम्प्रूवमैंट के लिए 21.75 लाख और ऐजुकेशन एवं वोकेशनल ऐजुकेशन के लिए 46.39 लाख रुपये इत्यादि मदों के लिए टोटल 247.25 लाख रुपए दिया गया है।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में दर्शाया गया है कि 12 ट्यूबवैल्ज पिंजौर क्षेत्र में लगाए गए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या शिवालिक एरिया केवल मोरनी या पिंजौर तक ही है ? सर, शिवालिक एरिया तो कालका से लेकर ताजेवाला तक लगा हुआ है लेकिन सिंचाई के लिए ये ट्यूबवैल्ज केवल पिंजौर खण्ड में ही लगाए गए हैं जबकि ये ट्यूबवैल्ज उस क्षेत्र में भी लगवाए जाने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, शिवालिक बोर्ड के ऐजेण्डा में दर्शाया गया है कि पार्कों को सुंदर बनाने के लिए 25-25 लाख रुपये दिए गए हैं क्या यह पैसा केवल पार्कों को सुंदर बनाने के लिए है, क्या शिवालिक बोर्ड इसलिए बनाया गया था ? शिवालिक क्षेत्र के लोगों के लिए ऐजुकेशन का कोई भी प्रबन्ध नहीं है अगर ऐजुकेशन के लिए कोई स्कूल है भी तो वहां पर कोई टीचर नहीं है। इस एरिया के लोगों के लिए ठीक से पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है और सिंचाई की भी बहुत बुरी हालत है। वहां के लोग कुदरत के रहमोकरम पर जीते हैं और कुदरत ही उनकी खेती पैदा करती है। मैं जानना चाहता हूं कि शिवालिक बोर्ड का पैसा पार्कों पर लगाने के लिए हैं या उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए है ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पैसा पार्कों के लिए नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि हमने सिंचाई के लिए 12 नलकूप लोहागढ़, सुपरखेड़ी, जाटामाजरी, खीड़ा तालूवाल, धरीड़ी करनपुर-1, करनपुर-2 और करनपुर नं०-3, नानकपुर रामपुरजंगी व धामला आदि गांवों में लगाए। यह सारा पैसा सिंचाई के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से सड़कों पर व पब्लिक हैल्थ के कार्यों पर पैसा खर्च हुआ है। सारा पैसा शिवालिक विकास कार्यों के लिए खर्च हो रहा है।

श्री रामजी लाल : अम्बाला कैन्ट में एक पार्क को सुन्दर बनाने के लिए 25 लाख रुपया दिया गया है। जो पैसा लोगों के उत्थान के लिए लगना चाहिए वह पैसा पार्कों पर खर्च हो रहा है और यह बात एजेन्डे में है और एजेन्डा मेरे पास है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा हमारे साथी ने पूछा है कि शिवालिक बोर्ड के एजेन्डे में दर्शाया गया है कि एक पार्क के रख-रखाव के लिए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है तो जहां पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को ठीक करने की बात है, शिक्षा की बात है पब्लिक हैल्थ की बात है इसमें पार्कों की बात कहां से आ गई यह जानकारी चाहूंगा ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि जहां पर विकास के लिए गलियों का पक्का होना, ट्यूबवैलों का लगवाना जरूरी होता है वहां आबादी के साथ-साथ उनके मनोरंजन के लिए भी कोई जरिया होना चाहिए, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सारी बातें की गई हैं।

Panipat Sugar Mill

***844. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) the date on which the Cooperative Sugar Mill was set up; and

(b) whether any meetings of the General Body of the aforesaid Sugar Mill were held since its inception to date; if so, the dates of such meetings ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) पानीपत सहकारी चीनी मिल 11-12-1955 को रजिस्टर्ड हुई थी और मिल द्वारा 21-03-57 से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया था।

(ख) पानीपत सहकारी चीनी मिल की आम सभा की बैठकें इसके स्थापित होने के बाद निम्नलिखित तिथियों में हुई हैं।

1. 20-12-1961
2. 03-09-1966
3. 23-10-1971
4. 25-10-1976

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1961, 1966, 1971 व 1976 में पानीपत शुगर मिल में मीटिंग हुई थीं उसके बाद से 22 वर्ष हो चुके हैं 22 वर्ष से पानीपत शुगर मिल में आम सभा नहीं बुलाई गई, इसका क्या कारण है और मीटिंग बुलाने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पानीपत शुगर मिल पिछले 20 वर्षों से नुकसान में है और हमारी सरकार आने के बाद रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसायटीज ने हर को-ऑपरेटिव इंसटीच्यूशन को 25-2-97 को चिट्ठी लिखी है कि हर जनरल बॉडी की साल में एक बार मीटिंग बुलाई जाए। पानीपत शुगर मिल के प्रबन्ध निदेशक से 30-6-98 को इस बारे में डिसकशन हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी शुगर मिल की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और इसके 34144 मैंबर हैं मीटिंग बुलाने में तकरीबन 5 लाख रुपये का खर्च आता है इसलिए जब तक वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक उसमें मीटिंग न रखी जाए।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Road from Sanghi to Chiri

***850. Shri Siri Krishan Hooda** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the present stage of the construction work of the road from village Sanghi to Chiri of district Rohtak together with the amount spent thereon so far ?

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : गांव सांघी से चिड़ी तक सड़क का अधिकतर भाग अर्थात 5.39 कि०मी० पूर्ण हो चुका है। 3.91 कि०मी० लम्बाई पर मिट्टी का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इस कार्य पर अभी तक 28.16 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

Financial Position of the Universities

***826. Shri Dharambir :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether Vice Chancellor, Kurukshetra and other Universities have made any representation in regard to grim financial position of the Universities in the State during the year, 1998; and

(b) if so, details thereof togetherwith the action taken by the Government in this regard ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) जी नहीं, उप कुलपति महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को छोड़ कर।

(ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के लिये पहले ही संशोधित वेतनमानों के प्रभाव सहित नान-प्लान पक्ष पर 1532.20 लाख रुपए का तथा विकास कार्य के लिये प्लान पक्ष पर 200 लाख रुपए का अनुदान व्यवस्थित है जबकि वर्ष 1997-98 में इसकी तुलना में नान-प्लान पक्ष पर 1107 लाख रुपए तथा प्लान पक्ष पर 115 लाख रुपए रिलीज किये गये थे। यह राशि किश्तों में रिलीज की जाती है। संशोधित अनुमानों द्वारा प्रत्येक मामले की मैरिट पर अतिरिक्त राशि रिलीज करना, वास्तविक आवश्यकता तथा सरकार के पास साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Filling of Vacant Posts of Polytechnic College, Narnaul

***860. Shri Kailash Chandra Sharma :** Will the Minister for Technical Education be pleased to state the time by which the vacant posts of polytechnic College, Narnaul are likely to be filled up ?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नारायण सिंह) : हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से योग्य उम्मीदवारों की सिफारिशें अपेक्षित हैं। ज्योंहि योग्य उम्मीदवार सिफारिश किये जाएंगे, उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जाएंगे।

Construction of Chara Mandi, Ambala Cantt.

***852. Shri Anil Vij :** Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Chara Mandi at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the said Chara Mandi is likely to be constructed ?

बागवानी तथा विपणन राज्य मंत्री (श्री जगवीर सिंह मलिक) :

(क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) पर दिये गये उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

Sannihit Sarovar, Kurukshetra

***880. Shri Ashok Kumar :** Will the Minister for Local Government be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to check the falling of contaminated water into the Kurukshetra holy Sannihit Sarovar ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डॉ० कमला वर्मा) : लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य विभाग) द्वारा आसपास के गांवों तथा रिहायशी कालोनियों के बरसाती पानी तथा गन्दे पानी की दिशा बदलने तथा इसको सन्निहित सरोवर में गिरने से रोकने के लिए एक योजना तैयार की गई है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

Building of Veterinary Hospital Bahadurgarh

***902. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) whether the building of veterinary hospital, Bahadurgarh is in dilapidated condition; and

(b) if so, the time by which the aforesaid building is likely to be repaired ?

पशुपालन मन्त्री (श्री जसवन्त सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) धन राशि उपलब्ध होते ही मरम्मत का कार्य जितना शीघ्र सम्भव होगा आरम्भ कर दिया जायेगा।

Consolidation of Holdings

***895. Shri Balbir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to conduct the consolidation of holdings in the villages of Mokhra Kheri Rohaz, Girawar, Nidana and Bhaini Chander Pal of the Meham constituency; and

(b) if so, the time by which it will be completed ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज पाल सिंह) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) गांव गिरावड़ व निदाना का चकबन्दी कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। गांव मोखरा खेड़ी रोझ व भैणी चन्द्रपाल का चकबन्दी कार्य अगले 2-$2^{1/2}$ वर्षों में पूर्ण कर दिए जाने की सम्भावना है।

Television Sets

***886. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Education Department has purchased colour televisions for schools during the year 1995; and

(b) if so, the district-wise names of the schools in which the aforesaid televisions have been provided togetherwith the purpose thereof ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान्; केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन 1995 में स्कूलों के लिये रंगीन टेलिविजन खरीदे गये हैं।

(ख) ये रंगीन टेलिविजन प्रान्त के 13 जिलों के 359 स्कूलों में दिये गये हैं। स्कूलों की जिलावार सूची अनुबन्ध-1 पर उपलब्ध है। रंगीन टेलिविजनों का उद्देश्य कक्षा-अध्यापन में आधुनिक-शिक्षण-प्रणाली को स्थान देना है।

अनुबन्ध—1

जिलावार विद्यालयों की सूची जहां पर रंगीन टेलिविजन प्रदान किये गये।

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	स्थान
1	2	3
	जिला : अम्बाला	
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	सकेतड़ी
2.	—सम—	बुर्ज कोटिया
3.	—सम—	विटना
4.	—सम—	चिकन
5.	—सम—	बतौड़
6.	—सम—	भूड़ी
7.	—सम—	पपलोहा
8.	—सम—	टेपला
9.	—सम—	शाहपुर (कन्या)
10.	—सम—	राजौली (कन्या)
11.	—सम—	बड़ागांव
12.	—सम—	कुराली
13.	—सम—	रामगढ़ (कन्या)

1	2	3
14.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	अम्बली
15.	—सम—	पंजलासा
16.	—सम—	जलोली
17.	—सम—	समलेड़ी
18.	—सम—	करधाव
19.	—सम—	सोंडा
20.	—सम—	दानीपुर
21.	—सम—	धरनिया
	भिवानी	
22.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	खेड़ी सनवाल
23.	—सम—	बलकरा
24.	—सम—	नरसिंहबास
25.	—सम—	भागेश्वरी
26.	—सम—	गोठड़ा
27.	—सम—	सातड़ (कन्या)
28.	—सम—	सारंगपुर
29.	—सम—	बरसामा
30.	—सम—	बिरन
31.	—सम—	नाथूवास
32.	—सम—	दिनोद (कन्या)
33.	—सम—	भैंगला
34.	—सम—	बरटाना
35.	—सम—	कुंडल (कन्या)
36.	—सम—	पूर (कन्या)
37.	—सम—	सिंपली
38.	—सम—	बडाला
39.	—सम—	खानक
40.	—सम—	बड़सी
41.	—सम—	जताई
42.	—सम—	कालुवास

[श्री राम विलास शर्मा]

1	2	3
43.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	मिथाथल (कन्या)
44.	—सम—	प्रलादगढ़
45.	—सम—	कुसुम्बी
46.	—सम—	मौरंगाबाद
	फरीदाबाद	
47.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	छज्जू नगर
48.	—सम—	विधावती
49.	—सम—	बढ़ा
50.	—सम—	धत्तीर
51.	—सम—	सारोली
52.	—सम—	छपरोला
53.	—सम—	फिरोजपुर
54.	—सम—	गडोपट्टी
55.	—सम—	जटौली
56.	—सम—	गुथराना
57.	—सम—	मामनजाट
58.	—सम—	मूंडकोला
59.	—सम—	टिकरी गुजर
60.	—सम—	रमडाना
61.	—सम—	रूंधी
62.	—सम—	विड़ुकी
63.	—सम—	अलापुर
64.	—सम—	दांडेरी
65.	—सम—	फुलधाड़ी
66.	—सम—	एतमादपुर
67.	—सम—	कारोली (कन्या)
68.	—सम—	मंदउवली
69.	—सम—	नगला गुजरान
70.	—सम—	झाजरू
71.	—सम—	संसरावली

1	2	3
72.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	ढहकोला
73.	—सम—	अजरोंदा
74.	—सम—	आंछोड़
75.	—सम—	बादशाहपुर
76.	—सम—	चान्दपुर
77.	—सम—	छैनसा (कन्या)
78.	—सम—	बदसिया
79.	—सम—	हरीजन बस्ती
80.	—सम—	सैक्टर-22, फरीदाबाद
81.	—सम—	शाहुपरा
82.	—सम—	सैक्टर-7, फरीदाबाद
83.	—सम—	ऊंचा गांव
84.	—सम—	बन्धाड़ी
	गुड़गांव	
85.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	रिवासन
86.	—सम—	जटौला
87.	—सम—	गागड़ोज अलीपुर
88.	—सम—	समसपुर
89.	—सम—	चक्करपुर
90.	—सम—	लाभवास
91.	—सम—	कतारपुर
92.	—सम—	सिकन्दरपुर सीही
93.	—सम—	चान्द
94.	—सम—	माहोली
95.	—सम—	शेख चोख
96.	—सम—	सलीलपुर
97.	—सम—	बास लाम्बी
98.	—सम—	पथरेडी
99.	—सम—	खेडली लाला
100.	—सम—	खेतीयाबास

[श्री राम बिलास शर्मा]

1	2	3
101.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	जोरी साम्पका
102.	—सम—	सिकन्दरपुर गोसी
103.	—सम—	पलड़ा
104.	—सम—	महलाना
105.	—सम—	शेर शाहपुर
106.	—सम—	मैहनीबास
107.	—सम—	कन्है
108.	—सम—	आटारोटा
109.	—सम—	घडोली खुर्द
110.	—सम—	खो
111.	—सम—	दमदमा
112.	—सम—	धानी मालियान
113.	—सम—	गंगोली
114.	—सम—	खबासपुर
115.	—सम—	उचामाजरा
116.	—सम—	खैड़ला
117.	—सम—	मिलकपुर
118.	—सम—	ईस्लामपुर
119.	—सम—	राठीवास
120.	—सम—	सुल्तानपुर
121.	—सम—	अलीमुदीनपुर
122.	—सम—	पहाड़ी
	जीन्द	
123.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	पिमाना
124.	—सम—	गोद
125.	—सम—	भुटानी
126.	—सम—	खांडा
127.	—सम—	डिफैन्स कालोनी
128.	—सम—	पांजूकलां
129.	—सम—	संगतपुरा

1	2	3
130.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	अमरेहड़ी
131.	—सम—	बडोदा (कन्या)
132.	—सम—	खटकड़ (कन्या)
133.	—सम—	आसनकलां
134.	—सम—	शीला खेड़ी
135.	—सम—	डिडवाड़ा
136.	—सम—	पाण्डू पिन्डारा
137.	—सम—	उगराह (कन्या)
138.	—सम—	राजगढ दौधी
139.	—सम—	धुआ (कन्या)
140.	—सम—	पहलवा
141.	—सम—	धनी टेक सिंह
142.	—सम—	खड़क भुरा
143.	—सम—	अलीपुरा
144.	—सम—	पिलथा (कन्या)
145.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	दिनोदा (कन्या)
146.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	शामलोकलां (कन्या)
147.	—सम—	करमगढ़
	करनाल	
148.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	ददलाना
149.	—सम—	अबला जागीर
150.	—सम—	बैडसाल
151.	—सम—	डबरी
152.	—सम—	ढिंगरभाजरा
153.	—सम—	पबाना हसनपुर
154.	—सम—	बदरपुर
155.	—सम—	बासा
156.	—सम—	सन्धीर
157.	—सम—	अमुपुर
158.	—सम—	केहरवाली

[श्री राम बिलास शर्मा]

1	2	3
159.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	सांवर
160.	—सम—	खेड़ा
161.	—सम—	अन्जनथली
162.	—सम—	सांवत
163.	—सम—	कुड़लन
164.	—सम—	जैनपुर सादान
165.	—सम—	कारसा रोड़
166.	—सम—	मूण्ड
167.	—सम—	बडथल
168.	—सम—	शेखपुरा खालसा
169.	—सम—	परवाना
170.	—सम—	जबाला
171.	—सम—	अलावल
172.	—सम—	पुण्डरक
173.	—सम—	महमूदपुर
174.	—सम—	रायपुर जाटान
	कैथल	
175.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	बाता (कन्या)
176.	—सम—	कठबाड़
177.	—सम—	पाई
178.	—सम—	नन्कसनमाजरा
179.	—सम—	सन्तोखमाजरा
180.	—सम—	खरोडी
181.	—सम—	सींठा
182.	—सम—	श्यो माजरा
183.	—सम—	बुडाखेड़ा
184.	—सम—	बीडाबांगड़ा
185.	—सम—	करोड़ा (कन्या)
186.	—सम—	गुसांय
187.	—सम—	पिलनी

1	2	3
188.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	प्योदा
189.	—सम—	तारागढ़
190.	—सम—	सैर
191.	—सम—	वुच्ची
192.	—सम—	वदनारा
193.	—सम—	जाजनपुर
194.	—सम—	मोहना
	कुरुक्षेत्र	
195.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	रत्तगल
196.	—सम—	व्रण
197.	—सम—	मिर्जापुर
198.	—सम—	बीड़माजरा
199.	—सम—	वराड़ा
200.	—सम—	रत्तनडेरा
201.	—सम—	पलवल
202.	—सम—	घमारसी
203.	—सम—	ठील (कन्या)
204.	—सम—	खेड़ी दबलैन
205.	—सम—	अमीन (कन्या)
206.	—सम—	वीड़ वड़तोली
207.	—सम—	हथीरा
208.	—सम—	मुकड़पुर
209.	—सम—	गड़ी गाडली
210.	—सम-	शान्तिनगर
211.	—सम—	लोहारमाजरा
212.	—सम—	सैनी सादान
213.	—सम—	दिवाना
214.	—सम—	खालसा
215.	—सम—	दुलगढ़ गुलढेरा
216.	—सम—	थानेसर (कन्या)

[श्री राम विलास शर्मा]

1	2	3
217.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	फतेहपुर
218.	—सम—	कोलापुर
219.	—सम—	टिरा
	पानीपत	
220.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	बाल जाटान
221.	—सम—	बेसर
222.	—सम—	छाजपुर (कन्या)
223.	—सम—	बिजौल
224.	—सम—	उखलाना (कन्या)
225.	—सम—	बहरामपुर
226.	—सम—	जलमाना
227.	—सम—	झट्टीपुर
228.	—सम—	बलाना
229.	—सम—	मडलौडा (कन्या)
230.	—सम—	नामूण्डा
231.	—सम—	निजामपुर
232.	—सम—	डाहर
233.	—सम—	बापोली
234.	—सम—	काबड़ी
235.	—सम—	जाटल
	रोहतक	
236.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	लाहली (कन्या)
237.	—सम—	गोरावड़ (कन्या)
238.	—सम—	गांगटान
239.	—सम—	खैरड़ी
240.	—सम—	आंवल (कन्या)
241.	—सम—	सुरखपुर

1	2	3
242.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	याकूबपुर
243.	—सम—	महमूदपुर माजरा
244.	—सम—	चान्दी
245.	—सम—	गढ़ी बोहर
246.	—सम—	ईस्माईलपुर
247.	—सम—	वरहाना (कन्या)
248.	—सम—	गढ़ी वल्लम
249.	—सम—	जोन्ठी
250.	—सम—	सिलाना (कन्या)
251.	—सम—	खिडवाली
252.	—सम—	भैणी भाहराजपुर
253.	—सम—	सिंगपुरा खुर्द
254.	—सम—	मनीलाहेड़ी
255.	—सम—	रूड़की (कन्या)
256.	—सम—	मैना (कन्या)
257.	—सम—	रेवाड़ी खेड़ा
258.	—सम—	माजरी (कन्या)
259.	—सम—	बिरनाकताबाद
260.	—सम—	कासण्डा
261.	—सम—	टाण्डाहेड़ी
262.	—सम—	सराय मोराबाद
263.	—सम—	छुड़ानी
264.	—सम—	लोहा खुर्द
265.	—सम—	लुकसर
266.	—सम—	सुण्डयावास
267.	—सम—	नोनोंद
268.	—सम—	भैणी भैरों
269.	—सम—	भैणी सुरजन

[श्री राम विलास शर्मा]

1	2	3
270.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	भिण्डावास
271.	—सम—	भणगैन
272.	—सम—	ददलान
273.	—सम—	रिटौली काबूलपुर
	यमुनानगर	
274.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	कलानौर
275.	—सम—	सुढैली
276.	—सम—	ससौली
277.	—सम—	दौरंग
278.	—सम—	सढौरा
279.	—सम—	तेजली
280.	—सम—	काजीवास
281.	—सम—	गोविन्दपुरा
282.	—सम—	जरावाद
283.	—सम—	दादूपुर
284.	—सम—	पारखपुर
285.	—सम—	लकड़
286.	—सम—	छाप्पर
287.	—सम—	शादीपुर
288.	—सम—	माहरपुर
	सोनीपत	
289.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	पुठी
290.	—सम—	कोहला
291.	—सम—	गंगाना (कन्या)
292.	—सम—	अनायत
293.	—सम—	बाली (ब्राह्मण)
294.	—सम—	कथूरा
295.	—सम—	पबनेरा

1	2	3
296.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	बजाना कलां
297.	—सम—	गन्नौर मण्डी
298.	—सम—	अटायल
299.	—सम—	चिरसमी
300.	—सम—	दुबेढ़टा
301.	—सम—	ललहेंडी कलां
302.	—सम—	शाहपुरतगा
303.	—सम—	सरडाना
304.	—सम—	शोटी
305.	—सम—	एम०टी० सोनीपत
306.	—सम—	ठरू उलेदपुर
307.	—सम—	रेवली
308.	—सम—	कंवाली
309.	—सम—	अलालपुर
310.	—सम—	मसद
311.	—सम—	छतेरा
312.	—सम—	थानाकलां
313.	—सम—	बोहला
314.	—सम—	किडोली पहलादपुर
315.	—सम—	बिसवांमील
316.	—सम—	थाना खुर्द
317.	—सम—	कुराड़
318.	—सम—	सोनीपत मण्डी
319.	—सम—	सेहरी
320.	—सम—	असदपुर नान्दनौर
321.	—सम—	सिकन्दरपुर माजरा
322.	—सम—	गामड़ी
323.	—सम—	महलाना (कन्या)
324.	—सम—	दिवाना
325.	—सम—	सिरसाद
326.	—सम—	खेड़ी मनाजाट

[श्री राम बिलास शर्मा]

1	2	3
	रिवाड़ी	
327.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	वरौली कलां
328.	—सम—	जैतपुर
329.	—सम—	मिरपुर
330.	—सम—	जी०टी० डहिना
331.	—सम—	चिहड़
332.	—सम—	तिहारा
333.	—सम—	टींट
334.	—सम—	परखोतमपुर
335.	—सम—	दखोड़ा
336.	—सम—	खलेटा
237.	—सम—	ममरियाअहीर
338.	—सम—	धानी कोलाना
339.	—सम—	बलवारी
340.	—सम—	मोहिदीपपुर
341.	—सम—	बावल (कन्या)
342.	—सम—	डी०पी० पुरा
343.	—सम—	सुठानी
344.	—सम—	बोलनी (कन्या)
345.	—सम—	रामगढ़
346.	—सम—	मनेठी
347.	—सम—	एम०एम० बालखी
348.	—सम—	बोलियाबास
349.	—सम—	सान्जरपुर
350.	—सम—	जाटसाना (कन्या)
351.	—सम—	मस्तापुर
352.	—सम—	सुठाना
353.	—सम—	दामलबास
354.	—सम—	झाबूआ
355.	—सम—	धामलावास

1	2	3
356.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	भोट वास अहीर
357.	—सम—	पिथनवास
358.	—सम—	चौकी नं०-2
359.	—सम—	निमौठ
360.	—सम—	वास बिटेड़ी

Supply of Water Through W.J.C.

***915. Smt. Kartar Devi :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) the cusecs of water supplied to district Rohtak through Western Yamuna Canal for the irrigation purpose before the formation of Haryana State together with the cusecs of water being supplied at present; and

(b) the number of days in a month the canal water is supplied in the irrigated area through Western Yamuna canal and Bhakra Irrigation system, seperately ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) वर्तमान जिला रोहतक के क्षेत्र को हरियाणा बनने से पूर्व (अक्तूबर 1966) पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई के लिए 767.93 क्यूसिक्स पानी दिया जाता था। इस समय (मई 1998) जिला रोहतक को सिंचाई के लिए 790.90 क्यूसिक्स पानी दिया जा रहा है।

(ख) (i) पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली में चार ग्रुप हैं तथा सभी ग्रुपों की पहली प्राथमिकता में आने वाली नहरों में 32 दिनों की अवधि में आठ दिन पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। दूसरी, तीसरी तथा चौथी प्राथमिकता की नहरें यमुना नदी में फालतू पानी उपलब्ध होने पर चलती हैं।

(ii) भाखड़ा प्रणाली की नहरों को तीन ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है। दो ग्रुपों की प्रथम प्राथमिकता की नहरें 24 दिन की अवधि में आठ दिन चलती है। तीसरे ग्रुप में नहरें प्रथम प्राथमिकता में 32 दिनों की अवधि में 16 दिन चलती हैं।

Number of Buses Purchased

***909. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state the total number of new buses purchased by the Haryana Roadways during the period from 1991 to 1998 to-date togetherwith the depot-wise allotment thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुज्जर) : सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

1. वर्ष 1991 से 1998 अब तक की अवधि के दौरान कुल नई खरीद की गई बसों की संख्या—3607

2. डिपो अनुसार आबंटन निम्न प्रकार से है :—

क्र० संख्या	डिपो का नाम	आबंटित बसों की संख्या
1.	अम्बाला	220
2.	चण्डीगढ़	251
3.	करनाल	195
4.	जीन्द	203
5.	कैथल	155
6.	सोनीपत	202
7.	यमुनानगर	216
8.	देहली	249
9.	कुरूक्षेत्र	178
10.	पानीपत	93
11.	गुड़गांव	213
12.	रोहतक	200
13.	हिसार	203
14.	रिवाड़ी	198
15.	भिवानी	139
16.	सिरसा	173
17.	फरीदाबाद	215
18.	फतेहाबाद	170
19.	चरखी दादरी	100
20.	नारनौल	34
	कुल	**3607**

Widening of the Syphon of Juan Village

***795. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the size of syphon provided for draining out the rainy water at village Juan in district Sonipat is inadequate to discharge the accumulated water; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to widen the size of aforesaid syphon.

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Number of Electricity Connections in the State

***801. Shri Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of electric connections in Agricultural sector in the State as on 30-4-96, 31-3-97, 31-3-98 and to-date;

(b) the number of applications for elctricity connections to tubewells lying pending with electricity Board in the State as on 30-4-96 and at present; and

(c) the number of beneficiaries under slab system as on 31-5-1996; and at present in Rewari, Mohindergarh and Bhiwani districts, separately ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : (a, b & c) :— Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The total number of electric connections in Agricultural sector in the state are :

As on 30-4-96	3,75,903
As on 31-3-97	3,66,540
As on 31-3-98	3,65,043
As on 30-11-98	3,60,695

(b) Number of applications pending for elctricity connections to tubewells are :

As on 30-4-96	72,207
As on 30-11-98	76,142

(c) The number of beneficiaries under slab system are as follows :

Name of District	No. of beneficiaries as on 31-5-96	No. of beneficiaries as on 30-11-98
Rewari	23,663	21,542
Mohindergarh	25,758	23,547
Bhiwani	13,449	10,722

Number of Dropsy Cases in the State

***806. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any case of dropsy was detected in the State due to the consumption of adulterated Sarson Oil during the year 1998; if so, the number thereof together with the action taken against the persons involved therein.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : वर्ष 1998 के दौरान राज्य में मिलावटी सरसों के तेल से डरापूसी के 18 केस हुए।

इन केसों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही :

सरसों के तेल के 35 नमूनों में आरजीमोन तेल की मिलावट पाई गई। इन सभी 35 केसों के विरूद्ध अदालत में मुकदमे दायर किए गए। अदालत में झज्जर जिले के दो मुकदमों के फैसले हुए। प्रत्येक दोषी को पी०एफ०ए० एक्ट के अधीन 500 रुपये जुर्माना किया गया तथा माननीय न्यायालय के उठने तक जुडिशियल कस्टडी में रहने की सजा दी गई।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Purchase of Gunny Bags

53. Shri Dev Raj Dewan : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether the Haryana Federation of Cooperative Sugar Mills made an agreement with M/s Union General Company, Calcutta on 29-08-96 for the purchase of Gunny Bags on fixed rates; if so, the rates thereof; togetherwith the reasons for altering the previous purchase policy at GTA rates;

(b) whether the benefit of the exemption of excise duty on the jute and jute goods passed on to the federation by the aforesaid firm w.e.f. 1-3-97; if not, the reasons thereof;

(c) the details of excise MODVAT reclaim on Gunny Bags by the Coop. Sugar Mills for the crushing seasons 1995-96, 1996-97 and 1997-98;

(d) the per bag landed cost of UP Federation of Cooperative Sugar Mills, the Saraswati Sugar Mill, Yamunanagar and Piccadily Sugar Mills, Bhadson for the crushing season 1996-97; and

(e) whether the Federation has suffered any loss due to the change in purchase policy; if so, the details thereof together with the action taken against the officials held responsible in this regard ?

सहकारिता मन्त्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) जी हां, श्रीमान, हरियाणा राज्य सहकारी मिल्ज प्रसंघ लि०, चण्डीगढ़ द्वारा पटसन की बोरियों की खरीद के लिए फिक्स रेट यानि 2991 रुपए प्रति सौ बोरियां जिसमें उत्पाद शुल्क, सैस, किराया, बीमा तथा सी०एस०टी० फार्म "सी" के विरुद्ध तथा एफ०ओ०आर० सम्मिलित थे पर 29-08-96 को मैसर्ज यूनियन जनरल कम्पनी, कलकत्ता के साथ एक इकरारनामा किया गया। संयुक्त खरीद कमेटी ने पटसन की बोरियां जी०टी०ए० रेट की बजाय फिक्स रेट 2991 रुपए पर खरीद करने का फैसला निम्नलिखित कारणों से किया :—

1. जी०टी०ए० रेट पर पटसन की बोरियों को खरीदने से चीनी मिलों को समय पर सप्लाई प्राप्त होने में दिक्कतें आती हैं।
2. जी०टी०ए० रेट में क्योंकि कीमतें एफ०ओ०आर० कलकत्ता की होती हैं अतः कानूनी तौर पर कलकत्ता से ट्रांसपोर्टेशन की सारी जिम्मेदारी एवं जोखिम शुगर मिलों का होता है।
3. पिछले दस माह का औसतन जी०टी०ए० मूल्य 26.07 रुपए प्रति बैग था तथा वह पिछले तीन चार माह से इस औसतन रेट से उत्तरोतर बढ़ता जा रहा था।
4. वर्ष 1995-96 में हरियाणा की पांच मिलों की औसतन पटसन की बोरियों की पहुंच कीमत निम्न प्रकार थी :—

करनाल	29.28 रुपए प्रति बैग
महम	29.78 रुपए प्रति बैग
पलवल	30.38 रुपए प्रति बैग
पानीपत	29.38 रुपए प्रति बैग
शाहबाद	30.49 रुपए प्रति बैग

जून, 1996 के जी०टी०ए० रेट 27.03 रुपए प्रति बैग के आधार पर तथा रेलवे भाड़ा जो उस समय था तथा साथ में सभी करों के साथ एफ०ओ०आर० हरियाणा शुगर मिल्ज प्रति बैग की कीमत रुपए 31.14 आंकी गई।

(ख) भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 4/97 दिनांक 01-03-97 द्वारा पटसन की बोरियों पर एक्साईज ड्यूटी की छूट प्रदान कर दी थी। बोरियों के व्यापारियों ने 01-03-97 से पटसन तथा पटसन सामग्री पर अक्साईज ड्यूटी की छूट का फायदा सहकारी चीनी मिलों को 1996-97 के दौरान नहीं दिया क्योंकि पटसन की बोरियों की खरीद निश्चित रेट पर जिसमें करों व शुल्कों के घटने बढ़ने से दरें परिवर्तित नहीं होंगी, के आधार पर की गई थी।

(ग) सहकारी चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में बोरियों की खरीद पर एक्साईज ड्यूटी माडवेट की प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार है :—

[श्री नरबीर सिंह]

राशि रुपयों में

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	1995-96	1996-97
1.	पानीपत	19,250.18	1,87,310.00
2.	रोहतक	48,959.00	3,40,781.64
3.	करनाल	4,55,836.00	5,15,567.00
4.	सोनीपत	2,46,417.30	2,07,894.73
5.	शाहबाद	5,64,686.10	6,18,524.00
6.	जीन्द	2,26,153.16	3,90,679.62
7.	पलवल	2,52,591.44	295,613.66
8.	महम	87,279.40	2,20,869.00
9.	कैथल	2,85,797.00	4,13,643.00
10.	भूना	शून्य	2,32,140.00
	जोड़	21,86,969.58	34,23,022.65

1997-98

भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 4/97 दिनांक 01-03-97 द्वारा पटसन की बोरियों पर एक्साईज डयूटी में छूट दे दी थी। इसलिए उसके बाद मिलों ने कोई माडवेट क्लेम प्राप्त नहीं किए।

(घ) वर्ष 1996-97 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्ज संघ लखनऊ, सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर तथा पिकाडिली शुगर मिल भादसों द्वारा खरीद की गई प्रति बोरी की पहुंच कीमत भेजने बारे दूरभाष तथा फैक्स द्वारा प्रार्थना की गई थी। पिकाडिली शुगर मिल, भादसों के अतिरिक्त शेष दोनों मिलों से सूचना प्राप्त हुई जो इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	मिल का नाम	वर्ष	कीमत प्रति बोरी
1.	उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्ज कारखाना, लखनऊ	1996-97	25.52 जमा भाड़ा (लगभग 2.25 रुपए से 2.50 रुपए प्रति बोरी)
2.	सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर	1996-97	24.94 रुपए

(ङ) प्रसंघ को निम्नलिखित कारणों से क्रय नीति में परिवर्तन से कोई आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ी :—

1. वर्ष 1995-96 में जी०टी०ए० पर खरीद की गई बोरियों की मिल तक पहुंच की कीमत 30 रुपए प्रति बोरी से अधिक पड़ रही थी।
2. वर्ष 1996-97 में जब पटसन की बोरियां सभी करों सहित खरीदी गई तब प्रति बोरी कीमत 30 रुपए से कम यानि 29.91 रुपए प्रति बोरी थी। उस समय का जी०टी०ए०

रेट 27.03 रुपए प्रति बोरी आंका गया था। जो उस समय के रेलवे भाड़ा तथा हरियाणा राज्य में प्रचलित सभी करों सहित प्रति बोरी मिल पहुंच रु० 31.14 पैसे बनता था जो संयुक्त खरीद कमेटी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक था।

Sugar Exported by Sugarfed

54. Shri Dev Raj Dewan : Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether the Haryana Sugarfed has exported upto 100 ICUMSA sugar from the Cooperative Sugar Mills of Shahabad, Karnal, Meham and Rohtak through M/s Sara International during the period from March, 1997 to July, 1997, if so, the rates at which it was exported and the criteria adopted for the purpose;

(b) whether it is a fact that the rates of exporting of Sugar by Bhadson Sugar Mill through M/s Satnam Overseas, Karnal Coop. Sugar Mill is higher than the rates of exporting of sugar by Sugarfed during the said period if so, the reasons thereof;

(c) whether it is also a fact that the aforesaid export deal was cancelled midway on 23-07-97 by Haryana Sugarfed, if so, the reasons thereof, and

(d) whether the Shahabad Coop. Sugar Mill exported 7 racks of Sugar against 5 racks as approved by the Board of Directors of the Mill; if so, the reasons thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) जी हां, श्री मान, मार्च से जुलाई, 1997 के दौरान मैसर्ज सारा इन्टरनैशनल के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों द्वारा चीनी का निर्यात किया गया है। करनाल चीनी मिल ने मैसर्ज सारा इन्टरनैशनल के माध्यम से कोई निर्यात नहीं किया। निर्यात की गई चीनी की मात्रा एवं दरों का ब्यौरा अनुबन्ध "क" पर संलग्न है।

चीनी का यह निर्यात भारत सरकार के द्वारा निर्धारित एवं निर्देशत नीतियों के अन्तर्गत ही किया गया है। निर्यात की गई चीनी का मूल्य घरेलू चीनी के मूल्यों की दरों से अधिक है। मिलों ने चीनी के निर्यात से लाभ कमाया है।

(ख) जी नहीं, श्री मान, पिकाडली शुगर मिल भादसों (करनाल) द्वारा निर्यात की गई चीनी का मूल्य 1270 रुपये प्रति क्विंटल (363 प्रति टन यू०एस० डालर) सहकारी चीनी मिलों से कम है, क्योंकि पिकाडली चीनी मिल ने चीनी का सीधा निर्यात किया है, जबकि सहकारी चीनी मिलों ने चीनी का निर्यात एजैंट के माध्यम से किया है जिसके कारण अपेडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के पक्ष में की जाने वाली पांच लाख रुपये की धरोहर राशि, भारत व पाकिस्तान द्वारा अधिकृत निरीक्षण हेतु खर्चा, आवकारी औपधारिकताओं के खर्चे निर्यात की जाने वाली चीनी के

[श्री नरबीर सिंह]

आदेश प्राप्त करवाना, रेलवे से रेलवे वैगन की व्यवस्था करवाना, एल०सी० नैगोशिएट करवाना (सहकारी चीनी मिलों ने निर्यात की गई चीनी का मुल्य तुरन्त प्राप्त किया जबकि पिकाडली शुगर मिल को निर्यात की गई चीनी का भुगतान काफी समय बाद मिला) पर खर्च नहीं करना पड़ा। इसके इलावा चीनी प्रसंघ ने एजैंट से 25 लाख रुपया धरोहर के रूप में भी जमा करवाया, जो चीनी प्रसंघ के पास अप्रैल, 1997 से सितम्बर, 1997 तक जमा रही, चीनी प्रसंघ ने इसके ऊपर भी ब्याज प्राप्त किया। उक्त समस्त खर्चों का आर्थिक प्रभाव लगभग 50 रुपये से 60 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है। इस प्रकार सहकारी चीनी मिलों द्वारा प्राप्त शुद्ध मूल्य पिकाडली चीनी मिल द्वारा पाकिस्तान को निर्यात की गई चीनी के मूल्य से कम नहीं है। हरियाणा सहकारी चीनी मिल्ज़ संघ ने निर्यात का अनुबन्ध 25-3-97 को लिया जबकि करनाल चीनी मिल ने इसका निर्णय 23-5-97 को अर्थात दो महीने बाद लिया। चूंकि चीनी के मूल्य प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं तथा निर्यात अलग अलग समय पर किया गया है इसलिए करनाल मिल से तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं, यह सच नहीं है कि हरियाणा चीनी मिल प्रसंघ द्वारा 23-7-97 को बीच में ही चीनी निर्यात का सौदा रद्द कर दिया गया। सरकार ने चीनी निर्यात के सौदे को कुछ समय के लिए रोकने की इच्छा व्यक्त की थी।

सरकार के आदेश के अनुपालना में इसे रोक दिया गया था तथा इसी बीच निर्यात के आदेश की वैधता का समय समाप्त हो गया।

(घ) यह ठीक है कि शाहाबाद सहकारी चीनी मिल ने चीनी के सात "रैक" का निर्यात किया। निर्देशक मण्डल की बैठक के प्रस्ताव में रैक की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। 1996-97 में उत्पादित की गई चीनी के निर्यात के लिए निर्देशक मण्डल ने सैद्धांतिक तौर पर नीति का अनुमोदन किया था तथा यह इच्छा व्यक्त की थी कि चीनी का निर्यात इस प्रकार किया जाता रहे जिससे कि चीनी मिल पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े।

अनुबन्ध - "क"

क्र० सं०	मिल का नाम	मात्रा मी० टन में	डिस्पैच माह	दर प्रति क्विंटल (रुपये)	मिलों के घरेलू औसत मूल्य 1997-98	मिलों के घरेलू औसत मूल्य 1996-97	निर्यात से प्राप्त कुल धन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-5)	10 (7-6)	11 (2+8)	12 (2+9)
1.	शाहबाद	1785.6	अप्रैल, 97	1205	1162	1215	1385	223	170	3981888	3035520
2.	शाहबाद	1757.7	अप्रैल, 97	1205	1162	1215	1385	223	170	3919671	2998090
3.	शाहबाद	1794	मई, 97	1215	1332	1215	1395	63	180	1130220	3229200
4.	रोहतक	1766.4	मई, 97	1215	1239	1237	1383	144	146	2543616	2578944
5.	शाहबाद	1794	मई, 97	1215	1332	1215	1395	63	180	1130220	3229200
6.	रोहतक	1794	जून, 97	1235	1365	1237	1403	38	166	681720	2978040
7.	शाहबाद	1794	जून, 97	1215	1341	1215	1395	54	180	968760	3229200
8.	महम	1794	जून, 97	1215	1314	1193	1375	61	182	1094340	3265080
9.	शाहबाद	1794	जुलाई, 97	1250	1304	1215	1430	126	215	2260440	3857100
10.	शाहबाद	1738.8	जुलाई, 97	1250	1304	1215	1430	126	215	2190888	3738420
										19901763	32128794

Number of Schools Upgraded

55. Shri Anil Vij : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise number of schools, if any, upgraded from Primary to Middle, Middle to High and High to 10+2 in the State during the period from Feb., 1998 to-date; and

(b) the number of new Schools and Colleges, if any, opened in the State since the formation of this Government ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(क) फरवरी, 1988 के बाद किसी भी स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

(ख) इस सरकार के बनने के पश्चात 21 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गए। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में 6 नये निम्नलिखित महाविद्यालय खोले गए :

1. राजकीय महाविद्यालय, कृष्णा नगर, नारनौल।
2. राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला छावनी।
3. राजकीय महाविद्यालय, बोंद कलां।
4. राजकीय महाविद्यालय, सिवानी।
5. राजकीय महिला महाविद्यालय, फतेहाबाद।
6. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, नारनौल।

राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, नारनौल यद्यपि खोल दिया गया है परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक परिषद्, जयपुर के अनुमोदन के अभाव में वर्ष 1998-99 में चालू नहीं हो पाया है। वर्ष 1999-2000 से यह आरम्भ हो जाना सम्भावित है। इसी अवधि में सरकार ने राजकीय महाविद्यालय, करनाल तथा महेन्द्रगढ़ के दो महिला विंगो को भी पूर्ण राजकीय महिला महाविद्यालयों में परिवर्तित किया। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार ने दो निजी महाविद्यालयों संजय कालेज, अटेली, (रिवाड़ी) तथा विवेकानन्द कालेज नांगल चौधरी को सरकारी नियंत्रण में लिया।

Number of Beneficiaries under Old Age Pension Scheme

56. Shri Anil Vij : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the district-wise number of beneficiaries and the amount disbursed under the old Age Pension scheme in the State during the last five years ?

समाज कल्याण मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

पिछले पांच वर्षों में जिलावार लाभपात्रों की संख्या तथा वृद्धावस्था पैंशन योजना राज्य में वितरित की गई राशि का ब्यौरा। (रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	31-3-95 को लाभ पात्रों की संख्या	1994-95 में वितरित की गई राशि	31-3-96 को लाभ पात्रों की संख्या	1995-96 में वितरित की गई राशि	31-3-97 को लाभ पात्रों की संख्या	1996-97 में वितरित की गई राशि	31-3-98 तक लाभ पात्रों की संख्या	1997-98 में वितरित की गई राशि	20-1-99 तक लाभ पात्रों की संख्या	1998-99 में वितरित की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	39,113	708.02	50,004	517.20	45,913	552.63	48,223	538.18	45,657	417.42
2.	यमुनानगर	29,190	539.25	32,378	364.09	30,018	366.48	32,042	356.50	29,978	274.52
3.	कुरुक्षेत्र	24,491	444.50	28,020	308.16	25,626	303.77	26,980	295.25	24,260	221.26
4.	कैथल	31,919	578.00	37,153	397.67	33,214	405.75	34,039	386.05	32,458	327.42
5.	करनाल	35,698	647.23	39,983	442.62	37,381	455.56	37,738	437.97	34,902	325.32
6.	पानीपत	22,380	409.84	26,115	383.48	24,723	296.32	25,635	284.20	23,999	215.64
7.	सोनीपत	50,999	910.97	58,616	626.05	55,402	641.70	59,018	633.64	56,013	496.61
8.	फरीदाबाद	34,891	640.55	45,064	473.79	42,486	517.85	43,101	492.25	40,067	408.61
9.	गुड़गांव	45,071	829.98	49,466	550.06	46,242	561.19	49,864	550.62	46,976	476.73

[डॉ० कमला वर्मा]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	रिवाड़ी	24,981	464.97	30,604	332.75	28,716	347.35	30,225	338.17	28,225	259.88
11.	नारनौल	32,952	609.55	41,366	428.02	39,259	469.08	39,196	452.35	36,428	333.32
12.	जींद	37,455	687.80	43,161	466.90	40,760	486.01	42,689	481.28	40,657	411.63
13.	रोहतक	74,126	1358.29	81,981	929.62	78,011	945.30	43,091	781.03	41,090	418.78
14.	झज्जर	-	-	-	-	-	-	39,420	617.03	37,818	345.10
15.	भिवानी	42,158	772.17	53,473	559.43	51,849	626.84	55,196	875.59	52,234	479.61
16.	हिसार	74,256	1358.24	90,015	982.78	84,489	1022.79	57,067	380.51	52,219	484.72
17.	फतेहाबाद	-	-	-	-	-	-	31,907	123.40	30,092	304.82
18.	सिरसा	25,906	462.37	33,892	351.21	32,016	389.14	34,236	157.73	33,480	328.53
	कुल योग	**6,24,886**	**11,421.73**	**7,41,291**	**8,013.83**	**6,96,104**	**8,387.76**	**7,29,697**	**8,182.50**	**6,86,553**	**6,529.92**

Installation of New Sub-Stations

57. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the number of new power sub-stations installed and the number of sub-stations augmented, since the formation of the present Government togetherwith names thereof; and

(b) the number of sub-stations to be installed or augmented by the year 2000 togetherwith locations thereof ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :--

(a) 25 No. New Sub-stations have been commissioned since the formation of present Government.

NEW SUB-STATIONS

220KV	1. Nissing	2. Rohtak	
132KV	3. Sagga	4. Munak	5. Ismailabad
	6. Chhajpur		
66KV	7. Hathin	8. Chandpur	9. I.A. Ambala Cantt.
33KV	10. Alewa	11. Nehla	12. Sewan Gate Kaithal
	13. Barsat	14. M.I.E. Bhadurgarh	15. Mehmara
	16. Aterna	17. Bhatghaon	18. Dharamgarh
	19. Dwarka	20. Jassorkheri	21. Bhiwani Rohila
	22. Cross Road Ambala Cantt.	23. MDU Rohtak	24. Teontha
	25. Model Town Rewari		

123 No. Sub-stations have been augmented :

AUGMENTATIONS

220KV	1. Pehowa	2. Bhiwani	3. Sirsa
	4. Nissing	5. Pehowa	6. Bhiwani
	7. I.A. Hisar	8. Kaithla	9. Sirsa
	10. PTPS	11. Sonipat	12. Palwal
132KV	13. Rohtak	14. Nilokheri	15. Jiwan Nagar
	16. Uklana	17. Tohana	18. Bhiwani
	19. Hansi	20. Cheeka	21. Rai
	22. Kaithla	23. Kaninakhas	24. Mohindergarh

[Shri Bansi Lal]

	25. Miran	26. Safidon	27. Fatehabad
	28. Chandoli	29. Jind (New)	30. Bahadurgarh
	31. Siwan	32. Thana	33. Madhuban
	34. Smalkha	35. Bhore	36. Ateli
	37. Jui	38. Hansi	39. Sirsa
	40. Sonipat	41. Kalanaur	42. Kaninakhas
	43. Gohana Road Panipat	44. Jhajjar	45. Chhajpur
	46. Bhiwani	47. Badhra	48. Chandoli
	49. Ratia	50. Munak	
66KV	51. FCI Faridabad	52. A3 Palla	53. 10A Gurgaon
	54. Palwal	55. Sadopur	56. Kesri
	57. IOC Ambala Cantt.	58. Dharuhera	59. Hyderabad Asbestos
	60. Adhoya	61. A2 Faridabad	62. Chormastpur
	63. Maruti Gurgaon	64. Ford Faridabad	65. Babain
	66. Jansui	67. Hodal	68. Mehrauli Road Gurgaon
	69. Basantpur	70. Shahbad	71. Dhauj
	72. Nuh	73. A5 Faridabad	
33 KV	74. Rajgarh Road Hisar	75. Nautch	76. Siwani
	77. Sasrauli	78. Kahanaur	79. Lukhi
	80. Ajrana	81. Sanauli Road, Panipat	82. Jamba
	83. RD-0	84. Mastgarh	85. Daba
	86. Behal	87. Meerut Road, Karnal	88. Pali/Gothra
	89. Ferozepur Jhirka	90. Badopal	91. Kadma
	92. Nakipur	93. Bhawani Khera	94. Engg. College, Murthal
	95. Lad	96. I.A. Karnal	97. Munak

	98. Jindal Metal, Hisar	99. Beholi	100. Kharkhoda
	101. IA Panipat	102. Mathana	103. Sampla
	104. IDC Rohtak	105. Vidyut Nagar, Hisar	106. Mundiakhera
	107. Sanjarwas	108. Ram Nagar	109. Mehmara
	110. Mundhal	111. Badopal	112. Madho Singhana
	113. KU Kurukshetra	114. Punhana	115. Teliwara
	116. Cross Road Ambala Cantt.	117. Kutail	118. Madho Singhana
	119. Larsoli	120. REC Kurukshetra	121. MIE Bahadurgarh
	122. Newal	123. Ram Nagaria	

(b) 93 No. New sub-stations are proposed to be commissioned by 2000.

220 KV	1. Tepla	2. Yamuna Nagar	3. Cheeka
	4. Sonipat	5. Bajghera	6. Palla
	7. Pali	8. Mohindergarh	9. Fatehabad
132KV	10. Pipli	11. Malikpur	12. Dangli
	13. Pai	14. Padla	15. Chakuladana
	16. Kangthli	17. Newal	18. Jalmana
	19. Israna	20. Kundli	21. Harsana
	22. Murthal	23. Mundiakhera	24. Pali/Gothra
	25. IA Hisar (27/28)	26. Arya Nagar Hisar	27. Sampla
	28. Sikandarpur	29. Ellenabad	30. Madho Singhana
	31. Kheri Taloda	32. Loharu	33. Tosham
	34. IA Bhiwani		
66 KV	35. IA Ambala Cantt.	36. Barnala	37. Mulana
	38. Mohra	39. Mansa Devi Panchkula	40. Kalka
	41. Jathiana	42. Bhore-kalan	43. Sector 40/45 Gurgaon
	44. Sector 33/ 34 Gurgaon	45. Sector 9, Gurgaon	46. Sector 55/56 Gurgaon

[Shri Bansi Lal]

	47. Punhana	48. Hassanpur	49. Chhainsa
	50. Green Field Faridabad	51. Sector 12/20 Faridabad	52. Pirthala
	53. Sector 23-A, Gurgaon	54. Allawalpur	
33KV	54. Teontha	56. Kawartan	57. Jakholi
	58. Biana	59. Uplana	60. Kohand
	61. G. T. Road Panipat	62. Assandh Road Panipat	63. Diwana
	64. Kutani Road Panipat	65. Butana	66. Barota
	67. Kewra	68. Khanpur Kalan	69. Garhi Mahasar
	70. Dablana	71. Bawania	72. Model Town Rewari
	73. Khushpura	74. Mangali	75. Sadhanwas
	76. Barwala Road Hansi	77. Daryapur	78. Ganda
	79. Keharwala	80. IA Sirsa	81. Shahindawali
	82. Rasulpur Ther	83. Odhan	84. Singhana
	85. Kheri Sherkhan	86. Bhana	87. Balu
	88. Morewala	89. Devrala	90. MDU Rohtak
	91. Surya Roshni Rohtak	92. Jassorkheri	93. Jahajgarh

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

AUGMENTATIONS

89 No. Sub-stations are proposed to be augmented :

220 KV	1. Panchkula	2. Pehowa	3. Nissing
	4. PTPP Panipat	5. Sonipat	6. Palwal
	7. IA Hisar	8. Sirsa	9. Rohtak
132 KV	10. Pinjore	11. Ismailabad	12. Bhore
	13. Pehowa	14. Thana	15. Pundri
	16. Sewan	17. Indri	18. Chandoli

	19. Munak	20. Chhajpur	21. Gohana
	22. Ateli	23. Mohinder-garh	24. Ratia
	25. Beer	26. Uklana	27. Rania
	28. Sirsa	29. Narwana (New)	30. Badhra
	31. Digawan Jattan	32. Jhajjar	33. Bahadurgarh
	34. Tohana		
66 KV	35. Chandpur	36. Nuh	37. Ford
	38. Hodal	39. Dhauj	
33 KV	40. Dhand	41. RECK	42. KU Kurukshetra
	43. Thana	44. Padla	45. Sewan Gate Kaithal
	46. Gheer	47. Ram Nagar	48. Kutail
	49. Israna	50. Kabri	51. Barsat
	52. Kharkhoda	53. HSIDC Kundli	54. Suraj Steel Sonipat
	55. Mini Sectt. Sonipat	56. Tajpur	57. Begga
	58. Kalyana	59. Partap Steel Faridabad	60. Chhainsa
	61. Nizampur	62. Jharthal	63. Mundia Khera
	64. Jharoda	65. Barwala	66. Bhatla
	67. Arya Nagar Hisar	68. Mundhal	69. Bhattu Kalan
	70. Begu	71. Sikandarpur	72. Ram Nagaria
	73. Nathu Sari	74. Kalanwali	75. Ganga
	76. Ding	77. Bahudin	78. Ramrai/ Bibipur
	79. Uchana	80. Dhanoda	81. Alewa
	82. Lohani	83. Lad	84. Sanjarwas
	85. Issarwal	86. Bahadurgarh	87. MIE Bahadurgarh
	88. Ding	89. Gheer	

Teachers of C.B. High School, Ambala Cantt.

58. Shri Anil Vij : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that teachers of C.B. High School, Ambala Cantt. were absorbed in the Education Department, Haryana on 5-2-1997; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give selection grade to the teachers as referred to in part (a) above in pursuance of the judgement of the Hon'ble High Court in C.W.P. No. 4550/80 ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) सी०बी० उच्च विद्यालय, अम्बाला छावनी के अध्यापक दिनांक 5-2-1977 से शिक्षा विभाग के नियंत्रण में लिये गये थे न कि 5-2-1997 से।

(ख) अभी मामला कोर्ट के विचाराधीन है, क्योंकि सी०डब्ल्यू०पी० नं० 4550/1980 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा एल०पी०ए० नं० 1341 ऑफ 1991 दायर की हुई है जिसका निर्णय अपेक्षित है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

11.00 बजे **श्री ओम प्रकाश चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है that has been disallowed.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे आपसे उम्मीद है, आपने यह फर्रा भेज दिया लेकिन मैं आपसे निवेदन तो कर सकता हूँ। यह एक बड़ा ही अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं लीडर ऑफ दि हाऊस ने आज एक सवाल के जवाब में कहा है कि इसमें विभाग की तरफ से कोताही हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बहुत घटनाएं घटी हैं। आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं और न ही राज नेता सुरक्षित हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मुद्दा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सवाल पर आधे घंटे की चर्चा करवा दें तो अच्छा होगा क्योंकि यह सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि दिन-प्रतिदिन प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा तो नहीं होगी जब गवर्नर एड्रैस पर बहस होगी तब आप भी बोल लेना और सरकार भी उसका जवाब दे सकती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय तो हम बोलेंगे लेकिन आप इस सवाल पर आधे घंटे की चर्चा के लिए परमिशन दें।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए अपनी बात कह लेना।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। रिवाड़ी और धारूहेड़ा के पास कई कॉलोनियां बन गई हैं वहां पर कोलोनाईजर इललीगल कोलोनाईजेशन कर रहे हैं

जिससे वहां पर स्लम पैदा हो रहा है इसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। उन कोलोनाइज़र्ज के पास कोई लाईसैन्स भी नहीं है।

Mr. Speaker : Your Calling Attention notice has been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई प्रस्ताव लाये तो भी आप उसको नहीं मानते। मेरा एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके अलावा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के रिवाड़ी में रिवाड़ी शहर के पास कई कालोनियां हैं, वहां पर ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। उन कालोनियों में पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से मलेरिया और दूसरी बीमारियां फैलने का खतरा है। मैंने इस बारे मे डी०सी० साहब से भी बात की थी लेकिन इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही बिना लाईसैन्स के कोलोनाईजर वहां पर कोलोनाईजेशन को बढ़ा रहे हैं।

Mr. Speaker : Please listen to me. That has also been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : इसका मतलब तो यह है कि इस सदन में आने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सही बात या पब्लिक इंट्रस्ट की बात हो तो वह भी डिसअलाऊ हो जाती है। कोई बात ठीक है तो वह भी डिसअलाऊ हो जाती है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैंने भी एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है।

Mr. Speaker : Your calling attention motion regarding disconnection of electricity connection of pump house of Jehangirpur village Distt. Jhajjjar has been sent to the Government for comments.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपका अच्छा मूड देखकर मेरा हौसला बढ़ा है। मेरा पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो आपने डिस अलाऊ कर दिया। लेकिन प्रदेश से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। ऐसा है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से (बिघ्न)

Mr. Speaker : I would request all the Hon'ble members to please listen to Sh. Om Parkash Chautala.

केन्द्र सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से संबंधित मामला

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की तरफ से आज यूरिया खाद पर, चीनी पर, चावल पर, गेहूँ पर बेइन्तहा पैसा बढ़ाया गया है। यह सारी स्टेट का मामला है। संयोग से विधान सभा का सैशन चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में सर्वसम्मति से एक रैजोलयूशन पास किया जाए और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाए कि हरियाणा प्रदेश में तो पहले से ही बहुत बुरी हालत है। देश के किसानों और गरीबों की हालत आज सबसे ज्यादा दयनीय है इसलिए इस वृद्धि को रोका जाए। इस बारे में यूनैनिमसली एक रैजोल्यूशन पास किया जाए। मैं आपसे चाहूंगा कि चूँकि विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है और विधानसभा जब सैशन में हो तो पहले भी ऐसे अहम मुद्दे यूनैनिमसली रैजोल्यूशन द्वारा पास हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक रैजोल्यूशन यूनैनिमसली पास करके केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए कि बढ़ाई गई कीमतें वापस ली जाएं। (विघ्न) मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में एक रैजोल्यूशन को स्वीकृति प्रदान की जाए और इसे केन्द्र सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाए।

श्री अध्यक्ष : तीन मुख्य पार्टियां एच०डी०पी०, बी०जे०पी० और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हैं और तीनों पार्टियां केन्द्र सरकार को समर्थन दे रही हैं इसलिए आप अपने एम०पी० के माध्यम से यह सवाल लोक सभा में उठायें क्योंकि यह मामला केन्द्र से संबंधित है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : सर, यह सवाल पार्टीज का नहीं है, यह हरियाणा प्रान्त के किसानों और हमारे लोगों के हितों का सवाल है यह राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है। यह हरियाणा प्रदेश के हितों से जुड़ा हुआ मामला है इसे आप राजनीतिक कलर क्यों दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे एक अर्ज की है कि यह केन्द्र सरकार से संबंधित है और बेहतर यही होगा कि इस बात को आप लोक सभा में ही उठाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, इस बात पर सारा सदन सहमत होगा। यह तो यूनैनिमस मामला है। यह तो सारे प्रान्त के हितों की रक्षा की बात है।

श्री अध्यक्ष : अगर सभी सदस्य सहमत हों तो मैं सभी पार्टियों के लीडर साहेबान से रिक्वैस्ट करता हूं कि आज सैशन खत्म होने के बाद वे मेरे चैम्बर में आकर मुझ से मिलें। (विघ्न) Please see me in my Chamber after the adjournment of the House.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, सदन में विपक्ष के मान्य नेता श्री चौटाला जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। स्पीकर सर, आप भी जानते हैं कि जब भारत सरकार का बजट अधिवेशन आता है पिछले कई सालों से यानि 1952 से लेकर 1998 तक यह रिवायत रही है कि बजट अधिवेशन से महीना दो महीने पहले डीज़ल , पैट्रोल, बीड़ी सिगरेट सब चीजों के दाम बढ़ाने की परम्परा रही है। इस बार भारत सरकार ने कमाल किया कि डीज़ल का दाम एक रुपया प्रति लीटर घटाया है।(इस समय मेजें थपथपाई गईं) स्पीकर सर, क्या श्री चौटाला जी ही किसानों के शुभचिन्तक हैं, इनको पता होना चाहिए कि किसान डीज़ल से ट्रैक्टर चलाता है, ट्यूबवैल चलाता है, डीज़ल के दाम कम होने से 220 रुपये एक इम पर उसे राहत मिली है, इसलिए एक रैजोल्यूशन यह भी पास करके भारत सरकार को भेजा जाये कि भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। स्पीकर सर, भारत सरकार ने 95 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ाया है। (विघ्न एवं शोर)

चौधरी रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चर्चा की कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से बहुत भारी बोझ आम जनता पर और किसानों पर चीनी के मूल्य बढ़ाकर, यूरिया खाद के मूल्य बढ़ाकर और अन्य जरूरियात की चीज़ों के मूल्यों में वृद्धि करके डाला है। यह कमरतोड़ वृद्धि की है। आपने भी फर्माया कि तीन मुख्य पार्टियां केन्द्र सरकार को बाहरी और अन्दरूनी समर्थन दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी जो सदन के नेता हैं, श्री राम बिलास शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और श्री ओम प्रकाश चौटाला जो भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं तथा विपक्ष के नेता भी हैं, इन सभी से प्रार्थना है कि अगर ये वास्तव में हरियाणा और हिन्दुस्तान की जनता के मद्दगार हैं तो बजाए इस बात को ऐसे ही उजागर करें, ये भारत सरकार पर अपना दबाव डालें कि या तो यह मूल्यवृद्धि वापिस ली जाए अन्यथा हम सरकार से अपना समर्थन वापिस लेते हैं। इस मामले में प्रस्ताव वगैरह पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस मामले में तो सीधे तौर पर एक्शन लेना पड़ेगा। वरना आज हरियाणा प्रदेश की जनता देखने लग रही है और वह इन बातों के लिए हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। श्री राम बिलास शर्मा जी ने चर्चा कर दी कि डीज़ल के भाव में एक रुपया प्रति लीटर के हिसाब से कमी की गई है। (शोर एवं विघ्न) उन्होंने कहा कि ऐसा करके भारत

सरकार ने हरियाणा और हिन्दुस्तान के किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में 5 डालर प्रति गैलन डीजल के भाव में कमी हुई है। इस प्रकार से हरियाणा व हिन्दुस्तान में 4 रुपये प्रति लीटर डीजल के भाव में कमी होनी चाहिए थी। लेकिन एक रुपया प्रति लीटर भाव कम करके हरियाणा व हिन्दुस्तान के किसानों के साथ क्रूर मजाक किया गया है। (विघ्न)

पशुपालन मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनकी कांग्रेस पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तथा उस समय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह और भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर ने बड़ा जोर दिया कि किसानों को दी जा रही सारी सबसिडी को हटाया जाए। (शोर) यहां ये हरियाणा प्रदेश के किसानों के समर्थक बनते हैं और वहां इनके नेता किसानों को दी जाने वाली सारी सबसिडी को खत्म करने का कार्य करते हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, ये वे लोग हैं जो चोर को कहते हैं कि चोरी करो और गांव वालों को कहते हैं कि जागो। (शोर) ये बहरूपिए हैं। (विघ्न)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है और मैंने भी निवेदन किया है कि यह सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजे जिसमें 95 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भाव बढ़ाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया जाए तथा जो डीजल के भाव में कमी की गई है, उस में और कमी करने के लिए अनुरोध किया जाए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा जिक्र आया है इसलिए आप मुझे बोलने के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठिए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Shri Anil Vij may move his motion.

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :–

> "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 28 जनवरी, 1999 को सदन में देने की कृपा की है।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर आकर अपना अभिभाषण दिया है उसके लिए इस विधान सभा के सभी सदस्य राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है कि हर साल विधान सभा का जो प्रथम सत्र बुलाया जाता है उसके प्रथम दिन राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों का, सरकार की भावी योजनाओं के बारे में सदन में आकर अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। यह अभिभाषण आगामी वर्ष में, सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं, उनका एक मीरर है। इस अभिभाषण में आने वाले वर्ष में क्या-क्या कार्य होने हैं उनको देखा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो इस बार का अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने इस सदन में रखा है यह अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि यह न

[श्री अनिल विज]

केवल आगामी योजनाओं की जानकारी देता है बल्कि यह इस ओर भी संकेत कर रहा है कि यह वर्ष इस सदी का अंतिम वर्ष है। हम सन् 2000 में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम नये वर्ष में नई योजनाओं और नई-नई नीतियों के साथ इस राष्ट्र को और इस प्रदेश को नई सदी में प्रवेश कराने जा रहे हैं यह इस अभिभाषण में बताया गया है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 50वीं शहादत की पुण्यतिथि को जो हम कल मनाने जा रहे हैं का वर्णन किया है। राज्यपाल महोदय, ने यह भी बताने की कोशिश की है कि इस वर्ष में सारे प्रदेश में जो पिछले वर्ष एक सफाई अभियान शुरू किया गया था उसको इस वर्ष 30 जनवरी के दिन जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का दिन है, पूरा करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को सर्व-धर्म सुखाय के रूप में मनाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल एक दिन का उपवास रखने का आह्वान किया है। उसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस दिन को सर्व-धर्म सुखाय के रूप में मनाने की भावना को व्यक्त करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उस पर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए कल एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उन सबका अनुसरण करते हुए मैं भी कल का उपवास रखने का ऐलान करता हूं। मैं अपने तमाम साथियों से भी यह आशा करता हूं कि वे भी कल का उपवास रखेंगे और जो हमारे राष्ट्र की मुख्यधारा है उसका अनुसरण करेंगे और करना भी चाहिए। सबको संकल्प लेना चाहिए कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की 50वीं पुण्यतिथि को हम सब सर्वधर्म सुखाय के रूप में मनायें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रदेश की जनता को भी यह कहना चाहता हूं कि वे भी कल का दिन उपवास रखें और महात्मा गांधी की 50वीं पुण्यतिथि को सर्व धर्म सुखाय के रूप में मनायें। सर्व धर्म सुखाय का संदेश सदा ही हिन्दुस्तान के द्वारा दिया गया।

"सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्, दुःखमाप्नुयात्।।"

यह संदेश हमारे देश में दिया गया। अगर उस फरवर को, देश की उस कल्पना को, बचाकर रखना है तो हम सबको, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, समाज के लोगों को, समाज शास्त्रियों को, समाज के जागरूक तत्वों को तथा सारे राष्ट्र की जनता को प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कल का उपवास रखने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। मौजूदा सरकार ने सर्वप्रथम लोकपाल बिल को मंजूरी दे कर लोकपाल नियुक्त करने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लोकपाल नियुक्त करने के बारे में सदा कहा जाता रहा, इस बारे में हमेशा बात कही जाती रही लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को पूरा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को तीन भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है ? कहा जाता है।

Plan your work and work your plan. On this basis all the governments can be categorised in three parts.

एक प्रकार की सरकार वह होती है जो सरकार अपने कामों को ठीक ढंग से प्लान करती है और फिर उस प्लान पर कार्य करती है। एक दूसरे प्रकार की सरकार होती है जो प्लान तो करती है Plan your work, do not work on it, never work on it. यह दूसरे प्रकार की सरकार है। एक तीसरे प्रकार की सरकार होती है उसके बारे में हमें समय समय पर देखने को मिला है क्योंकि हमारे सामने तीसरे प्रकार की सरकारें भी आई हैं जो न तो कोई प्लान करती थी और न ही कोई कार्य करती थी। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का फख्र है और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को इस बात का फख्र होना

चाहिए कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो सरकार विराजमान है यह सरकार अपने काम प्लान भी करती है और उस प्लान पर पूरी तरह से अमल भी करती है। उस प्लान पर पूरी तरह से वर्क भी करती है। जब मौजूदा सरकार वजूद में आई तब हमारी सरकार ने अनेकों बातें कहीं और उन बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह की कि लोकपाल बिल को मंजूरी दे कर लोकपाल की नियुक्ति की। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में पहले की अनेकों सरकारों द्वारा भी काफी कोशिश की जाती रही लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने इस बात को अमलीजामा पहनाया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को भी इन्टरवीन करना पड़ा, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारें बताएं कि लोकपाल की नियुक्ति के बारे में क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रदेश सरकार ने इस बात को केवल नारे तक ही नहीं रहने दिया। हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे यहां लोकपाल नियुक्त करके अपनी कही गई बात को अमलीजामा पहनाया। हमारे यहां लोकपाल की नियुक्ति हो गई है और उसने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी नेशन वॉडी को, आज हमारे राष्ट्र की व्यवस्था को, आज हमारे इस सारे ढांचे को बुरी तरह से अगर किसी ने खोखला किया है, अगर किसी ने ग्रस्त किया है, अगर किसी ने इसको अपंग बनाया है तो उसके लिए भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर भ्रष्टाचार को सही दृष्टि से देखा जाए तो यह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। जैसे पौधा लगाने के लिए पहले बीज बोया जाता है, उस बीज का पौधा बनता है फिर पेड़ बनता है। पौधा तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है इस भ्रष्टाचार का खेल उल्टा है। भ्रष्टाचार विनाश की जड़ है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर फैलता है, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, अगर इससे निजात पानी है, अगर प्रजातंत्र को बचा कर रखना है, अगर लोगों का अटूट विश्वास कायम रखना है तो इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फैंकना बहुत ही आवश्यक है। इसकी जड़ें आकाश में हैं और इसको खत्म करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। कहा भी जाता है सामरथ को नहीं दोष गुसाईं। जो ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं उन तक कोई उंगली नहीं कर सकता उनको कोई नहीं पूछ सकता। नीचे कोई छोटा मोटा आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी गर्दन मरोड़ी जा सकती है लेकिन जो ऊंचे पदों पर विराजमान हैं जिन्होंने इस देश की वागडोर सम्भालने का जिम्मा लिया है भ्रष्टाचार वहां से शुरू होता है। उन तक हाथ नहीं पहुंच पाते। अगर वे गलत काम करें तो उन तक भी हाथ पहुंच सके, उनके गिरेवान को पकड़ सकें, उन द्वारा गलत किए गए कामों को रोका जा सके, उच्च पदों पर पदस्थ लोगों को काबू में रखने के लिए, उनको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए और भ्रष्टाचार के वृक्ष की जड़ों को काटने के लिए एक ऐसी अथोरिटी की आवश्यकता थी जो उनको पूछ सके। इसलिए मैं मौजुदा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने प्रदेश में लोकपाल की नियुक्ति करके एक बहुत ही एतिहासिक कदम उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि हम जो नई सदी सन् 2000 में प्रवेश करने जा रहे हैं उसमें पुरानी बुराईयों को छोड़ पायेंगे। आज लोगों का राजनीतिज्ञों पर से विश्वास उठ चुका है। आज अगर सबसे अधिक डी-वैल्यूएशन हुई है तो वह राजनीतिज्ञों की हुई है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि हम पुरानी बुराईयों को छोड़ कर उनसे मुक्त होकर नई सदी में प्रवेश करेंगे। सरकार ने जो लोकपाल की नियुक्ति की है उसके लिए मैं सरकार की एक बार नहीं हजार बार प्रशंसा करता हूं और सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में खुलेपन की हवा बह रही है। सरकार की सोच में परिवर्तन आया है। ऐसा परिवर्तन सारे राष्ट्र में आया है। आज सरकार की मुख्य जिम्मेवारी लोगों को इन्फ्रास्ट्रैक्चर

[श्री अनिल विज]

प्रोवाइड कराने की है। इन्फ्रास्ट्रैक्चर लोगों को प्रोवाइड करा कर राष्ट्र की तरक्की हो सकती है, किसी प्रान्त की उन्नति हो सकती है। सरकार का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जिससे लोग भय मुक्त होकर सरकार की आलोचना कर सकें। सरकार लोगों के लिए ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे वे आगे बढ़ सकें और सबका भला हो सके। उसके लिए इन्फ्रास्ट्रैक्चर प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रान्त देश में वैल प्लेसड है। हमारा प्रदेश जब पंजाब से अलग हुआ था तो उस वक्त न तो यहां पर उपयुक्त सड़कें थीं, न बिजली के कनैक्शन थे और न नहरी पानी हमारी जरूरत के मुताबिक था। आज के दिन हमने सभी चीजों में महारत हासिल की है। हमारा प्रदेश देश की राजधानी से सटा होने के कारण यहां पर सड़कों का जाल है, रेलवे लाईनों का जाल है। हमारे यहां पर नहरी पानी उस वक्त की अपेक्षा अधिक है जब हम पंजाब से अलग हुए थे। हमारे पास आज वे सब साधन मौजूद हैं जिनसे हम हिन्दुस्तान का नंबर वन प्रान्त बन सकते हैं। हमारे यहां पर कमी है तो बिजली की है। बिजली की कमी के लिए अनेक वर्षों से प्रयास किए गए लेकिन उतने नहीं किए गए जितने की आवश्यकता थी। हमारे यहां पर बिजली की खपत निरंतर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस समय हमारा प्रदेश बना उस वक्त बिजली की कंजम्पशन पर कैपिटा 57 यूनिट की थी जो अब बढ़कर 460 यूनिट हो चुकी है। बिजली की ज्यादा जनरेशन के लिए जितने प्रयास किए जाने थे, वे उस स्तर पर नहीं किए गए। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने सत्ता सम्भालते ही सबसे अधिक ध्यान अगर दिया है तो वह बिजली की हालत सुधारने की तरफ दिया है। अगर बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे और अगर कारखाने चलेंगे तो उत्पादन अधिक होगा, अगर उत्पादन अधिक होगा तो उजरत अधिक होगी, अगर उजरत अधिक होगी तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी अधिक होगी, अगर परचेजिंग कैपेसिटी अधिक होगी तो दुकानदार को अधिक माल लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी सेल अधिक बढ़ेगी, अगर दुकानदार अधिक माल लाएगा तो मांग और भी बढ़ेगी। यह सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे विकास को गति मिलती है। ये सभी चीज़ें बिजली की उपलब्धता से जुड़ी हुई हैं। बिजली की उपलब्धता मात्र 863 मैगावाट है जबकि बिजली की मांग और जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। नये कारखाने लगेंगे और कारखाने लग भी रहे हैं लेकिन जितने कारखाने लगने चाहिए उतने बिजली की उपलब्धता न होने के कारण लग नहीं पा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि विकास की तेजी में कमी हुई है। बिजली की उपलब्धता कम होने के कारण इस विकास को सरअन्जाम नहीं दिया जा सका। इस सरकार ने आते ही बिजली उपलब्धता बढ़ाने के लिए और इसका उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल कहने की ही बात नहीं है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि यह केवल नारा नहीं है केवल घोषणा नहीं है, जो भी घोषणा सरकार की तरफ से की जाती है उसे अमली जामा पहनाया जाता है। अगर बिजली का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की गई है तो उसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। आज फरीदाबाद में गैस बेस्ड थर्मल प्लांट एन०टी०पी०सी० के द्वारा बनाया जा रहा है जिस पर 1163 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उसकी पहली इकाई बन कर तैयार होने जा रही है और अगले छः महीने तक दूसरी इकाई भी तैयार हो जाएगी। इस वर्ष के अन्त तक यानि दिसम्बर माह तक वह गैस बेस्ड थर्मल प्लांट 432 मैगावाट बिजली की जनरेशन हमें और देगा। आज तक हमें 863 मैगावाट बिजली प्राप्त है और फरीदाबाद के इस गैस बेस्ड प्लांट से 432 मैगावाट बिजली हमें और उपलब्ध होने लग जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ पानीपत की जो चार इकाइयां हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर 25% से अधिक नहीं था। सरकार उसको भी बढ़ाना चाहती है और जर्मनी की फर्म ए०बी०बी० को उसका कंट्रैक्ट दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 25% पी०एल०एफ० को

बढ़ा कर वे 80% प्लांट लोड फैक्टर कर देंगे। इस कार्य के भी शीघ्र ही पूरा होने की उम्मीद है और इससे लगभग 232 मैगावाट अतिरिक्त बिजली हमें मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत की छठी इकाई लगाने के बारे में भी सरकार प्रयास कर रही है। समय-समय पर इसके बारे मे घोषणाएं होती रही हैं लेकिन वे केवल घोषणाएं ही रही हैं। सबसे पहले 1989 में इस इकाई को लगाने का विचार किया गया था लेकिन वह विचार केवल विचार ही रह गया। अगर उस वक्त यह इकाई लग गई होती तो 238 करोड़ रुपया इस पर खर्च होता और बिजली का टैरिफ 92 या 93 पैसे लगता लेकिन वह विचार केवल विचार ही रहा और यह स्कीम फाईलों से बाहर नहीं निकल सकी। उस पर कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया जिसके कारण उसकी कीमत दिन-प्रति-दिन बढ़ती चली गई। आज की मौजूदा सरकार ने इस छठी यूनिट को चालू करने के लिए कार्य आरम्भ किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 238 करोड़ की बजाए इस पर 634 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा जिससे टैरिफ की कीमत जो 92-93 पैसे होनी थी वह आज 3 रुपये बनती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिजली की जरूरतों को देखते हुए छठी योजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है। वह शीघ्र अति शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने निजी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 25-25 मैगावाट के 12 लिक्वेड फयूल बेस्ड स्टेशंज बनाने आरम्भ कर दिए हैं। इनमें से फरीदाबाद में मैसर्ज मैगनम को 25 मैगावाट और मारूति उद्योग को 25 मैगावाट के स्टेशंज स्थापित करने का काम आरम्भ करने को कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 33-33 के०वी० के आठ नए बिजली उप केन्द्रों को शुरू किया गया है। कैथल, नीसिंग की 220 के०वी० की ट्रांसमिशन लाईन और पानीपत तथा रोहतक की 200 के०वी० की ट्रांसमिशन लाईन कमीशन की गई है। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमाम बातों पर ध्यान रखा गया है। चाहे बिजली की जनरेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे सब-स्टेशन लगाने की बात हो इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस सरकार ने आने के बाद 25 सब-स्टेशंज लगाए गए हैं और लगभग 123 सब-स्टेशंज को आगमैंट किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2000 तक 93 नए सब-स्टेशंज लगाए जाएंगे। चौधरी बंसी लाल जी ने बार-बार घोषणा की है इस प्रदेश में जनता को जुलाई के बाद 24 घंटे बिजली देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश में प्रथम राज्य होगा जहां पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जो काम आज बिजली की वजह से रुके हुए हैं वे भी शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सबको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और इस काम में मुख्यमंत्री जी को भरपूर समर्थन देना चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में इस सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धता प्राप्त की है। इस सरकार ने पिछले 30 मास में फ्लड कंट्रोल करने के लिए 532 ड्रेनेज की सफाई करवाई है। उपाध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि ताजेवाला हैड वर्कस 100 वर्ष पुराना है। जब 1997 में बाढ़ आई थी तो उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया था क्योंकि उससे 700 क्युसिक ज्यादा पानी बाढ़ के वक्त आ गया था। उस वक्त पता नहीं था कि ताजेवाला हैड वर्कस उस पानी को बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसलिए सरकार ने हथनीकुंड बैराज बनाने का कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है और वह भी शीघ्र ही यानी जून, 1999 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी सब क्षेत्रों में भी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने आजकल बी०पी०एल० का भी एक सर्वे करवाया है। उसके मुताबिक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए और गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए वह अलग-अलग राशन कार्ड बना रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन राशन की दुकानों के माध्यम से काफी काला बाजारी होती है इसलिए हम इस बारे में एक तरमीम कर सकते हैं, एक चेंज कर सकते हैं कि हर राशन कार्ड होल्डर से पहले ही एक रिक्वीजिशन ले ली जाए कि वह क्या-क्या सामान

[श्री अनिल विज]

राशन की दुकान से लेना चाहता है क्योंकि हर एक राशन कार्ड होल्डर हर महीने मिट्टी का तेल, गेहूं या अन्य सामान नहीं लेता है। नतीजतन होता यह है कि वहां पर बाकी बचे हुए सामान की काला बाजारी होती है इसलिए हर राशन कार्ड होल्डर से एक रिक्वीजिशन ली जानी चाहिए ताकि उसका राशन की दुकान वाला उसको वही सामान मुहैया करवा सके। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में भी सरकार ने काफी काम किया है। चाहे वह विकलांग पैंशन हो या ओल्ड ऐज पैंशन हो या चाहे वह विधवा पैंशन हो ये सारी पैंशन हर महीने की सात तारीख को उनको मिल जाती है। सरकार ने इस मामले में अपनी एक गुडविल स्थापित की है क्योंकि वह सात तारीख को उपरोक्त लोगों को पैंशन उपलब्ध करवा देती है। इसके अलावा बाकी जो योजनाएं हैं चाहे वह अपनी बेटी अपना धन हो या अन्य कोई योजना हो उन सभी पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। सरकार ने अनेकों स्थानों पर ओल्ड ऐज होम स्थापित किए हैं। इसी तरह के एक ओल्ड ऐज होम की आधारशिला अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला शहर में रखी है। यह होम भी शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से सरकार समाज के सभी वर्गों की तरफ अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही है चाहे वह अनुसूचित जाति के लोग हों या चाहे वह बुजुर्ग हो इन सभी की तरफ सरकार ने अपना ध्यान दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर कोई हरिजन बच्चा प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करता है तो उसको सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाता है। इसके अलावा भी सरकार की अनेकों ऐसी स्कीम्ज हैं जिनका लोग पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए मैं इस बारे में सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वह उन तमाम स्कीम्ज के बारे में सेमीनार आयोजित करके लोगों को बताए। उन सेमीनार में चुने हुए प्रतिनिधियों को तथा अन्य लोगों को भी बुलाकर बताया जाना चाहिए क्योंकि मैं यह समझता हूं कि जितना उन स्कीम्ज का प्रचार होना चाहिए था उतना नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हैल्थ के बारे में भी सरकार ने काफी गंभीरता दिखायी है। अभी पिछले दिनों ही पल्स पोलियो अभियान 6 दिसम्बर और 17 जनवरी को चलाया गया है। इस अभियान को मैंने स्वयं देखा है। यह अभियान एक मूवमैन्ट की तरह चला है। लोग इस तरह से झुंडों में इकट्ठे होकर अपने अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए लेकर गए हैं जैसे चुनावों के दौरान चुनाव वाले दिन इकट्ठे होकर वोट डालने जाते हैं। यह सरकार का एक सराहनीय काम था। इसी तरह से सरकार ने हैपाटाईटिस-बी के टीकाकरण का भी बीड़ा उठाया है लेकिन मैं इस बारे में सरकार का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे ध्यान में यह बात आयी है कि यह पहला टीका लगाए जाने के एक महीने बाद दूसरा टीका लगाया जाना अति आवश्यक है लेकिन सरकारी अस्पतालों में इस टीके की सप्लाई एक महीने बाद उपलब्ध नहीं हो पायी है इसलिए सरकार को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ नाजायज लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इन नाजायज लोगों ने स्थान-स्थान पर कैम्प लगाकर और यह कहकर इस टीके को बेचा है कि अगर महीने अंदर दूसरा टीका नहीं लगे तो पहला टीका बेकार हो जाएगा। इस बारे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां पहला टीका उपलब्ध कराया जाता है वहां दूसरे टीके का स्टॉक भी रखना चाहिए। चाहे थोड़े लोगों को ही लगाएं लेकिन पहला लग जाए तो दूसरे का स्टॉक अवश्य होना चाहिए ताकि पहला टीका कारगर हो सके। उसका कोई नुकसान न हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी। नगर पालिका के बारे में इस अभिभाषण में काफी कुछ कहा गया है। गंदी बस्तियों व पर्यावरण के सुधार के लिए काफी पैसे का प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल सरकार द्वारा प्रावधान करने मात्र से नगरपालिकाओं की हालत नहीं सुधारी जा सकती। जब तक हम नगरपालिकाओं को उनकी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते तब तक उनकी हालत

को सुधारा नहीं जा सकता। आज हम देखते हैं कि नगरपालिकाएं गम्भीर वित्तीय स्थिति के दौर से गुजर रही हैं लेकिन फिर भी उनकी आय के स्त्रोत बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। नगरपालिकाओं में हाउस असेसमैंट फीस की रेशनेलाइजेशन होनी चाहिए जिसके तहत हाउस असेसमैंट फीस उनसे कलैक्ट की जा सके। आज किस दर पर उनसे हाउस असेसमैंट फीस ली जानी चाहिए उस बारे में कोई फार्मूला नहीं है वह अपनी मर्जी के मुताबिक फीस लगा देते हैं नतीजतन इससे उन्हें काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। नगरपालिकाओं की बहुत बड़ी भूमि पर इन्क्रोचमैंट हुई है और यह प्रवृति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। प्रभावशाली व्यक्ति उसको इन्क्रोच करते हैं। इस बारे में सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। It should be made a criminal offence. इन्क्रोचमैंट करने वाले को किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से डिबार करना चाहिए ताकि इस पर रोक लग सके और सरकार की जमीन को बचाया जा सके। नगरपालिकाओं की आय के स्त्रोत को बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ नगरपालिकाओं द्वारा सफाई के लिए भी कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में लगभग तमाम मुद्दों पर बात की गई है। भवन एवं सड़कों के बारे में बात की गई है। नेशनल हाईवे घोषित किए गए हैं उनके बारे में भी इस अभिभाषण में कहा गया है। पर्यटन व खेलकूद के बारे में भी कहा गया है। जो विकास की तमाम चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। सरकार यकीनी तौर पर उन तमाम बातों की ओर ध्यान दे रही है। मैं सरकार का ध्यान इन तमाम बातों से हटकर कुछ दूसरी बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। वह मैं इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार में संकल्प शक्ति है। इन तमाम चीजों को यह सरकार ठीक कर सकती है जो बात मैं कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि वह किस सरकार के समय से है लेकिन वह बात मौजूद है। वह यह है कि जो हमारी व्यवस्था है उससे आम आदमी तंग आ चुका है। आम आदमी का उससे विश्वास उठता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह सरकार जिम्मेदार है या पिछली सरकार जिम्मेदार है लेकिन इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। हम सबको राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। आखिर इस व्यवस्था को हम कब तक घसीटते रहेंगे ? आज इंसपैक्टरी राज है लेकिन कोई इंसपैक्टर अपना काम नहीं करता। अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता जैसे फूड इंसपैक्टर यह नहीं देखता कि लोगों को खाने पीने की चीजें शुद्ध मिल रही हैं या नहीं। कार्यालयों में पत्र भेजो तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह सब इस सरकार के समय से चल रहा है। यह पिछले काफी समय से चल रहा है। यह इस तरीके से चल रहा है जैसे सूबेदारियां स्थापित की गई हों। चाहे वह डी०एच०ओज० हों या इग इंस्पैक्टर हो या कोई ऐसी पोस्टें हो जैसे पुलिस विभाग में है ऐसी पोस्टों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सब को दुरुस्त करना चाहिये, क्योंकि लोगों का धीरे-धीरे ऐसी पोस्टों पर कार्यरत लोगों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। इसके लिए सब दोषी हैं। इसके लिए कोई एक या दो दोषी नहीं हैं। इसके लिए दोषी आप भी हैं हम भी हैं। हम सबको मिलकर इसको सुधारना चाहिये ताकि लोगों का विश्वास न उठे। लोगों को अपने कामों को करवाने के लिए ठोकरें न खानी पड़ें, उनको मुख्य मंत्री जी से मिलने की नौबत न आये, जिस भी अधिकारी का काम हो वह उसे करे। डी०सी० का काम डी०सी० करे, तहसीलदार का काम तहसीलदार करे और डाक्टर का काम डाक्टर करे। इन तमाम चीजों को सुधारने के लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हंगामा खड़ा करने का मकसद नहीं है मेरी ख्वाहिश तो यह है कि हालात सुधरने चाहिये। "मेरे दिल में न सही, तेरे दिल में सही, आग आखिर आग है किसी ओर तो सुलगनी चाहिए।" मैंने पहले भी कहा है कि हम सब को मिलकर आम आदमी के कष्टों को कम करने

[श्री अनिल विज]

के लिए पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रयास करने चाहियें। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो बातें राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस सदन में कही हैं मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से उनको पारित करके उनके पास धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नृपेन्द्र सिंह जी आप बोलिये and second the motion.

श्री नृपेन्द्र सिंह (बाढ़ड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाई अनिल विज ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है कि इस सदन में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 28 जनवरी, 1999 को इस सदन में पढ़ने की कृपा की है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कल 28 जनवरी, 1999 को जो अभिभाषण यहां विधानसभा में पढ़ा उस पूरे अभिभाषण को ध्यान से सुनने से मालुम हुआ कि पिछले अढ़ाई साल के अर्से में सरकार ने जो काम करने की एक योजना पूरे प्रदेश में बनाई है उसकी चर्चा इस अभिभाषण में बिस्तार से हुई है। इस अभिभाषण में आने वाले साल के लिए जो योजनायें राज्यपाल महोदय ने बताई हैं, इन अढ़ाई साल में हुए कामों का हमें आभास मिला कि थोड़े से अर्से में कितना कुछ काम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश का जन्म पंजाब प्रदेश के एक हिस्से के रूप में हुआ। हरियाणा प्रदेश की अलग प्रदेश के रूप में मांग करने वालों में उस समय दो तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। प्रथम सोच तो वह थी कि हरियाणा प्रदेश को खासतौर से रेतीले क्षेत्र को पंजाब से अलग किये बगैर इसका विकास नहीं हो पायेगा क्योंकि वहां न पीने का पानी था और न सड़कें थीं न बिजली की व्यवस्था थी। आम लोगों तक तभी पहुंचा जा सकता है जब इन चीजों की व्यवस्था की जाये इसलिए प्रथम सोच के व्यक्ति तो वे थे जो यह सोचते थे कि हरियाणा प्रदेश को अलग प्रदेश का रूप दिया जाये। दूसरी सोच के व्यक्ति भी उस समय सक्रिय थे। उनका भी इस हरियाणा प्रदेश को बनाने में योगदान रहा। जिनके दिमाग में एक बात थी और वे जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते थे। उनकी सोच यह थी कि पंजाब में रहते हुये उन्हें जाति के नाम पर सत्ता में कभी भागीदारी नहीं मिल सकेगी। अगर अलग प्रदेश का निर्माण किसी न किसी तरह से हो जाये तो वे जातिवाद का सहारा लेकर जाति के नाम पर इस प्रदेश में अपना राज कायम कर सकेंगे। दूसरी सोच के व्यक्ति ये थे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि प्रथम सोच के व्यक्ति चौधरी बंसी लाल जी थे और उनको मौका भी मिला, 1 नवम्बर, 1966 को जब हरियाणा का जन्म हुआ, 1966 से 1976 के अर्से में हरियाणा प्रदेश के हिस्से में जो भू-भाग आया था उसमें न ही सड़कें थी, न ही बिजली थी और न ही पानी, खास तौर से दक्षिणी हरियाणा में उस समय कोई भी यह अन्दाजा नहीं लगा सकता था कि नहरें इस क्षेत्र में भी पहुंच सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी के अथक प्रयास से उस अर्से में हरियाणा के हर क्षेत्र में सड़कें पहुंचाई गई, बिजली पहुंचाई गई, पानी पहुंचाया गया, जहां नहरी पानी का इंतजाम नहीं था वहां नहरी पानी का इंतजाम किया गया। उसके बाद यानि 1976 के बाद 1977 में जो दूसरी सोच के व्यक्ति थे जो हरियाणा के निर्माण में लगे हुये थे, उन लोगों के हाथ में यह सत्ता आई तो नतीजा यह हुआ कि जातिवाद के नाम पर राजनीति शुरू हुई। उस समय 1977 में जो लोग सत्ता में आये उनकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसे एक डाकू के गिरोह की हालत डाका डालने के बाद डाके का माल बंटबारे के लिये लड़ना। उस समय हालत यह बनी। उस समय जाति वाद का नाम लेकर हरियाणा प्रदेश में राज कायम किया गया। उसके उपर भी एक पूंजीवादी व्यवस्था आई और यहां पर हमारे हरियाणा प्रदेश के विधायकों की खरीद फरोख्त इस ढंग से की गई जैसे

बछड़े और ऊंट बिका करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा प्रदेश की जनता का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया। एक अनिश्चय की स्थिति हरियाणा प्रदेश में आई और खास तौर से ऐसी परिस्थिति में बैकवर्ड और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना भविष्य अन्धकारमय लगने लगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये बताता हूँ कि उस समय के गवर्नर महोदय, को भी उसी सरकार में अपमानित होना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। जातिवाद और पूंजीवादी लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, उनका संघर्ष चलता रहा। हरियाणा प्रदेश के विकास की किसी ने परवाह नहीं की। आखिर में 1996 में आकर हरियाणा प्रदेश की जनता को यह फैसला अपने हाथ में लेना पड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि जो दस-पन्द्रह साल में एक राजनीतिक सोच हरियाणा प्रदेश में ऐसे लोगों ने अपने स्वार्थों से पैदा की थी, उस सोच से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक बार फिर इस सरकार को कायम किया। वे लोग इस बात पर घमण्ड करते थे कि वे पूरे हिन्दुस्तान में राजनीति करते थे और अपने बलबूते पर जिसको चाहे संसद में पहुंचा सकते थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में ऐसी स्थिति आई कि जो लोग किसी को भी संसद में पहुंचाने का दावा करते थे उन्हें खुद भी संसद में पहुंचने के लिए रामविलास शर्मा जी और अटल बिहारी बाजपेयी जी का सहारा लेना पड़ा और वे पिछले दरवाजे से ही राज्य सभा जा सके, सामने के दरवाजे से नहीं आ पाये। उनकी जो राजनीतिक सोच थी उसी को देख कर ही हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार 12.00 बजे किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई में मेहम जैसी घटनाएं भी हुई हैं (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए अपनी तीनों पीढ़ियों को बचाना ही मुश्किल हो गया और यह संदेश केवल हरियाणा प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि यह संदेश साथ लगते हुए राज्यों में भी गया और पिछले दिनों ऐसे हालातों में राजस्थान और दिल्ली के चुनाओं में इनकी पार्टी के लोगों की ये जमानतें भी नहीं बचा सके। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी के लिए ये सारी बैकग्राउंड की बातें बताना जरूरी था। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उस में एक झलक इस बात की भी आने लगी है कि हरियाणा प्रदेश अपने खोए हुए अस्तित्व को फिर से पाने की ओर अग्रसर है। पिछले अढ़ाई साल में जो विकास हुआ है और आने वाले सालों की योजनाओं के दृष्टिगत राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा जिससे यह लगता है कि हरियाणा प्रदेश अपनी पुरानी स्थिति को पुनः पा सकेगा और हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश पुनः अपनी वह जगह बना सकेगा जो पहले कभी चौधरी बंसी लाल जी के कार्यकाल में हुआ करती थी। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय ने लोकपाल की नियुक्ति की बात कही है। मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो लोग अभी शोर मचा रहे हैं, लोकपाल महोदय की नियुक्ति से सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को होगी। श्री ओम प्रकाश चौटाला अभी सदन में नहीं हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो 300 करोड़ रुपया मेरे भाई ने राजनीति में रहते हुए गलत ढंग से कमाया है, उसके लिए जो भाई अदालतों में घूम रहे हैं अब इनको इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि श्री ओम प्रकाश चौटाला ने गलत तरीके से कमाया गया जो धन विदेशी बैंक में जमा करवाया था, वह बैंक भी डूब गया। "जित-जित पां बड़े संतन के, हो गया बंटाधार"। लोकपाल की नियुक्त के बाद आने वाले समय में ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो सबसे अहम काम किया है, वह आने वाले समय में 24 घंटे बिजली देने का किया है। मैं बिजली के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि मैं खासतौर से उस क्षेत्र से संबंध रखता हूं जिस क्षेत्र के लोग पिछले बीस साल से सत्ता में रहे वे बिजली के नाम पर ही राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने किसानों

[श्री नृपेन्द्र सिंह]

की यह आवश्यकता नहीं समझी कि बिजली के और कारखाने स्थापित किए जाएं। इसके अलावा वे हर बार बिजली का भाव बढ़ाते रहे। जैसे बिजली का भाव 5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया, तब आन्दोलन हुए और उन्होंने बिजली का भाव 3 रुपये प्रति यूनिट कम करके तुष्टिकरण की नीति अपनाई। आखिरकार पहली बार इस सरकार ने इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा प्रदेश में पहले 863 मैगावाट बिजली पैदा होती थी लेकिन इस सरकार ने 1200 मैगावाट बिजली पैदा करने की योजना बनाई है। इस प्रकार से जुलाई, 1999 से पूरे हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। आज जो लोग बिजली के नाम पर राजनीति करते हुए प्रदेश में घूमते हैं, उनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा परेशानी जो विपक्ष के भाईयों को हो रही है वह यही है कि इन के हाथ से यह बिजली का मुद्दा भी निकलने जा रहा है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सिंचाई के बारे में भी कहा। मैं सिंचाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने नहरों के टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 20-20 साल से जो सरकारें नहरों के टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचा सकी थीं, यह कार्य हमारी सरकार ने पूरा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हरियाणा राज्य ने काफी उन्नति की है, इसका परिचय भारत के केन्द्रीय पूल में, हरियाणा प्रदेश द्वारा अनाज का एक बहुत हिस्सा भेजकर, दिया गया है। जिस समय हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ था, उस समय सभी को मालूम था कि हरियाणा में खनिज उपलब्ध नहीं होता था, यहां पर प्रकृति की कोई देन नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां का किसान बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है लेकिन पिछले 20 सालों में किसी भी सरकार ने किसानों को न पानी दिया, न बिजली दी, उसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा प्रदेश में अनाज की पैदावार बहुत कम हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने अढ़ाई साल के कार्यकाल में कृषि को काफी बढ़ावा दिया है जिसके कारण कृषि क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सहकारिता के बारे में जिक्र किया है कि हरियाणा स्टेट कोआप्रेटिव लैंड डिवैल्पमैंट बैंक को वर्ष 1997-98 के दौरान उसकी आउटस्टैंडिंग प्रफोरमैंस के लिए एन०सी०ए०एंड आर०डी०बी०एफ० की ओर से इनाम में ट्रौफी दी गई है। यह बहुत ही खुशी की बात है। इस बैंक ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय इस सरकार को जाता है। दूसरा श्रेय बैंक के कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की बदोलत हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश को पहली बार पुरस्कार दिलाया है। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने बृद्धावस्था पैंशन को लेकर यहां पर राजनीति शुरू की थी। उसके बाद जो पिछली सरकार आई उसके समय में लोगों को बृद्धावस्था पैंशन नहीं मिलती थी। लेकिन हमारी सरकार हर महीने की 7 तारीख तक हर वृद्ध व्यक्ति को उसकी पैंशन दे देती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले अढ़ाई साल के दौरान बहुत बड़े-बड़े गैंग अरैस्ट किये गये और वे लोग हरियाणा प्रदेश में, खासतौर से दिल्ली के साथ लगते एरियाज से अरैस्ट किए गए। आज सुबह प्रश्नोत्तर काल के दौरान चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी और प्रो० सम्पत सिंह जी ने एक बात उठाई थी कि कार की चोरियां कितनी हुई और उनमें से बरामद कितनी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे लोगों के संबंध दिल्ली में बैठे रोमेश शर्मा जैसे लोगों के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कार की चोरियों की बात को छोड़िये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी सदस्यगण से प्रार्थना है कि आप सभी लोग आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं और सदन की कार्यवाही को चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बात कानून व्यवस्था की चल रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात सदन में बताना चाहता हूँ वह यह है कि इंडिया टू-डे एक मैगजीन है, जो पूरे हिन्दुस्तान में मिल जाती है तथा मनोहर कहानियों की जो किताब अब आयेगी उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी के और रोमेश शर्मा के बारे में बताया गया है और उसमें इन दोनों के एक साथ फोटो भी छपे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये कार सनैचिंग की बात करते हैं। (शोर)

Mr. Speaker : No interruptions please.

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी भाई कार सनैचिंग की घटनाओं से बहुत परेशान हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि श्री ओम प्रकाश चौटाला का संबंध ऐसे आदमी के साथ है जिसने हैलीकाप्टर सनैच किया है। उस हैलीकाप्टर सनैचर के साथ ओम प्रकाश चौटाला की फोटो भी है। यह हैलीकाप्टर सनैचर इनका अजय रथ उड़ा कर ले गया उसका आज तक पता नहीं वह कहां है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों झज्जर में एक व्यापारी की किडनैपिंग की घटना हुई। इस बात की आम चर्चा है कि उस किडनैपर ने बताया कि जिस दिन उस व्यापारी को किडनैप किया गया उससे पहले वाली शाम को ओम प्रकाश चौटाला के बेटे ने उस किडनैपर के साथ खाना खाया था। ये ऐसे लोग हैं जो शाम को किसी के साथ खाना खाते हैं और सुबह उसकी लाश मिलती है या कोई और अपराध कर देते हैं। चाहे अमीर सिंह की बात हो और चाहे किसी और की बात हो। (शोर) अध्यक्ष महोदय, अपराधों के सहारे ये लोग हरियाणा प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इनके कारनामें समझ चुकी है। आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में कोई स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो चुनाव हुए उन चुनावों में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिल कर वह चुनाव लड़ा। (शोर)

Mr. Speaker : Whosoever is speaking without the permission of the Chair his speech should not be recorded.

श्री नृपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने पिछले लोक सभा के चुनाव एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिल कर लड़ा। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे ज्यादा चिन्ता इनकी पार्टी में बैठे हुए शिड्यूल्ड कास्टस भाईयों को है क्योंकि वे चुनाव होते ही ओम प्रकाश चौटाला ने अगले दिन ही कहा कि जूता और जनेऊ एक नहीं हो सकते। स्वार्थ कहां तक काम करता है यह देखने की बात है। वोट लेने के लिए इनका समर्थन ले लिया उसके बाद अपने स्वार्थ के लिए जनेऊधारियों के साथ मिल गए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता अब इनको समझ चुकी है। आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में कोई स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है जिसको ले कर ये लड़ाई लड़ सकें। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। अध्यक्ष महोदय, भाई अनिल विज ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूँ कि प्रैस की तीसरी आँख हमारी एक एक बात को देख रही है अगर इन लोगों के दिलों में थोड़ी सी भावना हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए है तो इस धन्यवाद प्रस्ताव को युनानीमसली पास करें जो भाई अनिल विज ने पेश किया है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Motion moved—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 28th January, 1999."

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद) : स्पीकर साहब, मैं राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण यहां पर पढ़ा है उस पर बोलना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को हमारी कही हुई बातों पर जवाब देना है वह जो भी जवाब दे अपना जवाब देते वक्त दे दे लेकिन मुझे बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

लोक निर्माण मंत्री (भवन तथा सड़कें) (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर साहब, मेरा भी इनसे निवेदन है कि वे सही बातों को ही यहां पर रखें क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हुआ करती है। चौधरी सम्पत सिंह जी को राजनीति का एक लम्बा अनुभव है। अगर ये अच्छे सुझाव सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार उनका स्वागत करेगी। अगर ये बीच में गलत बात कहेंगे तो उसका तो उत्तर बीच में देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इनकी बातों को सुने बिना कैसे कह सकते हैं कि ये गलत कहेंगे। पहले आप इनकी बातों को सुने।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) : मेरा तो सम्पत सिंह जी से यह कहना है कि ये इन्ट्रप्शन को इन्वाइट न करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल नीतिगत मामलों पर ही चर्चा करूंगा और जो बात करूंगा वह फैक्ट्स के साथ ही करूंगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक संवैधानिक औपचारिकता है। इस अभिभाषण में सरकार द्वारा चालू साल में किए गए कार्यों और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतिगत कार्यक्रमों की एक उद्घोषणा हुआ करती है। यह महामहिम के लिए एक संवैधानिक औपचारिकता है। उन्होंने एक संवैधानिक औपचारिकता के नाते यहां पर आने का जो कष्ट किया और उनको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सरकार ने जो गवर्नर एड्रैस तैयार करके दिया वह तथ्यों से परे और असत्य है। यह अभिभाषण एक ऐसा अभिभाषण ज्ञात होता है जैसे कोई निजी कम्पनी अपना व्यावसायिक विज्ञापन तैयार करवाती है। ऐसी कम्पनी अपने व्यवसाय के बारे में विज्ञापन के अन्दर अनाप-शनाप दिखाती है। ठीक उसी तरह का यह अभिभाषण सरकार ने तैयार किया है। आजकल टी०वी० सीरियल पर एक सीरियल शक्तिमान चल रहा है जिसकी हकीकत को सही जानकर कई बच्चों ने छलांग लगाई जिससे उनकी टांग टूट गई और कुछ की मृत्यु हो गई। सोचा था शक्तिमान मदद पर आयेगा परन्तु नहीं आया इसी तरह से यह अभिभाषण लगता है।

स्पीकर साहब, प्रजातंत्र में जो काम किए जाते हैं वे लोगों के विकास के लिए करने होते हैं। सरकार का काम लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक रखना होता है। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह लोगों के लिए पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और दूसरी आवश्यक चीजों का ध्यान रखे। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह किसानों को अच्छे भाव दे। साथ ही सरकार का यह फर्ज बनता है कि उपभोक्ताओं को सही दामों पर सही चीजें मिले यानी आम

उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर मंहगाई को कन्ट्रोल रखे और सस्ते दामों पर लोगों को वस्तुएं दिलाये। यह सारा सरकार का दायित्व बनता है। सरकार का फर्ज होता है कि वह संवेदनशील होकर लोगों की समस्याओं को सुने। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह तत्परता से लोगों की मदद करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस ढंग से सरकार का रवैया रहा है उससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। यह तो आज सुबह ही सवालों के जवाब के समय पता लगा कि जिस ढंग से सरकार का रवैया इस समस्या की तरफ है। कानून-व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है और सरकार ने इसको किस ढंग से लिया है। मुख्य मंत्री जी ने उस समय यह माना है कि इसको कैजुअल रूप में लिया गया है। स्पीकर सर इसलिए यह अच्छा होता अगर गवर्नर महोदय से 24 पेज का इतना लम्बा-चौड़ा भाषण पढ़वाने की बजाए चार लाईन गवर्नर महोदय पढ़कर चले जाते तो हम उनका आभार प्रकट करते और सारे हरियाणा प्रदेश की जनता भी उनका आभार प्रकट करती। वे लाइने स्पीकर सर, इस प्रकार हैं, ''हरियाणा के संवैधानिक मुखिया महामहिम राज्यपाल को भी अपनी मंजिल कुरूक्षेत्र तक नैशनल विमैन फैस्टीवल गेम्स की ओपनिंग के लिए नहीं पहुंचने दिया गया था। सरकार के खिलाफ जन-आक्रोश की वजह से शाहबाद से ही वापिस लौटना पड़ा था तो आम आदमी का जीवन क्या होगा। प्रदेश में संवैधानिक व प्रशासनिक मशीनरी फेल हो चुकी है, अतः मैं हरियाणा सरकार को अपदस्थ करता हूं और विधान सभा भंग करता हूं'' अगर गवर्नर महोदय, इतना पढ़ जाते तो बढ़िया होता और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्पत सिंह जी ने माननीय राज्यपाल महोदय के बारे में जो चर्चा की कि वे कुरुक्षेत्र जा रहे थे और लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी बात है जिस पर सरकार को भी अफसोस था। (विघ्न) स्पीकर सर, ऐसी भी वारदातें हुई हैं कि राज्यपाल महोदय का मुंह काला किया गया हमारी सरकार के समय में कम से कम ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। चौधरी सम्पत सिंह जी को याद होगा जब इनकी अपनी ही सरकार थी या दूसरे साथियों की सरकार थी, तब राज्यपाल महोदय का मुंह काला किया गया था। जिस व्यक्ति ने मुंह काला किया था उसको इनकी तरफ से बाकायदा इनाम भी दिया गया था। (विघ्न एवं शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, काउंटर ऐलीगेशन लगा देने से बात नहीं बनती है, जिसने जो किया है उसका खामियाज़ा उसको भुगतना पड़ा है। आज हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि मंत्री यहां पर तो बड़ी बहादुरी दिखाते हैं लेकिन अपने इलाकों में जाते हुए डरते हैं। पहली बात तो यह है कि वे अपने इलाकों में जाते ही नहीं हैं और अगर वे जाते हैं तो उनको जनाक्रोश का सामना करना पड़ता है। इनके सामने जनता की मांगे आती हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें बिजली नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इससे फालतू प्रदेश की हालत और क्या खराब होगी। स्पीकर सर, जब इनकी हालत खराब हो जाती है तो ये बेचारे वहां से भाग लेते हैं क्योंकि मात्र भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरता है। (विघ्न एवं शोर)

पशु पालन मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी ये कह रहे हैं कि मंत्री अपने हल्कों में जाते हुए डरते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है सभी मंत्री अपने तथा दूसरे हल्कों में जाते हैं तो वहां पर लोग बड़ी भारी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। इनके लोकदल के लोग भी स्वागत करने के लिए आते हैं और लोग यह कहते हैं कि हम पहले चौटाला के आदमी थे लेकिन अब आपके आदमी हैं और आपके साथ ही रहेंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह कोलैप्स हो गया है। लोगों का पेट कागज़ी भाषणों से नहीं भरता, मात्र लिफाफेबाजी से लोगों का पेट नहीं भरता। जब * * * * * मंत्री लोगों के बीच में जाते हैं तो तंग आ कर कहते हैं कि चण्डीगढ़ में जा कर इस सरकार को बदल देंगे लेकिन चण्डीगढ़ में आते ही पता नहीं क्यों इनकी हवा निकल जाती है या पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है या जो इनको गद्दियां मिली हुई हैं उनके जाने के भय से ये कहने लगते हैं कि उसी नौकरी पर काम करेंगे। स्पीकर सर, इन मंत्रियों की हालत बहुत खराब है। जब ये चण्डीगढ़ से प्रस्थान करते हैं तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट वाले इनके हाथों में एक प्रैस नोट थमा देते हैं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मंत्रियों के लिये जो शब्द * इस्तेमाल किया है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस शब्द की जगह निःसहाय कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब ये यहां से निकलते हैं तो इनको तथ्यों का खुद ही मालूम नहीं होता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट सरकार द्वारा तैयार की हुई एक स्टेटमैंट की कापी इनके हाथ में सौंप देता है। जब इसको जारी किया जाता है तो प्रैस के लोग जब मंत्रियों से प्रश्न करते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा है वही छाप दें बाकी तो मुझे पता नहीं है। इसके अलावा जब ये जुबानी बोलने लगते हैं तो पुरानी बात भूल जाते हैं और ये बोलते हुये तथ्यों से परे हो जाते हैं। एक स्टेज पर कुछ कह जाते हैं और दूसरी स्टेज पर कुछ कह जाते हैं। मंत्री कुछ कहते हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ कह देते हैं। ये सब तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। स्पीकर साहब, सत्य की तो कोई नीव होती है लेकिन असत्य की कोई नीव नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, लोग इतने दुःखी हैं कि मंत्रियों के प्रति जन आक्रोश बढ़ रहा है। जींद जिले के मंत्री के विरूद्ध तो 12 गांवों की पंचायत हुई और उस मंत्री के विरूद्ध उन गावों में दाखिल होने पर पाबन्दी लगा दी। उन गांवों में पत्रकारों की एन्ट्री बन्द कर रखी है। स्पीकर साहब, बसंत पंचमी के दिन कुरूक्षेत्र में दो मंत्री गए थे। वहां पर एक मंत्री की हुटिंग हुई और उसको वहां पर बोलने ही नहीं दिया गया। यह जन आक्रोश है। यह पब्लिक के गुस्से की रिफ्लैक्शन है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, अभी सम्पत सिंह जी ने तीन बातें मंत्रियों के बारे में कही हैं। उनमें से एक तो यह कही है कि मंत्री दहाड़ते हैं। दूसरे एक मंत्री के आगे बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया है तो शायद ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हों। (विघ्न) यह जो इन्होंने कुरूक्षेत्र वाली बात कही है वह ऐसी बात नहीं है। आज नैतिकता सभी राजनीतिज्ञों में एक जैसी नहीं है। करैक्टर के बारे में भी सभी एकसार नहीं हैं। यही बात पत्रकार साथियों के साथ हुई। कुछ पत्रकार बात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। यह बात ठीक है कि वहां पर हुटिंग हुई थी। हुटिंग करने वाले कौन थे ? वे किसान यूनियन के आदमी थे। उनका एक नेता घासीराम जेल में है उसको रिहा करवाने की बात कर रहे थे। अब आप उस बारे में कुछ भी कह दें उससे कुछ नहीं होता है। यह जो मैंने बात बताई है इसके अलावा वहां पर और कोई रोष नहीं था।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब यह जो मामला है इस बारे में सारे अखबारों में छपा है और इनकी तरफ से कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमैंट अखबारों में नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं सिर्फ यही बातें ही नहीं हैं। एक मंत्री को तो हाई कोर्ट ने जुर्माना किया है और एक मंत्री की प्रताड़ना भी की है। यह कोई असत्य बात नहीं है। सारी की सारी बातें तथ्यों पर आधारित हैं। मैं किसी पर पर्सनल

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

आक्षेप नहीं लगाना चाहता इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार संवेदनशील नहीं है। यह सरकार पूर्वाग्रह से कैद है। इस सरकार ने अनभिज्ञता और उदासीनता का रुख अपना रखा है। केवल फालूस प्रैस्टिज में रहते हैं। प्रदेश की जनता का इससे बड़ा दुर्भाग्य और विवशता क्या हो सकती है कि प्रदेश की जनता को गूंगी और बहरी सरकार को झेलना पड़ रहा है।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इनके दिल में जो मर्जी आए उसको ये यहां पर थोड़े ही बोल सकते हैं यह विधान सभा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, आप एक पूर्व होम मिनिस्टर की बात सुनिए और अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : अगर एक पूर्व होम मिनिस्टर इस तरह से बोलेंगे तो फिर और लोग कैसे बोलेंगे। इनके जो भी दिल में आए क्या उसको ये यहां पर बोल सकते हैं ?

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इनको तो पहली बार यहां आने का मौका मिला है।जबकि मुझे चार बार लगातार यहां पर आने का मौका मिला है। केवल पांच या सात लोग ही ऐसे होंगे जिनको लगातार चार बार यहां पर आने का मौका मिला होगा। एक बार हार गया था लेकिन फिर दोबारा चुनाव जीतकर आ गया हूं। जब हम अगली बार यहां पर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं इन बातों को छोड़कर पावर की बात पर आता हूं। बार बार सरकार की तरफ से ब्यान आते हैं और सरकार ज्यादा स्ट्रैस "पी" पर दे रही और "पी" से ऐलर्जी रखती है। "पी" यानी पावर, प्रैस, पीपल, प्रोहिबिशन, पुलिस, प्रजातंत्र और पूअर। ये बार-बार इन्हीं बातों पर आ रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यही कारण है कि आने वाले वक्त में लोग इनसे बदला लेंगे। अभी पहले पार्लियामैंट का चुनाव हुआ था तो इनको पता लग गया था। जुलाना के एक मंत्री बड़े जोर से बोल रहे थे लेकिन पार्लियामैंट के चुनाव में इनकें क्षेत्र में इनकी जमानत जब्त हो गयी थी।

आवास राज्य मंत्री (श्री सत नारायण लाठर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठें और लाठर साहब को अपनी बात कह लेने दें।

श्री सम्पत सिंह : सर, अगर इस तरह से आप इन लोगों को बीच बीच में इंट्रप्शन की इजाजत देते रहे तो फिर हम भी मुख्यमंत्री जी को जवाब देते समय बोलने नहीं देंगे यह आप नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप भी ऐसे हो गये।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, बार-बार इंट्रप्शन हो रही है और आप उनको बोलने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन पहले जब मैंने अपना प्वायंट ऑफ आर्डर किया था तो उस वक्त आपने उसको रिजैक्ट कर दिया था। अगर इसी तरह से हमारे साथ इंट्रप्शन रही तो हम मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बड़े अनुभवी हैं आपको ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लगता। आप बैठें।

श्री सम्पत सिंह : सर, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हमें तो आपकी हालत पर तरस आता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं आपकी दया से यहां पर नहीं बैठा हूं बल्कि इस हाउस ने मुझे यहां पर बैठाया है।

श्री सम्पत सिंह : जब मैंने पहले अपना प्वायंट ऑफ आर्डर किया था तो उसको आपने डिसअलाऊ कर दिया था फिर अब आप इन लोगों को प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए कैसे

[श्री सम्पत सिंह]
इजाजत दे रहे हैं यदि आप इन लोगों को इसी तरह से अलाऊ करते रहे तो हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जब सी०एम० साहब बोलेंगे तो हम उनको बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : जब नृपेन्द्र सिंह बोल रहे थे तो उसी वक्त मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप इंट्रप्शन न करें लेकिन आप उस समय तो इंट्रप्शन करते रहे फिर अब आप कैसे कहते हैं कि आप सदन में मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। यह तो आपका कोई अधिकार नहीं है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपका यही व्यवहार रहा तो फिर हम भी यही काम करेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम उनको बोलने नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से सम्पत सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 27 फरवरी, 1990 को जब मेहम में उप चुनाव हुआ था और 28 तारीख को दोबारा से जब बैंसी गांव के आठ बूथों पर चुनाव हुआ था तो उस समय श्री हरि सिंह, सरपंच, खरकड़ा भी मौजूद थे। उस समय इन्होंने वहां पर बूथ कैपचरिंग करनी चाही थी लेकिन वहां के लोगों ने इनको ऐसा नहीं करने दिया। उस समय वहां पुलिस भी आंतकित हुई थी। उस समय श्री सम्पत सिंह जी होम मिनिस्टर थे। ये उस समय वहां पर तख्त के नीचे घुस गए थे। इनके साथ उस समय के पंचायत मंत्री श्री हुक्म सिंह और परिवहन मंत्री श्री धर्मवीर भी थे वे भी वहां पर तख्त के नीचे घुस गए थे। फिर आज ये मंत्रियों के बारे में कैसे कह सकते हैं ? स्पीकर सर, इसके अलावा इन्होंने मेरे हल्के के बारे में भी कहा है। अगर आज इनको जुलाना हल्के के बारे में इतना ही घमंड है तो चौटाला साहब या चौधरी देवीलाल जी वहां से दोबारा से चुनाव लड़कर देख लें इनको पता चल जाएगा। मैं पहले भी वहां से साढ़े बारह हजार वोटो से जीता था और फिर वहां से जीतूंगा।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पॉवर के बारे में जिक्र करूंगा। बार-बार मुख्यमंत्री जी, मंत्री मण्डल के सभी सदस्य और उनके विधायकगण पॉवर का जिक्र करते हैं हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम भी नहीं है क्योंकि आंकड़े भी भिन्न दिए जाते हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। इनको जो प्रैस रिलीज बिजली बोर्ड के प्यादे देते हैं उसको ये जारी कर देते हैं। सबसे पहले मैं इस बारे में जिक्र करूंगा, जो ये कहते हैं कि 30 जून, 1999 तक प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन जो पॉवर अवेलेबल है वह किसी भी सूरत में 2392 मेगावाट से फालतू नहीं है और आज हमारी जरूरत 4 हजार मेगावाट की है अगर ट्रांसमीशन व डिस्ट्रीब्यूशन लौसिज निकाल दिए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कंज्यूमर तक पहुंचने वाली बिजली एक तिहाई से कम हो जाती है ये यहां पर बार-बार नये थर्मल पॉवर प्लांट्स लगाने का जिक्र करते हैं। स्पीकर साहब, जहां तक बिजली की जनरेशन का सवाल है, जितने ऑन-गोइंग प्रौजैक्ट्स हैं उन पर किसी पर धीमा सा काम चालू कर दिया हो तो अलग बात है लेकिन एक भी नया प्रौजैक्ट शुरू किया हो तो मुख्यमंत्री जी जवाब देते समय बताएं कि फलां प्रौजैक्ट पर हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। इसके अलावा ये फरीदाबाद के गैस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट का जिक्र करते हैं यह 432 मेगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट है और उसको एन०टी०पी०सी० स्थापित करेगी उसका 143 मेगावाट का जो पहला यूनिट है वह जून तक जनरेशन शुरू कर देगा उससे जो बिजली बढ़ेगी उसके बारे में कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 3-1-1999 को जो भिवानी में बयान दिया कि फरीदाबाद गैस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट की 143 मेगावाट की पहली यूनिट 10 अप्रैल 99 से पहले बिजली जनरेट करनी शुरू कर देगी और अतर सिंह सैनी पॉवर मिनिस्टर हालांकि अटैच्ड पॉवर मिनिस्टर हैं उन्होंने 16-6-98 को चण्डीगढ़ में बयान दिया था कि उसकी पहली यूनिट 1 जनवरी 99 तक

पूरी हो जाएगी। दोबारा सैनी साहब ने चन्दौली गांव में 21-12-98 को बयान दिया था कि वह यूनिट मई-1999 में पूरी हो जाएगी इस प्रकार इनकी तरफ से तीन डिफरैंट स्टेटमैंट्स हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट के रैनोवेशन की बात करती है इसकी 110-110 मेगावाट की चार यूनिट हैं उनमें से एक यूनिट की रैनोवेशन का काम किया जा रहा है उससे उसकी कैपेसिटी 8 मेगावाट बढ़ेगी और वह बढ़कर 110 से 118 मेगावाट हो जाएगी। केवल 8 मेगावाट बिजली बढ़ने से तो क्रान्ति नहीं आएगी। इसी प्रकार पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की छठी यूनिट का जिक्र है वह भी ऑन गोइंग प्रौजैक्ट है उसके छठे यूनिट का काम 23-3-89 को शुरू हुआ था उसके लिए हमारी सरकार ने उस समय 80 करोड़ रुपये की मशीनरी के लिए सवा ग्यारह करोड़ रुपये बी०एच०ई०एल० को जमा करवा दिए थे।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मौके पर ही इस बारे में जवाब दे देता हूं कि उस थर्मल पॉवर प्लांट की 210 मेगावाट की छठी यूनिट का काम 1989 में शुरू हुआ था और उस पर ग्यारह करोड़ रुपये इनकी सरकार के समय में भी खर्च हुये थे लेकिन 1989 में उसके लिए जो 75 करोड़ रुपये की मशीनरी लाए थे, वह लगी नहीं। वह वैसी की वैसी धरती पर ही पड़ी रही, हमने आकर लगाई। जब बी०एच०ई०एल० से उसका हिसाब करने लगे, क्योंकि मशीन की कीमत चुकानी थी, उन्होंने मशीन की कीमत से ज्यादा ब्याज लगा दिया। हमने उनके साथ जैसे तैसे समझौता किया।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह मशीनरी कांग्रेस के शासन में पड़ी रही। हमने तो उसके लिए एडवांस में राशि जमा करा दी थी और उसी डेट को मशीनरी नहीं आती है जिस दिन पैसा जमा करवाया जाता है वह तो एडवांस जमा कराने पर तैयार होती है उस यूनिट का 15 करोड़ रुपये का सिविल वर्क भी 31-3-91 तक पूरा हो चुका था वह ऑन गोइंग प्रौजैक्ट था इसलिए उससे दिसंबर-2000 से पहले प्रौडक्शन होने की उम्मीद नहीं थी। इस सरकार ने कौन सा नया तीर मारा है कौन सी नयी जनरेशन का उत्पादन किया है। कभी यमुनानगर के थर्मल पॉवर प्लांट का जिक्र करते हैं कभी हिसार के थर्मल पॉवर प्लांट का जिक्र करते हैं। किसी पर भी काम चालू नहीं हो रहा है। स्पीकर सर, यह बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी थर्मल पॉवर प्लांट 30 जून, 1999 तक जनरेशन में नहीं आयेगा। फिर ये कैसे 24 घंटे बिजली दे पायेंगे। हां, एक तरीका है। आजकल छापे बार-बार डाले जा रहे हैं। जो जैनूयन कन्जूमर हैं उन पर बार-बार छापे डाले जा रहे हैं और उनके कनैक्शन काटे जा रहे हैं। ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन काटे जाने के जो तथ्य हमारे सामने आये हैं उनके अनुसार १५-२० हजार ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन इसी सरकार के समय में कम हुये हैं। इसके अलावा डोमैस्टिक, कामर्शियल और इंडस्ट्रीयल सैक्टर्ज में न जाने कितने हजारों बिजली के कनैक्शन कम हुये हैं। क्या इस सरकार का यह टारगेट तो नहीं है कि आधे से ज्यादा बिजली के कनैक्शन काट दिये जायें ताकि 30 जून तक लोगों को बिजली की जरूरत कम पड़े और ऐसा करके यह सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली देने की अपनी बात पूरी कर सके। वरना 24 घंटे बिजली देने की बात बनती नहीं है। इसके अलावा स्पीकर साहब, ये बार-बार वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये लौन लेने का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी जबानी ब्यान करते हैं और तथ्यों से परे रहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक अटैच्ड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने 20-1-1999 को नारायणगढ़ में ब्यान दिया कि सरकार की 7900 करोड़ रुपये की बिजली के सुधारीकरण की एक योजना है। मंत्री महोदय, इस बारे में कहीं पर 2400 करोड़ रुपये, कहीं पर 240 करोड़ रुपये और कहीं पर 1100 करोड़ रुपये कह कर अलग-अलग समय और स्थान पर ब्यान देते हैं। कोयल में 505 करोड़ रुपये तो नारायणगढ़ में 7900 करोड़ रुपये और कहीं पर 240 करोड़ रुपये कहते हैं लेकिन तथ्य कुछ

[श्री सम्पत सिंह]
और हैं। स्पीकर सर, तथ्य तो इसके और ही हैं। यह सब जबानी कहा जा रहा है और कोरी कागजी स्टेटमैंट है। जहां तक वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये के लोन देने की बात है वह आज की बात नहीं है। (विघ्न)

वास्तुकला राज्य मंत्री (श्री राजकुमार सैनी) : अध्यक्ष महोदय, नारायण गढ़ का जिक्र माननीय सदस्य ने किया। नारायण गढ़ क्षेत्र में रायपुरानी एक छोटा सा कस्बा है जो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में पड़ता है। इस कस्बे में बिजली की समस्या पिछले 20 सालों से चल रही है। इस समस्या का निदान करने के लिए वहां के लोगों ने 66 के०वी० का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी थी। बिजली महकमें के संबंधित अधिकारी उस समस्या का निदान करने के लिए वहां पर गये थे। वहां पर बिजली की लाइन लगाने के लिए काम शुरू हो चुका है शायद माननीय सदस्य को यह बात मालूम नहीं है। आज जो भी बात हमारी सरकार के बीच में होती है इस सरकार का कोई भी अटैचड मंत्री माननीय सदस्य चाहे वह निर्दलीय हो चाहे बी०जे०पी० का हो वह सदन में की गई किसी भी जायज बात को, जो किसी क्षेत्र के विकास से जुड़ी हो, कहीं पर भी कह सकता है। आज तक इस सरकार ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास की ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी है। वहां पर बिजली की लाइन बिछाने का कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आदरणीय सम्पत सिंह जी ने एक बात कही है कि इस सरकार के मंत्रियों ने अलग-अलग स्टेटमैंट दी है। उसमें अगर नारायण गढ़ का नाम आ गया तो क्या है।

श्री अध्यक्ष : उन के हल्के का नाम आया है तो वे इस बारे में कह तो सकते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, यह प्वाइंट ऑफ आर्डर तो नहीं है। (विघ्न)

Mr. Speaker : You are nobody to interrupt. I have allowed him to speak.

श्री सम्पत सिंह : सर, अच्छा होता अगर वो 7900 करोड़ रुपये की बात का जिक्र करते। स्पीकर साहब, केवल मात्र दो ट्रांसफार्मर लगा दिये या बिजली का एक कनैक्शन दे दिया, मैं उन बातों में नहीं जा रहा हूं। स्पीकर सर, जहां तक वर्ल्ड बैंक से 2400 करोड़ रुपये लोन लेने की बात है यह तो ऑन गोइंग प्रौसेस था, जो 1993 से चल रहा था। वर्ल्ड बैंक के साथ इस बारे में बात-चीत चल रही थी। रिफोर्म एण्ड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पावर का जो प्रोजैक्ट तैयार किया गया था उसके लिए एस्टीमेटिड कॉस्ट 2400 करोड़ रुपये थी। यह तो एक कमिटमैंट थी। गवर्नर एड्रैस में इन्होंने यह माना भी है कि यह सैंक्शन नहीं है, इन्होंने शायद इसमें कमिटमैंट शब्द इस्तेमाल किया है। Commitment is not a sanction. ये बार-बार ब्यान देते रहते हैं कि 2400 करोड़ रुपया मंजूर हो गया जबकि मंजूर तो केवल 240 करोड़ रुपया हुआ है। वह डैविल्टी प्रोग्राम लोन-I है यानी ए०पी०एल०-I है। बदले में जो पैसा इनको अब तक मिला है वह पैसा वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया इसकी री-इम्बर्समैंट होती है। अब तक 32 करोड़ रुपया मिला है और 10 करोड़ रुपये के कलेम्ज पैंडिंग हैं। यह मोस्टली 90 प्रतिशत मशीनरी पर खर्च किया गया है। कन्स्ट्रशन पर कोई खर्च नहीं किया है जिससे कि बिजली में इज़ाफा होगा या ट्रांसमिशन में कोई फायदा होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी बखूबी जानते हैं कि आज भी बिजली बोर्ड में करोड़ों रुपये का ऐसा सामान स्टोर्ज में पड़ा है जो अनयूज्ड है। उसकी लायबिलिटी सक्सैसिव कम्पनी की बजाय स्टेट गवर्नमैंट को लेनी पड़ेगी और यह करोड़ों रुपये की लायबिलिटी होगी। आज आनन-फानन में जो हुक्म दिया जाता है कि इसको खरीद लो, लोन खत्म करना

है, ऐसे में घटिया मशीनरी खरीदी जा रही है। इसलिये मुख्यमंत्री जी अपने लैवल पर इन्कवायरी करवा लें, चाहे हमें उसकी रिपोर्ट न दे लेकिन इन्कवायरी करा कर यह देख लें कि वह कैसा सामान है। नहीं तो कल आप उससे बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं कर पायेंगे। स्पीकर सर, जो लोन है वह बिना प्रोडक्टिव काम के लिये लेंगे और ऐसे मशीनरी पर पैसा बर्बाद करेंगे। कोरिया ने भी इसी प्रकार से आई०एम०एफ० से लोन लिया था, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। वह करोड़ों-अरबों डालर लोन लेते रहे। सारा संसार खुश होता था कि कोरिया की बड़ी तरक्की हो रही है। उस समय कोरिया टाइगर ऑफ एशिया कहलाता था लेकिन आज कोरिया का भट्ठा बैठ गया। स्पीकर सर, अगर इसी तरह से लोन का इस्तेमाल इन्होंने किया तो हरियाणा प्रदेश का भी भट्ठा बैठ जायेगा। (विघ्न) दो कोरिया हैं। दोनों का ही भट्ठा बैठ गया। स्पीकर साहब, ये बिजली बोर्ड के निजीकरण के बारे में कहते हैं कि हमने कोई निजीकरण नहीं किया जबकि निजीकरण बाकायदा होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिये दो कम्पनियों के बारे में वर्ल्ड बैंक के साथ जो डॉकूमैंट साइन किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिये दो कम्पनियां होंगी और उन दोनों कम्पनीज़ में मैजोरिटी शेयर प्राइवेट होंगे। अगर मैजोरिटी शेयर प्राइवेट होते हैं तो अपने आप ही निजीकरण हो गया। हरियाणा सरकार की तरफ से दो-तीन आई०ए०एस० अधिकारी और दो टैक्नोक्रेट्स उस डॉकूमैंट पर हस्ताक्षर करके आये हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण तो पहले ही फेल हो चुका है। पहले भी 1948 में निजी करण से संबंधित एक एक्ट बना था जिसके तहत सारी की सारी कंपनियां जो निजी तौर पर थीं, उनको पब्लिक सैक्टर में लाना था। हरियाणा में बिजली बोर्ड 1967 में बना। उससे पहले संयुक्त पंजाब में सिरसा की एक निजी कंपनी होती थी जो सिरसा, हिसार, भिवानी और रोहतक के क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने का काम करती थी। वह भी एक निजी कंपनी थी, जिसे बाद में पब्लिक सैक्टर में लाया गया था। उसको बाकायदा टेक-ओवर किया गया था। लेकिन आज ये बिल्कुल उल्टी ही गंगा बहाने जा रहे हैं। आज फिर बिजली बोर्ड के निजीकरण की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, निजीकरण केवल विकसित देशों के लिए तो ठीक है लेकिन जो विकासशील देश हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी को निजीकरण तोड़ देगा। इसलिए जो पॉवर रैगुलेटरी कमीशन बनाया गया है उस बारे में मेरा सुझाव है कि they should scrap it. क्योंकि यह कार्यवाही सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पर अतिरिक्त बोझ ही होगी।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से श्री संपत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे केवल अच्छे सुझाव ही सदन के सम्मुख रखें जिन पर हमारी सरकार विचार कर सके। संपत सिंह जी जैसे नेता से हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि वे इस तरह की फिजूल बातें सदन में करें। आज पूरा देश बिजली के सुधारीकरण की प्रशंसा कर रहा है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिजली के सुधारीकरण के बारे में हमारी सरकार के कार्यक्रम को विस्तार से बताया है। अच्छा तो यह होता कि ये चौधरी बंसी लाल द्वारा उठाए गए इस ठोस कदम की प्रशंसा करते लेकिन इसके विपरीत ये विधान सभा में विरोधस्वरूप इस कदम की मुखालफत कर रहे हैं जिसका सदन की नज़रों में कोई वजन नज़र नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से इन से फिर अनुरोध करूंगा के वे सदन में केवल अच्छे सुझाव व अच्छी बातें ही रखें तथा सदन का समय बर्बाद न करें। (शोर एवं विघ्न)

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 4000 करोड़ रुपये की बिजली बोर्ड की लायबिलिटी है और इस एग्रीमेंट के अनुसार यह सारी की सारी लायबिलिटी राज्य सरकार

[श्री सम्पत सिंह]
ओन करेगी। इसके अतिरिक्त जहां तक असैट्स की बात है, इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस एग्रीमैंट के पेज-2 पर आप पढ़े जिसमें लिखा है–

"H.S.E.B. will re-value its fixed assets by about 50%"

इस प्रकार असैट्स की वैल्यूएशन तो 50 प्रतिशत पर होगी और लायबिलिटी सारा स्टेट लेगा तो इसकी इकॉनामी कहां रहेगी ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इस एग्रीमैंट में 24 घंटे बिजली देने के स्थान पर बिजली आपूर्ति में कटौती की बात की है, जिसके बारे में एग्रीमैंट में लिखा है--

"During the next 4 to 5 years, it will not be possible to fully meet the demands of power and therefore, the power supply will have to be curtailed."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ये कैसे कह सकते हैं कि ये 24 घंटे बिजली देंगे। यहां एग्रीमैंट में तो बिल्कुल उल्टा ही लिखा है कि 4-5 साल तक तो बिजली की खपत को करटेल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अच्छे सुझाव दें। (विघ्न) मैं अच्छे सुझाव ही दे रहा हूं। ये तो किसी भी तरीके से अपना समय जैसे-तैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बचकर निकलना चाहते हैं। हमारे अच्छे सुझाव तो इनको जंचते नहीं है। जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, उस से तो और वित्तीय उलझनें/अड़चनें पैदा होंगी। अध्यक्ष महोदय, इनकी इस कार्यवाही से वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कृषि उपभोक्ताओं पर 37 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तथा बाकि उपभोक्ताओं पर 8-10 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में यह अतिरिक्त बोझ 33 प्रतिशत तथा वर्ष 2001-2002 में यह बोझ 25 प्रतिशत का और पड़ेगा व वर्ष 2002-2003 में 41 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो मीटर्ड और अनमीटर्ड बिजली की सप्लाई 55 पैसे प्रति यूनिट पड़ रही है, बाद में यह 174 पैसे प्रति यूनिट पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इन सारी बातों का सदन के अंदर जिक्र नहीं करूंगा तो हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की इस कार्यवाही से किसानों पर साढ़े-तीन गुना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तथा 8-10 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ प्रति वर्ष आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, रिनोवेशन और माडर्नाईजेशन से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लौसिज़ कम हुआ करते हैं लेकिन इसके विपरीत ये लौसिज़ बढ़ रहे हैं। 1995-96 में ये लौसिज़ 28.13 प्रतिशत थे जो 1996-97 में बढ़कर 37.71 प्रतिशत हो गए, वर्ष 1997-98 में यो लौसिज़ 32.15 प्रतिशत हो गए तथा 1998-99 की फिगर अभी आनी है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भी ये लौसिज़ ३३ प्रतिशत से ज्यादा ही होंगे। अगर यही हालत रहेगी तो इतना ज्यादा कर्ज लेकर खर्च करने का क्या औचित्य है कि इसके बावजूद भी उत्तरोत्तर बिजली की चोरी बढ़ ही रही है। दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि बिजली की चोरी रुकी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भिवानी में एक विजीलैंस टीम भेजी थी यह एक अलार्मिंग बात है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली चोरी भिवानी में होती है और हो रही है परंतु उन चोरियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि कहीं यह भेद न खुल जाये कि बिजली चोरी करने वाले इंडस्ट्रीयलिस्ट को किसका संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उस टीम को वहां से वापिस बुला लिया गया। अध्यक्ष महोदय, बिजली चोरी के मामले में पहले जो एफ०आई०आर० फोरन दर्ज की जाती थी उसमें 48 घंटे का गैप डालने के आदेश हो गये हैं क्योंकि अगर एफ०आई०आर० लोज करेंगे तो उस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन इनके आदेश के अनुसार छापे मारने के 48 घंटे बाद एफ०आई०आर० लोज की जायेगी ताकि बाद में राजनैतिक दखल आ जाये और दोषी व्यक्तियों को बचाया जा सके।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, शायद चौ० संपत सिंह जी को मालूम नहीं है कि भिवानी में क्या हुआ ? ये जो कुछ भी कह रहे हैं इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ये हमारे साथ भिवानी में चलें और हम इनको रिकार्ड दिखायेंगे कि जो भी बिजली की चोरियां हुई हैं उनके कितने केस दर्ज हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग दोषी थे सभी को पकड़ा गया है। किसी को भी नहीं छोड़ा। चाहे वह किसी का भी आदमी हो। जिन फैक्टरियों के मालिक गड़बड़ी कर रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी संपत सिंह जी भिवानी में आयें हम इनको बता देंगे कि कितने लोगों को पकड़ा गया है और कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं। यहां तक कि जो दोषी पकड़े गये हैं उनकी जमानतें भी नहीं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो आम जनता को कहते हैं कि आप लोग बिजली का बिल मत भरो और लोगों से बिजली की चोरियां करवाते हैं। (शोर) ये जो कह रहे हैं कि विजीलैंस टीम को वापिस बुला लिया गया इनको उस बारे में मालूम ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह टीम वहीं पर है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बैठ जायें।

Shri Sat Pal Sangwan : Speaker Sir, I can show you the record and I can give you the F.I.R. No. even.

Mr. Speaker : Dr. Virender Pal, please take your seat (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी संपत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जो सच्चाई है उसको मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि आज चौधरी संपत सिंह जी विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम जो बिजली का उत्पादन हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल केवल हरियाणा विकास पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करेगी बल्कि प्रदेश की पूरी जनता करेगी। अध्यक्ष महोदय, इनको तो लोगों को यह कहना चाहिए कि सरकार यह अच्छा काम कर रही है। इसमें हम भी सरकार की मदद करेंगे। चौ० संपत सिंह को बिजली की बात से तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि सरकार इस कार्य को जल्दी ही पूरा कर लेगी और हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने के अपने वायदे को पूरा करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन विपक्ष वालों का तो मेन मकसद यह है कि ये लोगों को गुमराह करें लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं तो बिजली के बारे में ये भी हमारी प्रशंसा करते हैं। आज इन्होंने आरोप लगाये हैं कि भिवानी में बिजली की चोरियां हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी भिवानी के रहने वाले हैं। आज कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी सरकार ने किसी दोषी के प्रति अपने रवैये में कोई ढील दी है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी बिजली की चोरी पकड़ी जाती है तो उस दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उसके खिलाफ विभाग अलग से कार्यवाही करता है और पुलिस अलग से कार्यवाही करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी नीतियां गलत हैं तो वे अपनी योजनाएं हमें बतायें लेकिन उन्होंने हमें कोई भी सुझाव नहीं दिया। ये तो सिर्फ हमारी आलोचना ही कर रहे हैं।

13.00 बजे **श्री सम्पत सिंह :** स्पीकर साहब, अभी मेरे माननीय साथी कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि जब हम अकेले बैठते हैं तो बात करते हैं। उन बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा कि आप और हम अकेले में क्या-क्या बात करते हैं। स्पीकर साहब, ऐसे बहुत से साथी हैं जो पता नहीं अकेले में क्या-क्या बातें करते हैं। वह तो समय ही बताएगा और सारा हरियाणा उन बातों को जान जाएगा। आपको भी उन बातों का पता लग जाएगा। मैं इस समय उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप रहने दें चौधरी भागी राम जी बता देंगे। (हंसी)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मिले हम बहुत खुश है। यह बहुत बढ़िया काम है। लेकिन आज प्रदेश के हालात यह हैं कि बिजली के लिए लोगों को रास्ते जाम करने पड़ते हैं। चक्का जाम करना पड़ता है। इनका घेराव किया जाता है। क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। स्पीकर साहब, अब मैं इरीगेशन के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस सरकार के आने से पहले सारी पार्टियों ने इनकल्यूडिंग इस समय के मुख्य मंत्री ने बार-बार जमना अकोई का डट कर विरोध किया था। उस समय इन्होंने रोहतक की एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हम इसके खिलाफ जन आन्दोलन करेंगे, बगावत करेंगे। चौ० बंसीलाल जी ने कहा था "भजन लाल ने खुराने के आगे घुटने टेक दिए"। लेकिन अब इनकी सरकार आई तो इन्होंने मान लिया कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ जो कुछ हो गया वह सही है। अब ये जमना अकोई के बारे में कुछ नहीं कहते। इसके अलावा ये अब हथनी कुण्ड बैराज की बात करते हैं। हथनी कुण्ड बैराज तो इस सरकार से पहले का है। उसके लिए 1994 में लोन मंजूर हुआ था। उस समय 1858 करोड़ रुपये का लोन इसके लिए मंजूर हुआ था। हरियाणा वाटर रिसोर्सिज कंसोलीडेशन प्रोजैक्ट में हथनी कुण्ड बैराज शामिल था यह तो पहले की योजना है। आज आप जमना अकोई का जिक्र नहीं करते, आज आप एस०वाई०एल० कैनाल का जिक्र नहीं करते। आप रावी व्यास के पानी का कोई जिक्र नहीं करते। इसी तरह से आप आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का कोई जिक्र नहीं करते। आगरा कैनाल के नीचे जो माइनर्ज हैं उनकी सफाई का काम आपने कागजों में दिखा दिया। मुख्य मंत्री जी ने पलवल में कहा था कि आगरा कैनाल का कंट्रोल तीन महीने के अन्दर हम अपने हाथ में ले कर रहेंगे वरना हम लैंड एक्वायर करेंगे और लैंड एक्वायर करके आगरा कैनाल को अपने कब्जे में लेंगे। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन के नोटिस का क्या हुआ। स्पीकर साहब, जब ये सिरसा में जाते थे तो ये कहते थे कि हम हरिके पत्तन से पानी लाएंगे। ये हरि के पत्तन से पानी लाने की ही बात नहीं करते बल्कि इन्होंने तो कहा था कि हम गंगा से पानी ला कर देंगे। स्पीकर साहब, गंगा के पानी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है फिर ये गंगा का पानी यहां कैसे ला सकते हैं, फिर भी ये कहते थे कि हम गंगा का पानी लाएंगे। एक काम हो रहा है अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उनके फूल बहाने लोग हरिद्वार जाते रहते हैं और वहां से गंगा जल लाते रहते हैं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जब संपत सिंह जी बिजली की बात से संतुष्ट हो गए तो अब ये पानी की बात पर आ गए। स्पीकर साहब, इन्होंने हथनी कुण्ड बैराज का जिक्र किया है। मैं इनको इस बारे में सन्तुष्ट करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन आज आप इस देश की हालत देख रहे हैं कैसी है। स्पीकर साहब, संपत सिंह जी की सरकार रही, पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उन सरकारों ने हथनी कुण्ड बैराज का काम शुरू क्यों नहीं करवाया ? उस पर खर्च किया गया पैसा केवल कागजों में ही दिखा दिया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी को तो हमारी सरकार को मुबारिक बाद देनी चाहिए कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर हथनी कुण्ड बैराज को बनाने के कार्य में दिन-रात लगी हुई है। चौधरी सम्पत सिंह जी जानते हैं कि उस बैराज के पूर्ण होने पर हरियाणा प्रदेश के किसानों की सिंचाई की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ जायेंगी। सम्पत सिंह जी आगरा नहर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। (विघ्न) आगरा नहर के बारे में मैं चौधरी सम्पत सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में पिछली सरकारों ने इस नहर से पानी लाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया

था। हमारे एरिया में इस नहर के जो रजबाहे लगते थे उनमें 20-20 साल से पानी नहीं आ रहा था और उस एरिया के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार के आने के बाद हमें उस नहर का पानी उन रजवाहों के माध्यम से मिल रहा है। यह कोई छोटा काम नहीं है।

Sh. Sampat Singh : Speaker Sir, I want to know whether they have taken over administrative control of that canal.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आगरा नहर का पानी 20 साल के बाद हमारे इलाके में आया इसके लिए मैं चौधरी बंसी लाल जी का धन्यवाद करता हूं। चौधरी संपत सिंह जी आप हमारे इलाके में आएं। जहां आगरा कैनाल का पानी हमारे रजवाहों में पिछले 20 सालों से देखने को नहीं मिलता था आज वही रजवाहे इस नहर के पानी से चल रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारी सरकार नहरी पानी की व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दे रही है और इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जैसी परम्परा डालें वह डालें क्योंकि आप इस चेयर पर बैठे हैं आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस को सवाल जवाब का सैशन बना दिया है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह के सवाल जवाब का सैशन आखिरी दिन तक चलाते रहें। स्पीकर महोदय का काम होता है कि अगर कोई मंत्री गलत बयान करता है तो उसको निर्देश दें कि वह सही जवाब दे। अभी कर्ण सिंह जी ने आगरा कैनाल के बारे में कुछ कहा ये ओन-ओथ कह दें कि इन्होंने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है तो हम इनकी बात को मान लेंगे। ये साथ ही ये भी ओन-ओथ कह दें कि जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो उस वक्त कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो इसका कंट्रोल हम अपने हाथ में लेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पत सिंह जी को बताना चाहता हूं कि जब मैं विपक्ष में होता था तब मैंने कभी यह नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसका कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेंगे। उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में हमारे सिंचाई मंत्री जी कई बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं और इस बारे में यू०पी० सरकार से बात कर चुके हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, अभी तक इन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? जो इन्होंने कहा है this is not the reply. अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा कैनाल की मेन्टीनेंस न होने की वजह से हमें उस नहर से 1600 क्यूसिक्स पानी कम मिल रहा है। केवल मात्र उस नहर की सफाई करवाने के लिए पैसा पंजाब के पास जमा करवाने से बात नहीं बनती। सरकार को चाहिए कि पंजाब के एरिया में उस नहर की सफाई का काम तेजी से करवाये ताकि हमें जो 1600 क्यूसिक्स पानी कम मिल रहा है, वह पूरा मिल जाये। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्होंने हथनी कुंड बैराज का जिक्र किया। इसको बनाने के लिए 1994 में पैसा मंजूर हो चुका था।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी अपनी स्पीच में आगरा कैनाल और हथनी कुंड बैराज का जिक्र कर रहे हैं। इस बारे में चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी भी पहले कह चुके हैं कि इनको चौधरी भागी राम जी के साथ कम्पेयर न करें क्योंकि उनका स्टेट्स दूसरा है और इनका स्टेट्स दूसरा है। (विघ्न) जहां तक आगरा कैनाल के कंट्रोल का सवाल है, उसकी बात को छोड़ें। (विघ्न) मरे हुए हाथी से हमें क्या लेना है। उसके कंट्रोल से हमें क्या लेना है। उससे हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव का थोड़ा सा हिस्सा सिंचित होता है। आगरा कैनाल से मथुरा, आगरा, यू०पी० के जिले अलवर, भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के जिले सिंचित होते हैं। इसलिए आगरा

[श्री हर्ष कुमार]

कैनाल के कंट्रोल से हमें क्या लेना है। सन् 1966 में हरियाणा बना और 30 साल के बाद 1996 में हमारी सरकार ने आगरा कैनाल की चैनल्ज़ का कंट्रोल 100 प्रतिशत अपने हाथ में लिया है। उन चैनल्ज़ की सफाई, उनके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंजीनियर्ज़ करते हैं। उनकी मुरम्मत का कार्य उनके जो छोटे-मोटे पुल हैं उनकी मुरम्मत का काम हमारे इंजीनियर्ज़ कर रहे हैं। आज आगरा कैनाल की चैनल्ज़ की एक-एक टेल एंड पर पानी पहुंच रहा है। गुड़गांव और फरीदाबाद का पूरा कमाण्ड एरिया उनसे सिंचित हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे फालतू कंट्रोल की बात और कोई नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से इससे हमारा परपज़ हल हो गया है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी बीच में बोल रहे हैं। उनके महकमें की चर्चा हुई है इसलिए उनको नोट करना चाहिए और बाद में उनका रिप्लाई आना चाहिए। इण्टरवीन करने की जो प्रथा डाली जा रही है वह चेयर की गरिमा पर चोट है। मंत्री जी बार-बार इन्टरवीन कर रहे हैं यह आपका अधिकार है आप उनको इससे रोकें।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ मजबूरी यह है कि जब हम इनकी बात का जवाब देना शुरू करते हैं तो ये लोग उस समय हाउस में नहीं होते, इसलिए जवाब बीच में देना पड़ रहा है।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी भजन लाल जी भी यही कह कर चले जाया करते थे, वही बात आप भी कर रहे हैं। हर्ष कुमार जी, आप बहुत अच्छे इन्सान हैं और मंत्री भी हैं, मेरी गुजारिश है कि आप बीच में इन्टरवीन न करें। (विघ्न एवं शोर) * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी धीरपाल सिंह जी, आप बैठें जो यह कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं बार-बार क्या कहूं यह अच्छा नहीं लगता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, धीरपाल जी आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। (विघ्न) चौधरी सम्पत सिंह जी आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है। आप जल्दी खत्म करें।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। मेरा समय तो बार-बार इन्ट्रप्ट करने में चला गया है। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया है। * * * *

श्री अध्यक्ष : यह जो सम्पत सिंह जी कह रहे हैं वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री सम्पत सिंह : * * *

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी मैं यहां पर नहीं था जब नृपेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे लेकिन उनको भी काफी इंट्रप्ट किया गया था। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें कि किसने इन्ट्रप्ट किया था। * * *

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट में अपनी बात कम्पलीट करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी ध्यान से इनकी बात सुनें।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जो लोगों की पीड़ा है उस पीड़ा के बारे में यहां पर बताना हमारा फर्ज है और इस बारे में मैं बार-बार यहां पर कह रहा हूँ। इनको चाहे कोई तकलीफ हो, ये चाहे मुझे रोकने की कोशिश करें लेकिन मैं उनकी बात यहां पर कहूंगा। आज इनकी बूट मैजोरिटी है। मैं इनमें

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

से किसी के बारे में पर्सनल बात नहीं कहूंगा क्योंकि इन लोगों की हमको जरूरत है ये लोग किसी भी समय हमारे काम आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी कम्पलशन है इस वजह से मैं इनके बारे में कुछ जिक्र नहीं करूंगा चाहे आप कितना भी मुझे प्रवोक कर लें। इसलिए स्पीकर साहब, फार दि लार्जर इन्ट्रस्ट में इनके साथ ऐसा नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस 1858 करोड़ रूपये के प्रोजैक्ट की बात कर रहा था उसमें वर्ल्ड बैंक का 975 करोड़ रुपये का शेयर था। यह बहुत ही बड़ा प्रैस्टीजियस प्रोजैक्ट था। उसमें सारी नहरों की माडर्नाइजेशन होनी थी और सारे सिस्टम की रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी। इसी के साथ ही रिहैबीलीटेशन होनी थी। लेकिन सरकार की कोताही की वजह से साढ़े चार साल खत्म होने जा रहे हैं, इतने समय में इसका 1/3 काम भी नहीं हुआ है। उसका काम कितना हुआ है वह मैं आपको बता देता हूँ। सिम्पल वर्क्स पर जैसे ड्रेनों से मिट्टी निकालने का काम हुआ है यानी जिस काम में कमीशन खानी थी, पैसा खाना था वही काम हुआ है। सर, स्ट्रक्चर वर्क्स का काम है, मेन कैनाल का काम है, चैनल और ब्रान्चिज़ का काम है अगर उन कामों की परसैन्टेज बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। आपको भी पता चलेगा कि पानी और नहरों के मामले में ये लोग कितने सीरियस है। स्पीकर साहब, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरैक्टर जो इंडिया के लिए हैं उनका नाम एडमिन आर०लिन है। उन्होंने लिखा है Ineffective project management at the senior level i.e. in Haryana's Irrigation Department as well as at the Government level has prevailed and is the root cause for the present unsatisfactory situation. उनके अनुसार लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच में इतना बड़ा अन्तर है। स्पीकर साहब, ये हालात उस प्रोजैक्ट के हैं। अब ये क्या करेंगे ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक वालों ने थ्रैट किया है जो यह है :-To cancel the part of the credit or even suspend the credit. स्पीकर साहब अगर ये हालात होंगे तो हमारे सारे के सारे प्रोजैक्ट रह जाएंगे। (विघ्न)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये वर्ल्ड बैंक की जिस थ्रेट की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक तो इसको और आगे बढ़ाने जा रहा है। वह हमारे काम से पूरी तरह से सैटिसफाईड है। मेरा सम्पत सिंह जी से कहना है कि वे भजन लाल जी के समय की चिट्ठियां हमारे समय में लागू न करें।

श्री सम्पत सिंह : सर, यह जून, 1998 की बात है क्या उस समय भजन लाल जी थे ?

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप यह लैटर हर्ष कुमार जी के पास भिजवा दें।

श्री सम्पत सिंह : सर, यह जून, 1998 की बात है। मैं यह चिंता जाहिर कर रहा हूं कि अगर इस तरह के प्रौजैक्टस के लोन कैंसिल हो जाएंगे तो फिर इनकी सारी की सारी स्कीम धरी की धरी रह जाएंगी।

श्री हर्ष कुमार : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : हर्ष कुमार जी, चौधरी सम्पत सिंह जी अभी इरीगेशन पर बोल रहे हैं इसलिए पहले इनको अपनी बात पूरी कर लेने दें। उसके बाद आप बोल लेना। अभी आप बैठें।

श्री सम्पत सिंह : सर, जहां तक यूटिलाइजेशन की बात है। इसमें 975 करोड़ रूपया वर्ल्ड बैंक का शेयर है। उसमें 301 करोड़ 52 लाख रूपये का यूटिलाइजेशन हुआ है यानी वन-थर्ड और जो कुल ऐक्सपैंडीचर हुआ है वह 522 करोड़ रूपये हैं। यह ऐक्सपैंडीचर 1858 करोड़ रूपये में से हुआ है। इसका मतलब 1361 करोड़ के अगेन्स्ट 38 परसैंट टोटल ऐक्सपैंडीचर हुआ है। इसी तरह से

[श्री सम्पत सिंह]

अस्टैब्लिशमैंट पर 496 करोड़ रूपया रखा गया था उसमें से जून तक 425 करोड़ रूपया खर्च हो चुका था। इसका मतलब अस्टैब्लिशमैंट पर टोटल खर्चा हो चुका है। सर, अस्टैब्लिशमैंट की तो वाह-वाह है आगे ये अस्टैब्लिशमैंट कैसे चलाएंगे। सर, इस तरह से ये अन-प्रोडक्टिव कामों पर खर्च कर रहे हैं और प्रोडक्टिव कामों पर खर्च नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मोडर्नाइजेशन हैड में मेन कैनाल पर केवल दो परसैंट काम हुआ है और स्ट्रक्चर पर 12 परसैंट तथा डिस्ट्रीब्यूटरी पर 18 परसैंट काम हुआ है। पथराला प्रौजैक्ट जो दादूपुर के नजदीक पड़ता है तथा बूढेड़ा प्रौजैक्ट जो थानेसर के नजदीक है और ओटूवियर प्रौजैक्ट जो सिरसा में है। सरकार के ये तीन बड़े प्रौजैक्टस हैं इनके लिए भी 1858 करोड़ रुपये में से ही लोन सैंक्शंड है लेकिन इन तीनों पर एक कस्सी मिट्टी का भी काम नहीं हुआ है। क्या एक साल और पांच महीने में यह सरकार इन तीनों प्रौजैक्टस को पूरा कर लेगी ? जब आज तक ये पूरे नहीं हो पाए हैं तो आगे ये कैसे पूरे हो पाएंगे ? इस प्रौजैक्ट में इन्होंने एक आवियाना वाली क्लॉज लागू करवायी है जिसके अनुसार हर वर्ष दस परसैंट आवियाना बढ़ा कर लेने में प्रोम्पट रहे हैं लेकिन अगर इन तीनों प्रौजैक्ट्स पर पूरी तरह से काम हो जाता तो हरियाणा प्रदेश की जल की समस्या खत्म हो जाती, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती और सेम की समस्या खत्म हो जाती। आज के दिन भी नरवाना, राजौंद, सफीदों, नारनौंद, घिराय, जुलाना, दड़वा, नूह, फतेहाबाद और रोड़ी के इलाकों में हजारों एकड़ जमीन में सेम का पानी खड़ा हुआ है। वहां की जमीन बिना बोए ही रह गयी है। लेकिन सरकार ने तो एक ही शब्द सीख लिया है कि हम इस बारे में एक मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। हमें यह नहीं पता लगता कि मास्टर प्लान है क्या ? इनके इस बारे में रोजाना अलग-अलग बयान आते रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि 2300 करोड़ रुपये और दूसरा कहता है कि 2600 करोड़ रूपये और जब इस बारे में कैबिनेट का फैसला हम सुनते हैं तो पता लगता है कि इसके लिए केवल 45 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट्स है। सर, अब हम किसकी बात सही माने। (विघ्न) सर, मैं अब अगली बात कहना चाहूंगा। मैं अगर पावर पर बात करता हूं तो इनको दिक्कत होती है और अगर इरीगेशन की बात करता हूं तब फिर इनको दिक्कत होती है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, सम्पत सिंह जी पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी जो आंकड़े सुना रहे हैं ये सच्चाई से दूर हैं। रोहतक जिले की बात तो मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं वहां ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग में जाता हूं रोहतक जिले से विधायक भी यहां बैठे हैं और वे खुद मानते हैं कि नालों की सफाई व सिंचाई इत्यादि का काफी काम हुआ है।

श्री सम्पत सिंह : मैं प्रौजैक्ट्स की बात कर रहा था। ये वहां के बारे में जानते तो हैं नहीं, इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री हर्ष कुमार : चौधरी सम्पत सिंह जी मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगा। आप भी इरीगेशन मिनिस्टर रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आंकड़े आप यहां दें वे सही हों। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं और हो सकता है कि अनुभव में भी छोटा हूं परन्तु आपने जो अस्टैब्लिशमैंट पर डब्ल्यू०आर०सी०पी० का 425 करोड़ का खर्च बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मद में यदि एक नया पैसा भी खर्च हुआ होगा तो मैं आज ही इरीगेशन महकमा छोड़ दूंगा। इस तरह की गलतबयानी आप यहां न करें।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, इरीगेशन मिनिस्टर का यह दावा है कि अस्टैबलिशमैंट पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ, आप इस बारे में क्या कहते हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बारे में मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है Speaker Sir, don't try to bail them out. यह जो आंकड़े मैंने दिये हैं यूं ही नहीं दिये हैं मेरा अफसोस यह है कि मुझे भैंस के आगे बीन बजानी पड़ रही है।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह महसूस करता हूं कि भैंस के आगे बीन बजाना बेवकूफी है। चौधरी सम्पत सिंह जी, आज इस चीज का फैसला करें कि भैंस में था आप, बीन बजाने वाले आप या मैं। (शोर)

Mr. Speaker : I think he is right.

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके आंकड़ों की बात नहीं करता कि इनको वह आंकड़े कौन देता है। आप सरकार के खजाने के रिकार्ड से पता कर लें मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूं। कि अस्टैब्लिशमैंट पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी सम्पत सिंह जी आप इनकी बात का कोई प्रूफ दें।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हम तो इस्तीफा देकर भी बहुत बार वापस चुनाव जीतकर आये हैं परन्तु ये हमारे साथी आज मंत्री हैं इस बारे में हमें बहुत खुशी है। मैं इनको अपदस्थ नहीं देखना चाहता।

श्री अध्यक्ष : आप इनकी बात का जवाब दीजिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि अगर सिंचाई मंत्री जी की बात चौधरी सम्पत सिंह जी नहीं मानते हैं तो हाऊस की एक कमेटी बना दी जाए।

श्री सम्पत सिंह : अगर ऐसा होगा तो हम तो हाऊस की सैंकड़ों कमेटियां बनवायेंगे फिर तो कमेटियां बनती जायेंगी। स्पीकर सर, इस प्रोजैक्ट के बारे में एक कमेटी बनाई जाए। इस टोटल प्रोजैक्ट की वर्किंग पर कमेटी बना लें, इसके लिए मैं सहमत हूं।

श्री रमेश कुमार : स्पीकर सर,..... (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठिये। (Shri Ramesh Kumar continued to interrupt)

Mr. Speaker : Ramesh Kumar ji, I warn you. (Interruptions) I again warn you. मंत्री जी आप एक मिनट में पूरा कीजिए।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी सम्पत सिंह जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे अन्दर इनके प्रति बड़ी इज्जत है और मैं इनको अपने से बड़ा मानता हूं। इनसे कुछ सीखना भी चाहता हूं। इनके तजुर्बे से कुछ लाभ उठाना चाहता हूं। लेकिन शायद आप अपनी पहली वाली आदर्शता की नीति से और अपने चरित्र से भटक गये हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने पथराला गांव का जिक्र किया, पथराला गांव के काम का टैण्डर फलौट हो चुका है। उसका काम इतना जल्दी शुरू नहीं हो सकता क्योंकि टैण्डर आने में भी थोड़ा समय लगेगा। जहां तक ओटू डैम का मामला है उसका भी लगभग काम शुरू होना बाकी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि काम शुरू होने में बहुत फार्मलिटीज पूरी करनी होती हैं। यह सरकार जनता के खजाने से खिलवाड़ करना नहीं चाहती। जो लोन लिये गए हैं उनका सोच समझकर इस्तेमाल करेगी। ऐसा न हो कि जल्दबाजी में कहीं उस लोन का दुरूपयोग हो जाये। सौ तरह की बातें होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारे काम में इस लोन का दुरूपयोग न हो, सदुपयोग हो।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप जल्दी कंक्लयूड करें।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि यह सरकार साढ़े चार साल तक सोचती ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी ? (विघ्न) स्पीकर सर, यह तो कंटीन्यूअस प्रोसैस है चाहे पहले कोई सरकार रही हो लेकिन इस सरकार को पौने तीन साल हो गये हैं ये पौने तीन साल तक सोचते ही रहे और इन तीनों प्रोजैक्टों का काम शुरू नहीं किया। स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि जो 1858 करोड़ रुपये का बाटर प्रोजैक्ट का मामला है और 2400 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक के लोन का मामला है इन दोनों के बारे में आप एक कमेटी बैठा दें इसके लिए मैं सहमत हूं। अब मैं अन्य विभागों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सत्ता में आने से पहले ये बार-बार कर्मचारियों और व्यापारियों के बारे में जिक्र करते थे कि हम आपकी भलाई के लिए ये-ये काम करेंगे लेकिन आज कर्मचारियों की क्या हालत है। उनके लिये पांचवे पे-कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, उनको भत्ते देने की बात थी लेकिन पांचवे पे-कमीशन की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू करने की बजाय या उनको पूरे भत्ते देने की बजाय कम दिये गये। अगर आज कर्मचारी उस बारे में आवाज भी उठाते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। यहां तक कि उनको डिसमिस कर दिया जाता है। जैसे बिजली बोर्ड के 1700 कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग की 34 नर्सों को, पर्यटन विभाग के 47 कर्मचारियों को और 15 पुलिस कमाण्डोज़ को डिसमिस कर दिया गया। स्पीकर सर, आज वे सर्विस से अलग हो गये हैं। इसी तरह से परिवहन विभाग और दूसरे महकमों में है।

श्री अतर सिंह सैनी : स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड के 1700 कर्मचारी तो सुप्रीम कोर्ट ने हटाये हैं।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाये हुये नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हटाये हैं, वे अलग हैं। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड में कर्मचारी यूनियन के जनरल सैक्रेटरी मिस्टर जग्गा हैं उनके साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया, मानो 1920 में अंग्रेजों के टाईम की पुनरावृत्ति की हो। 1920 में लोकमान्य तिलक ने टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज, बम्बई की लेबर की बात उठाई थी और उस वक्त उन पर जुर्माना लगाया गया था कि आपने काम में गड़बड़ कराई है। उसी तरह से मिस्टर जग्गा को इन्होंने 15 लाख रुपये का आरोप पत्र थमा दिया कि आपकी वजह से बिजली बोर्ड में हड़ताल हुई और आपकी वजह से बहुत नुक्सान हो गया है। यही हालत आज व्यापारियों की है। आप कहते हैं कि टैक्सों का सरलीकरण करेंगे। चुंगी खत्म करेंगे, टैक्स कम करेंगे, इन्सपैक्ट्री राज समाप्त करेंगे। लेकिन सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों का सवाल है, आज हरियाणा में 180 आई०ए०एस० अधिकारियों का कैडर है और 140 वास्तविक स्ट्रैंथ है और 140 में से 68 एफैक्टिड है जिनको या तो सस्पैंड किया गया है, या ए०सी०आर० डाऊन मार्क की गई है या फिर चार्ज शीट इशू की गई है। यही हाल आई०पी०एस० अधिकारियों के साथ हो रहा है। उनको भी चार्जशीट देकर सस्पैंड करके प्रशासनिक मशीनरी को ठप्प कर रहे हैं। एक केस में तो कोर्ट ने सरकार को सी०बी०आई० से जांच कराने को कहा और सी०बी०आई० ने उस अधिकारी को निर्दोष माना तो ऐसे में सरकार कहां स्टैण्ड करती है। इसी तरह की पोजीशन हमारी एच०सी०एस० सर्विस की है जो कि हमारी स्टेट की प्रीमियर सर्विसिज़ हैं इनमें से प्रमोट होकर आई०ए०एस० भी बनते हैं परन्तु प्रमोशन कोटे के आज भी 35 पद खाली पड़े हैं। अभी तक इन्होंने डी०पी०सी० की मिटिंग नहीं बुलाई है। मेरा अंतिम प्वाएंट कानून और व्यवस्था के बारे में हैं। इस बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। आज सुबह प्रश्नोत्तर-काल के समय कानून व्यवस्था

के बारे जो आंकड़े सामने आये थे उन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि people are living under the shadow of criminals. जब शराब बंदी लागू करने की बात थी तो उसको हमने भी स्पोर्ट किया था लेकिन शराब बंदी लागू करने से प्रदेश में एक शराब माफिया बन गया। एक महीने बाद जो रिजल्ट्स आये तो ये लोग माफिया के रूप में शराब बेचने लगे। वह काम भी सरकारी संरक्षण प्राप्त लोग ही कर रहे थे। नये-नये हथियार लेकर, गाड़ियां लेकर और सैल्यूलर फोन के जरिये बाहर से शराब लाकर हरियाणा प्रदेश में बेचते थे। वह शराब माफिया अपराध माफिया बनता जा रहा था तब हमने उसका विरोध किया।

Mr. Speaker : Sampat Singh ji, please conclude.

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमने कहा था कि शराब माफिया एक अपराध माफिया बनता जा रहा है, उसे रोको।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री सम्पत सिंह : सर, मैं लॉ एण्ड आर्डर की कुछ बातें कह कर अभी कन्क्लूड कर रहा हूं। हमने कहा था कि जो शराब माफिया क्राइम माफिया बन गया है इसे रोको अगर उस वक्त हमारी बात सुनते तो इनको ***** न पड़ता और अपना शराब बन्दी का फैसला वापिस न लेना पड़ता और आज शराब माफिया अपराध माफिया न बनता।

श्री अध्यक्ष : थूक कर चाटना शब्द रिकार्ड न किया जाए।

वाक-आउट

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून और व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं। *****

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (Interruptions). Whatever is being said by Shri Sampat Singh will not go on record.

Shri Sampat Singh : Sir, kindly allow me to conclude my speech...

Mr. Speaker : I have requested you so many times to conclude your speech but you have not concluded then. (Interruptions) Now it is final that you cannot speak.

Shri Sampat Singh : Sir, kindly review your decision.

Mr. Speaker : No. I would not review it. You please take your seat.

(इस समय बहुत से सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप हमें बोलने के लिए समय ही नहीं देते हैं तो हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित लोकदल (राष्ट्रीय) के सभी सदस्य सदन से वॉक-आऊट कर गए)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by half an hour.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by half an hour.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती करतार देवी (कलानौर-एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने लोकतांत्रिक परम्परा के अनुसार हम सभी सदस्यों को अपने अभिभाषण द्वारा संबोधित किया है। सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों का जो प्रारूप अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय को दिया गया उसको उन्होंने पढ़ा है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं लेकिन इस सारे प्रारूप को पढ़ने से पता लगता है कि यह सारे का सारा प्रारूप एक असमर्थ, असंवेदनशील और हताश सरकार की गुहार है। जैसे बच्चा पालने में पहुंचने से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है, वैसा ही यह प्रारूप है। इस अभिभाषण को बार-बार देखने से मुझे एक बात याद आती है। दो दोस्त थे और वे दोनों भूखे थे। एक दोस्त ने सुबह उठकर दूसरे दोस्त को कहा कि रात मैंने सपने में दाल रोटी खाई। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा कि अगर सपने में ही खाना खाया था तो कम से कम खीर या हलवा ही खाता। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सरकार का यह प्रारूप भी ऐसा ही लगता है। इस प्रारूप में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है वे ऐसी ही योजनायें लगती हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि चाहे मुझे आप 10 मिनट का ही समय दें लेकिन कोई भी सदस्य बीच में न बोले और मेरी बात ध्यान से सुनें। कम से कम सत्ता पक्ष के सदस्य तो शोर न करें। उन्हें तो सबर रखना ही चाहिए क्योंकि उनको तो कुछ क्रिटीसिज्म सुनना ही पड़ेगा। लेकिन ये सत्तापक्ष के सदस्य शब्दों पर भी झगड़ा करने लगते हैं, यह गलत है। किसी व्यक्ति विशेष की बात हो तो दूसरी बात है लेकिन ये तो सच्चाई को भी नहीं सुनते। इनकी बेसब्री यह दिखा रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। अध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति है उसमें यही लिखा हुआ है कि यह योजना है और यह सरकार के विचाराधीन है। कहीं-कहीं पर यह भी कहा गया है कि इस योजना को सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। यही नहीं बल्कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की प्रोत्साहन स्कीमें आरम्भ किए जाने की बात कही है लेकिन इन्होंने एक भी स्कीम चालू नहीं की है। केवल चालू करने का प्रस्ताव है। इन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनमें से इस साल से एक या दो स्कीम शुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने छोटी सी बात का उदाहरण दिया है। जब इस प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है तो इससे सरकार की असमर्थता नजर आती है और इसकी विल में भी कमी नजर आती है। ये जो कुछ कह रहे हैं उसको पूरा भी कर पायेंगे या नहीं यह इनको मालुम नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि रचनात्मक परिचर्चा की बात होनी चाहिए इसलिए मेरे भी चंद शब्द इस चर्चा में शामिल किये जायें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने लोकपाल की नियुक्ति के बारे में कहा है। यह एक शुभ संकेत है बशर्ते की बदले की भावना से न हो। इसमें एक लाईन बहुत अच्छी कही गई है कि हमारी सरकार सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृतसंकल्प है। यह बड़ी अच्छी बात है। मैं तो यह कहती हूं कि आप लोकपाल की बात को छोड़िए आप अपनी किसी भी एजेंसी के

हजारों नौजवानों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाओ। जिन नौजवानों ने पुलिस में भर्ती के लिए पैसे दिये और भर्ती भी नहीं हुए उन्हें न्याय दिलवाओ। जो पैसे देकर भर्ती हो गये वे तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने पैसे दिये हैं क्योंकि वे तो भर्ती हो गये, लेकिन जो भर्ती नहीं हुए उनसे पूछो भर्ती में कितने पैसे दिये हैं आप इन बातों की ओर ध्यान दें। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे अपनी बात कंक्लयूड करने का मौका नहीं देंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिजली परियोजना की चर्चा है। स्पीकर साहब, इस सरकार को सच्चाई स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सरकार सरकार है। सरकार आती है चली जाती है यह तो एक प्रोग्राम है जो चलता रहता है। पहले भी परियोजनाएं बहुत बनी थीं यह भी सच्चाई है। आपने जिन परियोजनाओं पर प्रैक्टिकली काम किया है यह अच्छी बात है। लेकिन जो नई परियोजनाओं का आपने जनता को झांसा दिया है। यह झांसा आप किसी पोलिटिकल स्टेज पर दे सकते हैं। यहां हाऊस में इस प्रकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। बिजली के बारे में जनता की आवाज है कि बिजली नहीं आती लेकिन बिल जरूर आते हैं। जैसे पहले डोमेस्टिक का बिल 500 रुपए का आता था अब वह 3000 रुपए का आता है और बिजली बोर्ड वाले वह बिल लोगों से वसूल कर रहे हैं। स्पीकर साहब, आश्चर्य की बात यह है कि किसानों पर सरकार की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसान बिजली के बिल नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि सरकार उन दिनों को याद करे जिन दिनों बाढ़ का पानी खेतों में खड़ा था और बिजली की तारें पानी में डूबी हुई होने के कारण सरकार ने खुद बिजली के कनैक्शन कटवाए थे। वे बिजली के कनैक्शन आज तक नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन बिजली बोर्ड ने आज तक यह फैसला नहीं किया कि जिन दिनों में बिजली के कनैक्शन कटे हुए थे उन दिनों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। जब सरकार ने खुद बिजली के कनैक्शन कटवाए तो फिर उन दिनों के बिजली के बिल माफ करने की बात क्यों नहीं की गई। कोई सदस्य या कोई किसान ऐसा नहीं चाहता कि बिजली मिले नहीं और उसका बिल भी भरा जाए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि खेतों में बाढ़ का पानी खड़ा होने के कारण सरकार ने बिजली के कनैक्शन खुद कटवाए। वह कनैक्शन इसलिए कटवाए ताकि पानी में करंट न आ जाए और किसी की जान न चली जाए। वे कनैक्शन आज तक नहीं जोड़े गए हैं लेकिन कनैक्शन कटे रहने के बावजूद भी बिजली के बिल आ रहे हैं उन दिनों के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए हैं ऐसा हमने देखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है और आशा भी है कि सरकार किसानों के बारे में सोचेगी और उन दिनों के उनके बिजली के बिल माफ करेगी जिन दिनों में सरकार ने खुद बिजली के कनैक्शन कटवाए थे। जिस तरह से सरकार ने बिजली के रेटस बढ़ाए उनकी मैं चर्चा नहीं करती। हो सकता है उसमें सरकार को कुछ मजबूरी हो लेकिन मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हर वैल्फेयर सरकार को कुछ न लेने के लिए कमिटमैंट करनी पड़ती है। उसके लिए सरकार पर जो कुछ बोझ पड़ता है उस बोझ को उठाना भी पड़ता है। जनता की भलाई के लिए इस ढंग से बिजली के टैरिफ मुकर्रर करें जिससे जनता का भला हो सके। हम आपकी प्रशंसा करेंगे। बिजली के बारे में आपने जो कम्पनियां बनाई हैं और ज्वायंट वैंचर की बात कही गई है यह ज्वायंट वैंचर धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएगा। मैं इसका विरोध नहीं करती क्योंकि इसमें भारत सरकार के सामने विश्व बाजार की बात आ गई उसमें हरियाणा अछूता नहीं रह सकता। अनाज के राष्ट्रीयकरण की वजह से इसमें आज उदारीकरण है इसी वजह से उत्पादन करने वाले को छूट है, उसको प्रोत्साहन है। उसी तरह से आप किसानों को बिजली के बारे में सुविधाएं दें। जो बिजली आपने किसानों को देनी है, गरीब से गरीब आदमी को उनकी झोंपड़ियों में लट्टू जलाने के लिए देनी है उसकी कीमतों पर कंट्रोल जरूर करें। आप ज्वायंट वैंचर के चक्कर में न पड़ें। अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगी। यह बात सही है कि नहरों की डीसिल्टिंग हुई है। नहरों में से गाद

[श्रीमती करतार देवी]

निकाली गई है। मेरा तो कहना है कि नहरों में यदि पानी ही नहीं होगा तो उनकी टेलों तक पानी कैसे पहुंचेगा। मेरे जिले की यह विशेष समस्या है। मेरे एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री जी ने लिखा है कि एक महीने में नहर 8 दिन चलेगी। यदि नहर महीने में 8 दिन चलेगी और उस दौरान कहीं बीच में नहर कट जाएगी तो जिसकी पानी की बारी होगी उसको एक महीना और पानी नहीं मिलेगा।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि नहर महीने में 8 दिन चलेगी।

श्रीमती करतार देवी : मेरा एक सवाल था उसके लिखित उत्तर में यह कहा गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आप 8 दिन की बजाय नहर को 10 दिन चला दें ताकि किसानों को पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यहां पर हथनी कुण्ड बैराज के बारे में जिक्र किया गया कि यह जून 1999 तक अवश्य पूरा हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि यह जल्दी पूरा हो ताकि लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नई सड़कें बनाने की बात कही गई कि केवल 65 किलोमीटर नई सड़क बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह नई सड़क भी 1-1 किलोमीटर लम्बी सत्तापक्ष के सदस्यों के हल्कों में ही बन पाएगी। इस 1-1 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने के बारे में हमारे हल्कों का नम्बर आने वाला नहीं है। इस साल सरकार केवल मात्र 65 किलोमीटर सड़कें नई बनाएगी तो उसके लिए हम सरकार की क्या प्रशंसा करें। अध्यक्ष महोदय, नई सड़कें तो बनानी दूर की बात रही जो पुरानी सड़कें टूटी पड़ी हैं उनकी रिपेयर भी सरकार अब तक नहीं कर पायी है। टूटी हुई सड़कों की रिपेयर के बारे में सदन के नेता ने कहा था कि सभी टूटी सड़कों की रिपेयर हो जाएगी। इस समय के मुख्य मंत्री जी के बारे में एक समय यह कहा जाता था कि जो यह वायदा करते हैं उसे पूरा करवाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक सड़कों की रिपेयर नहीं हो पायी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार किसी काम को करने का जो वायदा करती है उसे पूरा नहीं कर पाती।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अपने क्षेत्र के जल निकासी के बारे में कहना चाहूंगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि जहां पर बारिश का पानी किसानों की जमीनों में खड़ा हुआ था वहां पर बहुत सी जगहों से अब भी पानी नहीं निकाला गया है। पानी न निकलने के कारण किसानों की तीन-तीन फसलें मारी जा चुकी हैं लेकिन पानी की निकासी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। मेरे हल्के से ड्रेन नं० 8 निकलती है मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उस ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाये बिना और इसमें दो ड्रेन और लाकर डाल दी गई। भगवान न करे 1995 जैसी बाढ़ आ गई तो फिर मेरे हल्के का क्या होगा क्योंकि एक तो पहले ही इस ड्रेन से पानी पूरा नहीं निकल पा रहा था और अब सरकार ने दो ड्रेन उसमें और लाकर डाल दी। अब यदि वैसी बाढ़ आ गई तो इस ड्रेन का क्या हाल होगा, यह भगवान ही जाने। मेरे हल्के के लोग शांति प्रिय हैं। उन्होंने इन दो ड्रेनों को इस ड्रेन नं० 8 में डालने पर कोई प्रोटिस्ट नहीं किया। ये जो दो ड्रेन निकाली गई उनके बारे में मैं शुरू से कहती रही कि इनका लैवल ठीक नहीं है लेकिन उस वक्त मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब इन ड्रेनों में जो पानी खड़ा है उसको पम्पों से उठाकर आगे डाला जा रहा है। जो बात मैं कह रही हूं उससे किसी को दुःखी होने वाली बात नहीं है। मैं सही बात कह रही हूं। इस तरह से जो फिजूल खर्ची किया जाता है उसका जो बोझ पड़ता है वह किसी पार्टी पर नहीं पड़ता बल्कि प्रदेश की जनता पर पड़ता है। जो सही बात नहीं होगी उसको कहने का हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि आपके हल्के के किस गांव की जमीन में अब भी बरसात का पानी खड़ा है।

श्रीमती करतार देवी : खुद मेरे हल्के के मेरे गांव कलानौर की जमीन में बारिश का पानी अब भी खड़ा है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : बहन जी क्या आपने खुद वह ड्रेन बनाये जाने के बारे में मांग नहीं की थी ? जब पीछे बाढ़ का पानी आया था तो उस वक्त केलंगा और खरक व दूसरे गांवों में काफी पानी खड़ा हो गया था। उस वक्त क्या आपने वह ड्रेन बनाने की बात नहीं कही थी ?

श्रीमती करतार देवी : मैंने मांग की थी लेकिन मेरी मांग तो मानी ही नहीं गई। जिस जगह से ड्रेन निकालने की मैंने मांग की थी वहां से तो ड्रेन निकाली ही नहीं गई।

अब मैं एक बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगी। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सरकार की मौजूदा नीति के कारण हजारों-हजारों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आने वाली लिस्ट में आने से वंचित हो गए हैं। मैंने इस बारे में अधिकारियों से पूछताछ की तो वे कहने लगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की गाईड लाईन ही ऐसी है कि यदि किसी ने दो कमरे डाल रखे हैं तो वह भी गरीबी की रेखा के नीचे आने वाली लिस्ट में नहीं आयेंगे। इन गरीब लोगों ने किसी भले वक्त में अगर दो कमरे डाल लिए हों तो इसका मतलब यह नहीं कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। क्या वे दो 14.00 बजे कमरे उनको अब खाने को देंगे। उनकी रिपेयर के लिए भी तो पैसा चाहिए। अगर भारत सरकार की कोई शर्तें हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। हरियाणा को बिहार न समझा जाए। हरियाणा की सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनज़र रखा जाए और उसके मुताबिक ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं, उसको सही बनाया जाए। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो नॉर्म्ज़ हैं वे भारत सरकार के हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बदल सकती है। मैं दो चीजें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। अब एटथ फाईव इयर प्लॉन है। हरियाणा बनने के वक्त साढ़े तीन लाख फेमिलीज़ गरीबी रेखा से नीचे थीं और 1996 में जो इनका रिव्यू किया गया है उसके अनुसार अब हरियाणा के अन्दर 37 लाख पापुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। सरकार ने दो रंग के राशन कार्ड रखे हैं पीले राशन कार्ड बिलो-दि-पावरटी लाईन के लोगों के लिए हैं। मैं मध्यप्रदेश गया था वहां पर एक मजदूर को 15 रुपये डेली वेज़ मिलते हैं जब कि यहां पर 100 रुपये की मजदूरी मिलती है, इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि पर-कैपिटा इन्कम में हरियाणा पूरे भारत वर्ष में नम्बर दो पर था। इसलिए यह नॉर्म सरकार रख सकती है कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है उसको गरीबी रेखा से नीचे रख सकते हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही कि जिन लोगों के नाम गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए थे उनके नाम गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इनकी सरकार के वक्त में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का जो सर्वे हुआ था उसमें विधायक तक के नाम भी शामिल थे। (विघ्न एवं शोर) 50-50 एकड़ जमीन वालों के नाम भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों में शामिल किए हुए हैं जो इन्कम टैक्स देते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वह तो उदारीकरण था। (विघ्न) बहन जी, आप बोलिए। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर सर, यह बहुत ही गम्भीर तथा पूरे प्रदेश की समस्या है जो मैंने आपके सामने रखी है। गरीब लोगों में इस बात को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करे और कार्यवाही करे। स्पीकर सर, माननीय विकास मंत्री साहब कह रहे थे कि कागजों में हेरा-फेरी की गई तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसी बात की भी गई होगी तो प्रदेश के हित में और लोगों के हित में ही की गई होगी क्योंकि जिस आदमी ने राशन मोल ले कर खाना है आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए। जिसने राशन मोल ले कर खाना है और उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे नहीं है तो उसका कार्ड भी नहीं बनेगा और अगर राशन कार्ड भी नहीं बनेगा तो फिर यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर किस काम आएगी। (विघ्न)

पंचायत एवं विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बहन जी सत्य बात कह रही हैं, लेकिन ये हरियाणा के हितों की बात कह रही हैं या हरियाणा के हितों के खिलाफ बोल रही हैं। अगर नियम के मुताबिक चला जाए और केन्द्रीय सरकार के जो नियम हैं उसके मुताबिक चला जाए तो हरियाणा प्रदेश में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं मिलेगा।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मान चुकी हूं कि भारत सरकार की गाईड लाईन्ज हैं लेकिन भारत सरकार कोई ब्रिटिश की नहीं है। भारत सरकार भी हम ही लोगों की सरकार है। विशेष तौर पर आपकी पार्टी की सरकार है। मैं सरकार को जागृत करना चाहती हूं कि ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हजारों गरीब आदमियों का आप बे-मतलब में गला काट रहे हैं। मेहरबानी करके खुद को जगाओ और हरियाणा की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से उसका सर्वे करवाने की कृपा करें। मैं समाज कल्याण के बारे में कहना चाहूंगी। जो पुरानी योजनाएं थी वही योजनाएं आज भी चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बार मंत्री रहने का मौका मिला तब से ये योजनाएं चली हुई हैं। अभी मुझे एस०सी०, एस०टी० एंड बी०सी० कमेटी में इन स्कीमों को रिव्यू करने का मौका मिला। स्पीकर साहब, यह देखकर बड़ा दुख: हुआ कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों को पुस्तकों के लिए साल में 10 रुपए का अनुदान और अटैंडैंस के लिए महीने में 10 रुपए का वज़ीफा दिया जाता है। यह बहुत कम हैं। सरकार द्वारा इन सारी योजनाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। अभी आपने महात्मा गांधी जी की 50 वीं जयन्ती मनाई है और कल उसका समापन होना है। गांधी जी का विशेषतौर पर गरीब लोगों के लिए और हम सब लोगों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जब तक हर आंख का आंसु पोंछ नहीं देंगे तब तक हमारा यह संघर्ष चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, उनको 10-10 रुपए देने की राशि बहुत पहले से निश्चित कर रखी है, इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं विधवा पैंशन के बारे में भी बताना चाहूंगी कि विधवा पैंशन लेने के लिए जो फार्म विधवाओं को भरना पड़ता है वह बहुत ही जटिल है। उसको भरने के लिए बेचारी विधवा को इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए उस फार्म का सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। विधवाओं के बारे में केवल यही पता लगाया जाना चाहिए कि उनका कमाई का कोई साधन है या नहीं । उनकी पैंशन पूरे वर्ष चलती रहनी चाहिए। साथ ही एस०सी०, एस० टी० एंड बी०सी० के लोगों को आज कोई फायदा दिखाई देता है तो वह सरकारी नौकरी का है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी चूंकि मैं एस०सी० एस०टी० एंड बी०सी० कमेटी की मैम्बर हूं और हर विभाग की तरफ से हमें यह रिपोर्ट आई है कि एस०सी० एस०टी० एंड बी०सी०की पोस्टस भरी नहीं गई हैं। उसमें शार्टफाल है। मैं तो यह चाहती हूं कि इस जागृति के दिनों में उन लोगों को मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी पूना पैक्ट में डाक्टर अम्बेदकर के माध्यम से यह विश्वास दिया था उसको पूरा करने के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाएं और कहें कि हम रिजर्वड कैटेगरी की पोस्टस को भरेंगे और कैरिफार्वर्ड नहीं करेंगे। जबकि सैन्टर ने कहा

है कि अगर पोस्ट नहीं भरी जाती है तो वह कैरिफार्वर्ड होगी। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि सैन्टर की तरह से यहां पर भी वह सिस्टम होना चाहिए। अगर आप हरियाणा प्रदेश को सब से आगे बढाना चाहते हैं तो यहां पर पंजाब पैटर्न पर सर्विस में रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए। इसके अलावा मैं महिलाओं के लिए भी यहां पर वकालत करूंगी। जब हर क्षेत्र में उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है तो सर्विस में भी उनके लिए विशेष व्यवस्था करवाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज एक महिला के सामने अपने घर को चलाने में मुश्किल होती है और उसका पूरा सम्मान भी तभी होगा जब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी और परिवार की आमदनी में उसकी सांझेदारी होगी। आज जो यह महिलाओं को जलाकर मारने की घटनाएं हो रही हैं या दूसरी अन्य घटनाएं घट रही हैं, अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी और इन पर रोक लग जाएगी। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि आज कई स्कीमें हैं इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग की स्कीम है दूसरी और कई स्कीमें हैं उनको चालू रखना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कलानौर में एक आई०टी०आई० हमारी सरकार के समय में स्वीकृत की गई थी और उसकी आधारशिला रख दी गई थी। पिछले सदन में इस बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने उस बारे में प्वायंट आउट भी किया था। अब की बार तो स्पीकर साहब उसका नाम ही काट दिया गया है और किन्हीं दूसरी जगहों पर आई०टी०आईज० बनेंगी लेकिन कलानौर में नहीं बनेंगी। मैं आपके माध्यम से इन्टरट्रीयल ट्रेनिंग मिनिस्टर जी से अनुरोध करूंगी कि वे कलानौर की आई०टी०आई० पूरे क्षेत्र में एक ही है उसको बनवाने की कृपा करें।

इसके साथ ही मेरे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित वाटर वर्कस के बारे में कहना चाहूंगी। इसकी जो स्कीमें बताई हैं उसमें बहुत सारे गांवों के नाम बताए हैं यह बहुत अच्छी बात है। आज लोग वाटर वर्कस का पानी चाहते हैं। हर गांव वाले चाहते हैं कि हरेक के घर में पानी का कनैक्शन हो। यह स्कीम चालू हुई तो उसमें मेरे हल्के काहनौर को सिलैक्ट किया गया था। वहां पर वाटर वर्कस का बहुत काम हो गया था। उस पर सरकार का पैसा लगा हुआ है लेकिन 3 वर्ष से उसकी कोई सुध नहीं ली गई है। जबकि यह स्कीम सीनेटरी बोर्ड और दूसरी जगहों से कलीयर हो चुकी थी। कृपा करके उसको बनवाने की कृपा करें। वैसे हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों के काम हमारे से ज्यादा होंगे लेकिन आप इतना स्पष्ट पक्षपात हमारे साथ न करें कि जो चलते हुए काम हैं उनको भी रोक दिया जाए। लोगों को यह महसूस न हो कि हमने कांग्रेस का नुमायंदा चुन कर भेजा है इसलिए हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे सरकार की कोई नेकनामी नहीं होगी। (विघ्न) स्पीकर साहब, सम्बन्धित मंत्री बार-बार खड़े होते रहते हैं वे अब इस बात का जवाब दें कि कलानौर का आई०टी०आई० क्यों नहीं बना और काहनौर की वाटर सप्लाई की स्कीम क्यों पूरी नहीं हुई ? अब मंत्री जी इसका जवाब दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार "हरियाणा ग्रामीण विकास निधि" के अन्तर्गत स्कूलों की छतों को पूरा करवाने के लिए या हरिजन चौपालों को पूरा करवाने के लिए पैसा खर्च करेगी, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस बारे में सरकार से एक अनुरोध करूंगी कि आज चौपालों के नक्शों का यूज होने की बजाए मिसयूज हो रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले नक्शे की शर्त इसलिए रखी होगी कि कम से कम इतनी जगह तो इनकी बन जाए लेकिन अब आबादी बढ़ रही है और बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए यदि किसी जगह पर आप चौपाल बनाना चाहें तो उस नक्शे की शर्त ऐसी है कि आप यह काम कर नहीं सकते। वहां पर दिया हुआ अनुदान भी काम नहीं आता इसलिए मैं विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह इस नक्शे से लोगों को निजात दिलवाएं। यह तो भारत सरकार का काम नहीं है बल्कि इसको तो ये स्वयं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और

[श्रीमती करतार देवी]

कहना चाहूंगी। विकास की बातें चाहे वह जन स्वास्थ्य की हों या कोई और हों, वे तभी पूरी हो सकती हैं जब स्टेट में कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। अगर यहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई भी काम ठीक नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, आज ही सुबह एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने जो बताया था उससे ही जाहिर हो जाता है कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। हरियाणा के बारे में कभी चर्चा रहती थी कि कालका से लेकर शिमला तक आप चले जाओ आपको इन्कम टैक्स वाले तो मिल सकते हैं लेकिन चोर डैकत नहीं मिलेंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। आज अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। देखने में यह भी आ रहा है कि अधिकारी भी बदमाशों को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते। अगर कोई अधिकारी ऐसी हिम्मत करता भी है तो उल्टे उसको सरकार का कोपभाजन बनना पड़ता है। स्पीकर सर, अगर ऐसा होगा तो फिर कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? इसको ठीक करना बाद में किसी के बस की बात नहीं होगी और यह बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर भी अगर सरकार सोचती है कि कानून व्यवस्था ठीक है तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हमारा सरकार से यह निवेदन है कि आज प्रदेश में कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझ रहा है। विशेषकर कमजोर वर्गों में असुरक्षा की भावना पनप रही है। आज जब हम महामहीम राज्यपाल और मंत्रियों के बच्चों को उठाने की बात सुनते हैं तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? इसलिए सरकार को कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों ने इसी भावना के साथ आपको पदासीन किया था कि जैसे श्रीमति इंदिरा गांधी के समय में चौधरी बंसी लाल जी ने कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री के रूप में काफी विकास किया था वैसे ही वे अब भी विकास करेंगे लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज आप किस प्रधान मंत्री के आश्वासनों पर स्कीम्ज बनाते हैं वह पूरी नहीं हो रही हैं। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। पहले पंजाब में भी बाढ़ आयी थी और हरियाणा में भी बाढ़ आयी थी। पंजाब में अकाली सरकार भी उनके साथ है और आप भी उनके साथ हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से वहां पर और यहां पर एक सर्वेक्षण टीम बाढ़ के बाद आयी थी। वहां के लोगों को तो मुआवजा मिल गया परन्तु हरियाणा को आज तक भी मुआवजा नहीं मिला। यहां की सरकार को अभी भी इस बारे में प्रतीक्षा है कि केन्द्र सरकार इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो इस प्रदेश का भगवान ही रखवाला है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस तरफ ध्यान दें। मैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी का यह आश्वासन दोहराना चाहती हूं कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे बल्कि सरकार के जो रचनात्मक काम हैं उनके लिए हम सहयोग देंगे। परन्तु अगर ब्रूट मैजोरिटी के आधार आम जनता की भावनाओं की अनदेखी की जाएगी तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हर जगह पर सरकार की गलतियों को उजागर करें और लोगों को जागृत करें कि वह जल्दी से जल्दी आपसे छुटकारा पाएं, जय हिन्द।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौन्द) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ने के लिए उनकी मजबूरी थी या फिर सरकार ने जो लिखा उसे उन्होंने यहां पर पढ़ दिया। हमने विधान सभा में आने से पहले सोचा था कि विधान सभा में जो बात रखी जाती होगी सरकार उस पर पूरा ध्यान देती होगी। लेकिन यहां आकर ऐसा देखने को मिला कि यहां तो भाषण बाजी है। अगर यहां पर कोई बात रखी जाती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर 30 जनवरी

को उनकी पुण्य तिथि मनाई जा रही है। एक सच्चे महात्मा का नाम लिया गया तो हम भी यह उम्मीद करते थे कि यह सरकार इसी तरह से अच्छे काम करेगी। यहां तक कि देश के प्रधान मंत्री भी 30-जनवरी को उपवास रखने जा रहे हैं। यह बात उन्होंने ठीक दो दिन पहले कही है क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर इतनी मंहगाई हो जाएगी और लाखों आदमी महीने में कई-कई उपवास रखेंगे तू एक दिन रख लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज राजनीति के अंदर जो भेदभाव है जो फर्क है कि ये सरकार के हैं ये अपोजीशन के हैं। यह जो सारी बातें हैं यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे वह नौकरियों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो यह भेदभाव हमेशा हुआ है। पीछे पुलिस की भर्ती थी उसमें लाखों नौजवानों ने हिस्सा लिया था और मुख्य मंत्री जी कहा करते थे कि नौकरियां मैरिट के आधार पर मिलेंगी। हमें तो उसी दिन इनकी नियत पर शक होने लगा था जब इन्होंने कहा था कि किसी भी जिले में कोई भी कहीं भी भर्ती हो जाए और वही हुआ, भर्ती में इतनी धांधली हुई कि क्या कहें ? मैं तो जींद की मिसाल दे सकता हूं जींद में भर्ती हुई और सलैक्शन की लिस्ट लग गई। ड्यूटी हवलदार मोटरसाइकिल पर एक नौजवान के घर जाकर खबर देता है कि लिस्ट लग गई है और आपकी सलैक्शन हो गई है। उसके घर वाले खुश हो जाते हैं और मिठाई पार्टी में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। सात दिन बाद पता चलता है कि दूसरी लिस्ट लग गई है और उस लिस्ट में उस नौजवान का नाम नहीं होता है ऐसे में उसके घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने इतनी खुशी मनाई थी। इतनी बड़ी धांधली की इस सरकार से उम्मीद नहीं थी जो यह कहा करती थी कि नौकरियां मैरिट के आधार पर दी जाएंगी। मुख्य मंत्री जी सबके लिए सारे प्रदेश के लिए बराबर हैं हम यह नहीं चाहते थे कि सतबिन्द्र राणा के हल्के के लोगों को ही नौकरियां मिलें। वोट तो हमारे हल्के के लोगों के भी बी०जे०पी० और हविपा को मिले फिर नौकरियों में भेदभाव क्यों किया गया और भिवानी के लोगों का ही ध्यान क्यों रखा गया ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुज्जर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो नौकरियों में भेदभाव की बात कही है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी यहां बैठे हैं चौधरी बंसी लाल के राज में मैरिट के आधार पर नौकरी दी गई है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended upto 3.00 P.M.?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Time of the sitting is extended upto 3.00 P.M.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सब कांग्रेस के राज में हुआ करता था जब चौधरी भजनलाल जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी सारे हरियाणा के हिस्से की नौकरियों में से आधी नौकरियां आदमपुर हल्के के लोगों को देते थे। भेदभाव तो कांग्रेस के राज में होता था। इस राज में भेदभाव नहीं होता है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी बता सकते हैं कि 26 हजार नौकरियां आदमपुर हल्के के आदमियों को दी गई जोकि सारे हरियाणा के हिस्से की नौकरियों में से आधी थी। भेदभाव की बात तो यह है और यह रिकार्ड की बात है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)**

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं क्योंकि इनके हिस्से में तो 15 प्रतिशत आरक्षित सीटें आ रही थी। मेरे हल्के में वोट तो बी०जे०पी० और एच०वी०पी० को भी मिले थे लेकिन एक भी लड़के को नौकरी नहीं मिली। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जब इलैक्शन का समय आता है तो नौजवानों की बात की जाती है और बाद में नौजवानों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। जहां तक सिंचाई की बात है आज बारिश हुए चार-पांच महीने होने को हैं लेकिन मेरे हल्के में हजारों एकड़ भूमि में आज भी पानी खड़ा हुआ है। मुख्य मंत्री जी खुद मौके पर देख कर आये हैं और उन्होंने पानी की निकासी के बारे में वायदा भी दिया था लेकिन पता नहीं इस सरकार की बात को आज के अधिकारी क्यों नहीं मानते। सभी खेतों में आज पानी वैसा का वैसा खड़ा हुआ है जबकि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर पानी का निकास हो जायेगा। लाठर साहब, मंत्री जी बैठे हुये हैं इनके इलाके में भी खेतों में पानी की हालत ऐसी है। (विघ्न)

आवास राज्य मंत्री (श्री सतनारायण लाठर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई सतविन्द्र सिंह राणा को बताना चाहता हूं कि 1995 में भी बाढ़ आई थी और उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी थे। उस समय की सरकार ने किसी भी क्षेत्र के खेतों का पानी निकालने की कोशिश नहीं की लेकिन इस सरकार ने रात-दिन एक करके प्रशासन की सहायता से खेतों का पानी निकालकर एक-एक इंच भूमि में बुआई करवाई है। जहां तक मेरे भाई ने पुलिस भर्ती की बात कही है। जींद जिले में इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। भिवानी का कोई आदमी पुलिस में भर्ती नहीं किया गया सभी आदमी जींद जिले के ही भर्ती हुये हैं।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, खेतों का पानी लाठर साहब के हल्के में निकाल दिया होगा मेरे हल्के में तो नहीं निकाला है। क्या यह भेदभाव की बात नहीं है ?

श्री सतनारायण लाठर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसी गांव के साथ, किसी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। महम चौबीसी में 25 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेन बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है जबकि वहां से हलोदरा का विधायक है वह हमारी पार्टी का तो विधायक ही नहीं है।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन खेतों में पिछली फसल हुई नहीं और अगली फसल होने की कोई उम्मीद नहीं तो उन किसानों का बहुत बुरा हाल होगा। जो किसान सिर्फ खेती पर निर्भर हैं और उसके बेटे को नौकरी न मिले तो यह भेदभाव नहीं तो और क्या है ? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी निकालने की बात इसलिये कह रहा हूं कि खेतों मे पानी खड़ा है जिसकी वजह से पिछली फसल नहीं हुई, अगली फसल की उम्मीद नहीं और उससे आगे की फसल होने की भी उम्मीद नहीं। किसान खेती पर ही निर्भर रहता है क्योंकि उनके बेटों के पास नौकरी तो है नहीं। (विघ्न) . . . उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिये कहता हूं कि आज जो क्राइम बढ़ रहा है वह इसलिये बढ़ रहा है क्योंकि जिस किसान के खेत में कई-कई साल तक फसल नहीं होती वह भूखा मरता है तो भूखा मरता किसान क्या करेगा या तो वह लाठी उठाता है या पिस्तौल उठाता है और क्राईम करने पर मजबूर हो जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का यह मतलब है कि राजनीतिक शोषण की वजह से ही आज नौजवान दूसरी तरफ चल दिया है। यहां सदन में उस बात को बड़े सहज रूप में या मज़ाक में लेकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि चुनाव के दौरान हविपा-भाजपा की इस गठबंधन सरकार ने यह बात कही थी कि हम मैरिट के आधार पर

नौजवानों को नौकरी देंगे लेकिन यह सरकार नौकरियों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर पायी और न ही खेतों में नहरी पानी मुहैया कराने की कोई व्यवस्था कर पायी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कहीं तो खेतों में पानी खड़ा है और कहीं नहरों में पानी ही नहीं है। मेरे इलाके में गोगणिया माईनर की टेल पर नौ महीने से पानी नहीं पहुंचा है। इस बारे में लोग मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे, उसके बावजूद भी 8-9 महीने से उसकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उस नहर की टेल पर पानी इसलिये नहीं पहुंच रहा है क्योंकि उस हल्के से मैं विपक्ष का और नया एम०एल०ए० हूं तथा पहली बार चुन कर आया हूं। इसलिये इन्होंने यह सोचा है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर उस नहर की टेल पर पानी नहीं पहुंचा। यदि कोई ठाड्डा एम०एल०ए० हो तो ये उसका काम कर देंगे। (विघ्न) . . . उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि नौजवानों को बिना किसी भेद-भाव के नौकरी मिले। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। पहले तो हविपा-भाजपा सरकार ने शराब बन्दी पर जोर दिया और शराब बन्दी के नाम पर इस प्रदेश के अन्दर लाखों रुपये के टैक्स लगा दिये। (विघ्न) जब सरकार शराब बन्दी लागू करने में पूरी तरह से फेल हो गई तो आज बिजली की बात कहने लग गई। सरकार बिजली की दुहाई देती है लेकिन ढाई-पौने तीन साल हो गये, आज तक हरियाणा में एक भी बिजली का नया कनैक्शन ट्यूबवैल के लिये नहीं दिया गया। इस सरकार ने नया कनैक्शन देने की बजाय 14-15 हजार कनैक्शन काट दिये। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा दिख रहा है कि अगर ऐसे ही कनैक्शन कटते रहे तो बिजली तारों और खम्बों में ही रहेगी, घरों में और ट्यूबवैलों के लिये तो होगी ही नहीं। जो लोग ईमानदारी से बिजली के बिल भरते हैं, जिन्होंने कभी बिजली के बिल भरने में कोताही नहीं की उनको ट्यूबवैल्ज़ के लिये बिजली नहीं मिलती है। कुछ ऐसे आदमी हैं जो बिल नहीं भरते और वे 30-40 परसैंट होंगे लेकिन 50 परसैंट से अधिक लोग बिजली का बिल भरते हैं। एक्सीयन साहब यह कहते हैं कि जब तक 60-70 परसैंट लोग बिजली का बिल नहीं भरेंगे तब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर उन आदमियों का कसूर क्या है, जो बिजली का बिल तो भरते हैं लेकिन 30-40 प्रतिशत लोगों के बिल न भरने की वजह से उन को भी बिजली नहीं मिलती है। इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग बिजली के बिल नहीं भरते हैं, उनके तो चाहे कनैक्शंज़ भी काट दिए जाएं परन्तु जो लोग नियमित रूप से बिजली के बिल अदा करते हैं, उनको तो बिजली अवश्य मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोगों के साथ बहुत भारी भेदभाव किया जाएगा। (विघ्न) सरकार में बैठे हुए इन साथियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनको तो सिर्फ झंडी वाली कार ही दिखाई देती है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज एक-एक आदमी इस बात का जवाब मांग रहा है। इसके साथ साथ गरीबी रेखा के बारे में मेरे से पहले चर्चा की गई थी कि हरियाणा में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवनयापन करता हो तथा सभी के पास पक्के मकान हैं तथा उन्होंने वैसे ही कागजों में अपने मकान कच्चे दिखा रखे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इस संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ है, उस में मुंह देख कर टीका लगाने का काम किया गया है। हम यह नहीं कहते हैं कि जो वास्तव में गरीब आदमी है, उसको फायदा नहीं मिले, उसको तो फायदा मिलना ही चाहिए। मगर पीछे जो गलतियां की गई हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तो सभी गरीब हो जाएंगे क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई ही इतनी कर दी है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जो वास्तव में गरीब आदमी हैं और सर्वेक्षण के दौरान वे रह गए हैं, उनका नाम अवश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए दुबारा सर्वेक्षण ही क्यों न कराना पड़े। (विघ्न)

पंचायत एवं विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि कहीं-कहीं इस सर्वेक्षण में गलतियां हो सकती हैं। जो नॉर्मज़ केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए हैं, उन के अनुसार यदि सर्वेक्षण किया जाए तो बहुत कम लोग ही इस सूची में आ पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं कि इस गरीबी रेखा की सूची में अनुसूचित जाति व पिछड़ी श्रेणी के लोगों को शामिल किया जाए फिर भी माननीय सदस्य को यदि इस बारे में कोई शिकायत है तो वे लिखकर के नाम हमें दे दें, वह गरीबी रेखा की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे इस बारे में हम ने बाकायदा ए०डी०सीज़० को आदेश दिए हुए हैं कि बड़े ध्यानपूर्वक यह सूची बनवाई जाए लेकिन फिर भी कोई गलती रह सकती है। लेकिन जहां तक सर्वेक्षण दुबारा से करवाने की बात है, इस में समय बहुत लगता है, जिसके लिए बाकायदा नॉटिफिकेशन होती है, इसलिए इसको दुबारा नहीं करवाया जा सकता है। हां, अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको अवश्य ठीक कर दिया जाएगा।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वे गरीबी रेखा की सूची बनाने में अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, उसको ठीक करवा देंगे। सौभाग्य से विकास मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज देहात के अन्दर गलियों व नालियों की हालत इतनी बुरी है कि उन पर चलना संभव नहीं होता है। पिछले अढाई साल के अर्से में गांव की गलियों में एक ईंट भी नहीं लगाई गई है। (विघ्न) मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि गांवों के अंदर पानी की निकासी कहीं नहीं है। (विघ्न) मैं अपने हल्के में ले जाकर इनको स्थिति दिखा सकता हूं। (विघ्न) 22 लाख रुपए पाई में दे दो या कहीं और दे दो। (विघ्न) गाजीद हल्के में पाई हल्के की अपेक्षा गांव ज्यादा हैं। (विघ्न) आप तो अलेवा में गए थे तथा वहां पर 29 लाख रुपए देने की घोषणा करके आए थे लेकिन वहां पर आज तक एक पैसा भी नहीं पहुंचा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोक सभा सदस्य को केन्द्रीय सरकार की तरफ से हल्के के विकास के नाम पर पहले जो एक करोड़ रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, गजनीति तो मैंबर ऑफ पार्लियामैंट भी करते हैं और हम एम०एल०एज़० भी करते हैं। अगर सरकार यह चाहती है कि किसी भी हल्के में भेदभाव न हो तो जो 40 लाख रुपये की ग्रांट सदस्यों को अपने हल्कों के विकास के लिए पिछली सरकार में मिलती थी वह फिर से चालू कर दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि यहां से मंत्री जी पैसा भेज देते हैं लेकिन वह पैसा कैथल से आगे नहीं पहुंचता वहीं तक पहुंचता है जिसकी वजह से पंचायतें अपना काम नहीं कर पा रही हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह 40 लाख रुपये की ग्रांट दोबारा से रीलीज की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ला एंड आर्डर की स्थिति है वह आज हरियाणा प्रदेश में बहुत खराब है। कहीं पर मंत्रियों की गाड़ियां लूटी जाती हैं, कहीं पर मंत्री के पोते को उठा लिया जाता है और कहीं पर मंत्री जी का पैट्रोल पम्प लूट लिया जाता है। जो लोग सरकार को चलाते हैं उनके साथ ऐसा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम यू०पी० और बिहार की मिसाल देते थे कि वहां पर ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। हमारे प्रदेश हरियाणा में बहुत अच्छी है लेकिन अब हम भी उनके बराबर हो गये हैं। हमारे यहां पर भी ला एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक परिवहन की बात है, इस सरकार ने जिन प्राईवेट बसों को प्रमिटस दे रखे हैं वे भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। हरियाणा प्रदेश में सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है। पता ही नहीं लगता कि कहां पर सड़क है और कहां पर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। पता नहीं चलता कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है। उपाध्यक्ष महोदय, हम

इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि अढ़ाई साल में तो इस सरकार ने कुछ किया नहीं और राज्यपाल महोदय से इतना बड़ा अभिभाषण पढ़वा लिया लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सरकार अपने आगे के कार्यकाल में कुछ अच्छे काम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की दो-चार बातें बताना चाहता हूं। एक बार मैंने पहले भी कहा था कि राजौंद 30-35 हजार की आबादी वाला कस्बा है वहां के किसान अपनी फसल बेचने के लिए कैथल जाते हैं इसलिए राजौंद में एक मण्डी बनाई जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई का भी मेरे हल्के में बहुत बुरा हाल है। आज से 15-20 साल पहले वहां पर एक वाटर सप्लाई बनी थी। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि उस वाटर सप्लाई स्कीम के पानी से आधे से ज्यादा गांव बंचित हैं। जिस नहर से उस वाटर सप्लाई स्कीम में पानी आता है उसमें पशु भी पानी पीते हैं, लोग कपड़े धोते हैं इसलिए वह पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर एक और वाटर सप्लाई स्कीम बनानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो काम इस सरकार ने किये हैं उसके लिए हम इस सरकार की तारीफ करते हैं। इस सरकार ने मेरे हल्के में कई स्कूलों को अपग्रेड तो कर दिया लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं हैं। मेरे हल्के में पीपड़ा गांव है जहां पर नई डिस्पैंसरी तो बना दी गई है लेकिन पिछले दो-अढ़ाई साल से वहां पर कोई भी डाक्टर नहीं है। राजौंद की बात तो मैंने कहनी ही छोड़ दी वहां पर चार डाक्टरों की पोस्टें हैं लेकिन वहां एक भी नहीं है। इस बारे में मैं कई बार मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल चुका हूं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से पर्सनली भी मिला लेकिन आज तक वहां पर एक भी डाक्टर नहीं गया है जबकि वहां पर चार डाक्टर होने चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस अभिभाषण में जो कुछ दर्शाया गया है उसके अनुरूप कुछ काम नहीं होता है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली) : डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, लोकतंत्र की परम्परा के अनुरूप राज्यपाल महोदय ने कल हम सब के बीच में अपना अभिभाषण पढ़ा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर सैक्शन 17 जोकि हमने स्वयं बनाई है जिसके अन्दर कहा गया है कि राज्यपाल के अभिभाषण का कोई सदस्य विरोध नहीं करेगा अगर वह अड़चन विरोधी पक्ष के सदस्यों के सामने नहीं होती तो मैं समझता हूं कल ही इस अभिभाषण के विरोध में विपक्ष के सारे सदस्य वाक आउट करते। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के अन्दर पिछले पौने तीन साल से इस हरियाणा भाजपा गठबंधन सरकार की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था से हरियाणा प्रदेश का किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी यानी सभी वर्ग के लोग नाखुश हैं, असन्तुष्ट हैं। इस सरकार की कारगुजारी आए दिन अखबारों के माध्यम से देखने को मिलती है कि आज फलां जगह प्रदर्शन हुए आज फलां जगह हत्या हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले 9 महीने के दौरान जितनी हत्याएं, जितने अपहरण, जितने बलात्कार हरियाणा प्रदेश के अन्दर हुए हैं मैं समझता हूं कि वह अपने आप में एक रिकार्ड है। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश खुशहाली और अमन चैन के बारे में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि जो दिल्ली के नजदीक हरियाणा प्रदेश का एरिया है चाहे वह गुड़गांव हो चाहे वह फरीदाबाद हो चाहे झज्जर का इलाका हो और चाहे सोनीपत का इलाका हो उन इलाकों में उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज्यादा खराब माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्थिति हरियाणा प्रदेश की बनती जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की यह हालत हो चुकी है कि गुड़गांव के अन्दर दाउद

[राव नरेन्द्र सिंह]
इब्राहीम सरगना माफिया के सदस्य सभ्य परिवारों के लोगों को टैलीफोन करते हैं कि इतने रुपए ले कर फलां जगह पर आओ अगर नहीं आए तो हम आपको दोबारा टैलीफोन करेंगे। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह स्थिति बन चुकी है। हरियाणा प्रदेश के लोग कभी अमनचैन की नींद सोया करते थे, पूरे प्रदेश में जो भाईचारे और शांति का वातावरण था आज वह भाईचारा और शांति का वातावरण इस प्रदेश में बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, एशियाड गेम्ज के दौरान की बात है। आपको याद होगा उस समय प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया था कि एशियाड गेम्ज में अगर कोई व्यक्ति विघ्न डालना चाहेगा, चाहे वह पंजाब से हो कर आए चाहे वह किसी दूसरे प्रदेश से हो कर आए उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वह भी एक सरकार थी जिसने यह फैसला लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आज यह सरकार आपके सामने चल रही है। आजकल हमें हर रोज अखबारों में देखने को मिलता है कि फलां जगह यह काण्ड हो गया फलां जगह उसकी हत्या हो गई। पिछले दिनों हमें अखबारों में पढ़ने को मिला कि एक बेबी किल्लर ने लगातार 13-14 अबोध बालिकाओं का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्याएं कर दी। लेकिन आज तक यह नहीं पता चला कि असली हत्यारा कौन है। पहले बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति पकड़ा गया। बाद में पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस काण्ड में एक दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। वह कहने लगा कि मैंने ये हत्याएं की हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज तक असली हत्यारा पकड़ा नहीं गया। आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। आज के दिन इस सरकार के अन्दर मौजूदा विधायक, मंत्री या जो दूसरे मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे आराम से कहीं पर अपना जलसा कर सकें। इन लोगों को रागनी वालों को बुला करके भीड़ इकट्ठी करवानी पड़ती है। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर बिजली व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जिक्र किया गया है और कहा गया है कि बिजली का सुधारीकरण करके सरकार प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देगी। इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक का राज्यपाल महोदय का यह तीसरा अभिभाषण है। पिछले तीन सालों से एक ही चीज पढ़ने को मिलती है कि प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय सच्चाई की बात यह है कि हरियाणा के लोगों को 5 से 7 घंटे से अधिक बिजली नहीं दी जा रही। इस प्रदेश का किसान बिजली के लिए तरस रहा है। खासकर दक्षिण हरियाणा के लोग बिजली न मिलने के कारण बहुत दुःखी है क्योंकि वहां पर सारा दारोमदार खेती पर ही है। वहां पर कोई उद्योग आदि नहीं है और न ही कोई दूसरा व्यापार है जिससे वे अपना अच्छा जीवन बसर कर सके। वहां के किसानों को 6-7 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है और जो बिजली मिल रही है वह भी कम वोल्टेज के कारण उसे लोग यूज नहीं कर पाते। कम वोल्टेज के कारण ट्रांसफारमर भी जल जाते हैं। अधिकारी भी जब तक उनको सुविधा शुल्क नहीं मिलता तब तक ट्रांसफारमर नहीं बदलते। जले हुए ट्रांसफारमरों के बारे में अब सरकार ने एक नीति यह बना दी कि जब तक लोग बिजली के बकाया बिलों का भुगतान नहीं करेंगे तब तक उसे बदला नहीं जायेगा। ऐसी पालिसी किसान विरोधी है क्योंकि जो किसान समय पर बिजली के बिल दे रहे हैं उनके लिए भी ट्रांसफारमर न बदला जाये यह अच्छी बात नहीं है। सरकार यह कर सकती है कि जिन लोगों ने बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं उनके कनैक्शन काट दें न कि ट्रांसफारमर ही न बदलें।

उपाध्यक्ष महोदय ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शन देने की बात यहां पर नहीं की गई। जहां तक मेरी जानकारी है 31 मार्च 1990 के बाद सरकार ने ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शन जारी नहीं किए। न ही मौजूदा अभिभाषण में इस बात का कोई जिकर किया गया कि इतने ट्यूबवैल्ज के नए कनैक्शन जारी किए जाएंगे। सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन जारी करने चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। जिस दिन से यह सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक यह कहती रही है कि हम नहरों की टेल एण्ड तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक सरकार टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचा पायी है। इसी तरह से एस०वाई०एल० कैनाल का पानी दक्षिण हरियाणा को आज तक नहीं मिल पाया है। एस०वाई०एल० कैनाल का पानी दक्षिण हरियाणा के लिए लाईफ लाईन का सवाल है। इसके बारे में पिछले अभिभाषण में जिकर किया गया था कि सरकार इस बारे में निरंतर प्रयास कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में बी०जे०पी० की सरकार थी, यहां पर एच०वी०पी० व बी०जे०पी० की सरकार है। पंजाब में अकालियों व बी०जे०पी० की सरकार है दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है लेकिन फिर भी इसको पूरा नहीं करवा पायी। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।**) मेरी सरकार से मांग है कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस तरफ कदम उठाते हुए प्रधान मंत्री से बात करके इसे पूरा करवाने की दिशा में कदम उठाये ताकि दक्षिण हरियाणा के लोगों को पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं सरकार का ध्यान नहरी पानी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह पानी हमें महीने में केवल 10 दिन मिलता है। मैं चाहूंगा कि हमारा यह हिस्सा भी बढ़ाया जाये ताकि पीने का पूरा पानी उस एरिया को मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज प्रदेश के तमाम अस्पतालों की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। स्पीकर सर, आप जब भी किसी शहर में जाएं तो मैं आग्रह करूंगा कि वहां के अस्पताल में पर्सनली जाने का कष्ट करें। मेरे नारनौल में सिविल अस्पताल के अन्दर सबसे ऊपर मरीजों का जो वार्ड था वहां पर ताला लग चुका है और पीछे जो ओल्ड वार्ड है उसमें महिला वार्ड पर ताला लगा हुआ है। वहां पर पूरे डॉक्टर्ज उपलब्ध नहीं हैं और जो उपलब्ध भी हैं वे पूरी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। वे अपनी ड्यूटी के अन्दर कोताही बरतते हैं जिससे मजबूर हो कर लोगों को प्राईवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ रही है। अस्पताल में केवल वही व्यक्ति जाता है जिसका केस पुलिस से सम्बन्धित हो। आम आदमी आज अस्पताल से दूर हो गया है। अस्पतालों में दवाई नाम की कोई चीज़ सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है इसलिए आम आदमी के पास प्राईवेट अस्पतालों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लोगों को अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक एक्स-रे मशीन का सवाल है, आमतौर पर अस्पतालों में जैनरेटर खराब पाए जाते हैं इसलिए जो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सी०एम०ओ० हो उसकी इस बारे में ड्यूटी लगाई जाए और सरकार की तरफ से विशेष अनुदान दिया जाए ताकि एक्स-रे मशीन, अल्ट्रा साउंड और दूसरी मशीनें ठीक हो सकें और जैनरेटर हर हालत में उपलब्ध करवाया जाए। जहां तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, अस्पतालों के अन्दर कोई भी काम पैसा दिए बगैर नहीं होता है इसके लिए सरकार को देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में शिक्षा मन्त्री जी का इस सदन में यह आश्वासन रहा है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्दी भर दिया जाएगा और उसके

[राव नरेन्द्र सिंह]

बाद फिर डेट बढ़ा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, जनवरी का महीना खत्म होने जा रहा है और मार्च-अप्रैल के बीच में इम्तिहान हैं लेकिन हरियाणा के अन्दर बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अध्यापक नहीं हैं। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर लैक्चरार नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि अध्यापकों और लैक्चरारों के पदों को भरने के लिए कदम उठाएं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं परिवहन की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस समय प्रदेश के अन्दर परिवहन व्यवस्था इतनी जर्जर और बुरी हालत में है, जहां तक मैं समझता हूं, इतनी बुरी हालत में कभी नहीं रही होगी। स्पीकर सर, आप स्वयं एक गांव से सम्बन्ध रखते हैं और आपको मालूम ही है कि गरीब आदमी से ले कर मध्यम वर्ग तक का हर आदमी बसों में सफर करता है लेकिन जब उनको कहीं आने-जाने के लिए बस नहीं मिलेगी या बसों की व्यवस्था खराब होगी तो वह अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकेगा। सरकार को चाहिए कि परिवहन व्यवस्था को ठीक करे। आज हरियाणा रोडवेज घाटे में चल रही है इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे वह लाभ में चल सके। पहले दूरदराज के प्रान्तों के लोग भी हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करते थे तथा हरियाणा रोडवेज देश भर में नम्बर एक पर चल रही थी लेकिन आज हरियाणा रोडवेज घाटे में चल रही है। इसके लिए ऐसे प्रयास करने चाहिएं कि यह लाभ में आ सके। स्पीकर सर, 125 कि०मी० तक रूट परमिट वाली बात मुख्य मन्त्री जी की तरफ से लगभग तीन साल से दोहराई जा रही है कि शीघ्र ही बेरोजगार युवकों को बसों के रूट परमिट इशू करेंगे लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक वह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। केवल कागजों में ही सीमित है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी बता रहे थे कि डीजल के रेट्स एक रुपया प्रति लीटर घटा दिए गए हैं। यह बात उसी समय क्लीयर भी हो गई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो यहां पर रेट्स बढ़ जाते हैं और अगर वहां पर रेट्स घटते हैं तो यहां पर भी रेट्स में कमी आ जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि अगर डीजल का रेट एक रुपया कम हुआ है तो हरियाणा के आम आदमी के लिए बसों का भाड़ा कुछ कम किया जाना चाहिए ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि डीजल के रेट्स कम हुए हैं। बसों का भाड़ा कई बार बढ़ाया गया है इसलिए सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बसों का भाड़ा कुछ कम हो। विकास के मामले में इस सरकार के पिछले पौने तीन साल में प्रदेश के अन्दर कोई विकास का कार्य कहीं नहीं हो पा रहा है। (विघ्न) सरकार को चाहिए कि हर हल्के के अन्दर विकास कार्य किए जाएं। विपक्षी विधायकों के हल्कों के अन्दर भी डिवैल्पमैंट के कार्य होने चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरे प्रदेश के अन्दर विकास कार्य पूरी नेक नीयती के साथ होने चाहिएं। स्पीकर सर, जहां तक एम०एल०ए० लोकल ऐरिया डिवैल्पमैंट स्कीम का सवाल है, आप इस बारे में अच्छी तरह से पता कर लीजिए कि राजस्थान के अन्दर ऐसी स्कीम लागू है। पिछले दिनों मैं दिल्ली के एक विधायक से व्यक्तिगत रूप से मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि पहले एक करोड़ रुपया दिल्ली के विधायकों को विकास के लिए मिलता था लेकिन अभी उन्होंने सैशन के दौरान दो करोड़ की व्यवस्था हर विधायक के लिए करवाई है। अगर यह बात सत्य है तो मैं समझता हूं कि एक करोड़ का तो हमारा भी हक बनता है इसलिए हरियाणा के लोगों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए अतः सरकार एम०एल०ए० लोकल ऐरिया डिवैल्पमैंट स्कीम हर विधायक को उपलब्ध करवाए। स्पीकर साहब, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और कॉलेज में लैक्चरार रहे हैं। (विघ्न) मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैश्य कॉलेज, भिवानी के अन्दर पिछले 13 और 15 जनवरी के दिन वहां के प्रिंसिपल डा० अमीं लाल यादव जो कि रिटायर्ड डिप्टी डायरैक्टर एजुकेशन तथा

ओ०एस०डी० रहे हैं, पर वहां के कुछ स्टुडैंट्स और बाहर के व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। स्पीकर सर, यह बात बहुत शर्मनाक तथा खेदजनक है। स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आज तक एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एडवांस में एस०डी०ओ०, एस०एच०ओ० और दूसरे बड़े अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया था कि मुझ पर हमला हो सकता है और मेरी जान जाने का खतरा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी सेफ्टी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। अब उन्होंने एज ए प्रोटैस्ट कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी कर्मचारी है या और कोई है, अगर कोई ऐसी शिकायत करता है तो उसको पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 1st February, 1999.

*14.56 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 1st February, 1999.)

30827–H.V.S.–H.G.P. Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh